चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

बाग़ी पलट सकते हैं बाज़ी

पेज-3

मुख्यधारा में कैसे आएं मुसलमान

पेज-4

आदिवासी आज भी ग़ुलाम हैं

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 18 अक्टूबर-24 अक्टूबर 2010

कश्मीर में

जनता जीती राजनीति हारी

कश्मीर में अमन लौट रहा है. लेकिन इस बदलती फ़िज़ा के लिए सियासी लोगों को नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम को शुक्रिया कहना चाहिए. यह कश्मीर के लोगों का ही जज़्बा था कि अपने बच्चों का मुस्तक़बिल बिगड़ता देख अमन की वापसी के लिए सड़कों पर आ गए. नतीजतन, सियासतदानों को अपना रुख़ बदलना पड़ा. बंद का समर्थन करने वाले संगठन और नेताओं को पीछे हटना पड़ा. एक बार फिर साबित हो गया कि लोकतंत्र की असली ताक़त जनता ही है. *श्रीनगर से डॉ. फरहा* की रिपोर्ट :

कश्मीर की वादियों में बंदूक़ों की आवाज़ थम गई है. नारेबाज़ी अब सुनाई नहीं देती. कोई पत्थर फेंकने वाला सड़क पर नज़र नहीं आ रहा है. पुलिस रिहायशी इलाक़ों से अपनी चौकियां हटा रही है. हुर्रियत का रुख़ भी सामान्य हो गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात जो तमाम बैठकों से निकल कर आई, वह सरकार की तरफ़ से ही संभव हुई. मरने वालों के परिवारजनों को मुआवज़ा देने की घोषणा हुई, मुआवज़ा भी पहले से ज़्यादा तय किया गया है. इसके अलावा उमर साहब ने दिल को छू लेने वाला शोक संदेश दिया है. उन्होंने पिछले दिनों जितने भी लोग मारे गए, उन्हें शहीद क़रार दिया है और यह भी कहा कि मेरे दिल के टुकड़े हो गए हैं, मेरे कंधे पर बंदूक़ है, लेकिन ट्रिगर किसी और के हाथ में है. यूं कहें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नैतिक ज़िम्मेदारी ले ली है. कश्मीर की जनता में इसका बहुत प्रभाव हुआ है. कुछ दिनों पहले तक जिस मुख्यमंत्री को लोग कोस रहे थे, वह अचानक उनके हमदर्द बनकर उभरे हैं. जहां तक बात पीडीपी की है तो वह इस वजह से बहिष्कार कर रही है कि जितने भी चिन्हित गनमैन हैं, जिनकी गोलियों से लोगों की जान गई है, उनके ख़िलाफ़ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे. सरकार ने भी अपनी तरफ़ से कार्रवाई तेज़ कर दी है. कई पुलिसवालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, कुछ थानेदारों को निलंबित कर दिया गया, कई चार्जशीट दाखिल हुई हैं, कुछ के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है. कश्मीर के हालात बेहतर होने की वजह से सरकार को राहत मिली है, क्योंकि पुलिस के हाथों लोगों की मौत का सिलसिला थम गया है. हालांकि रोज़ कर्फ्यू रहता है और रोज़ शाम को छूट भी मिल रही है. अच्छी बात यह है कि कर्फ्यू में ढील के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होती, सब शांत रहता है. सरकार भी अपनी तरफ़ से हरसंभव प्रयास कर रही है, ताकि लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो जाए. उन परिवारों, जिनके लड़के या अन्य सदस्य मारे गए हैं, को सरकार मुआवज़ा देगी. दूसरी ओर सरकार शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रयास कर रही है.

यह एक बदलाव है, जो कश्मीर में देखने को मिला है. इससे यही लगता है कि सरकार भी चाह रही है कि शांति बहाल हो, ताकि जनजीवन सामान्य हो जाए. जैसे कि शाम को जब ढील दी जाती है तो उस दौरान एकदम से सब कुछ सामान्य हो जाता है. बाज़ार, ट्रांसपोर्ट और माहौल यानी सब कुछ सामान्य. वैसे आहिस्ता-आहिस्ता लोग ख़ुद ही हड़ताल की कॉल को तोड़ रहे हैं, चोरी-छुपे दुकानें भी खोल रहे हैं. अच्छी बात यह है कि कर्फ्यू के बावजूद अभिभावक ज़ोख़िम लेकर बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं और अपने निजी वाहन भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पथराव वग़ैरह की घटनाएं ख़त्म हो गई हैं. लोग किसी भी क़ीमत पर अमन चाहते हैं. वे शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. कर्फ्यू में जितने भी घंटे की ढील दी जाती है, उस दौरान सब कुछ सामान्य हो जाता है. कुछ दिनों पहले तक कर्फ्यू में ढील के दौरान भी लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन स्कूल-कॉलेजों की परीक्षाओं का वक़्त नजदीक आते ही हालात सुधर गए. इस वजह से सबको बहुत फ़ायदा हुआ. समाज के एक बड़े हिस्से ने हड़ताल से खुद को जोड़ना छोड़ दिया है. ये वही लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले दिनों हड़ताल की वजह से ये अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे थे. ये वही अभिभावक हैं, जो हड़ताल को छुट्टियों की तरह मना रहे थे. लेकिन जब अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ख्याल आया तो ये एक झटके में बंद, हड़ताल और कर्फ्यू के विरोध में खड़े हो गए.

इस वक़्त तीनों पक्षों ने यह तय किया है कि कोई भी संस्था-एजेंसी इसमें व्यवधान न पहुंचाए. हुर्रियत सरकार के कर्फ्यू पर टिप्पणी नहीं कर रही है और सरकार भी हुर्रियत के कैलेंडर पर ज़्यादा छींटाकशी नहीं कर रही है तथा आम लोग दोनों ही चीजों का फ़ायदा उठा रहे हैं. वे सरकार और हुर्रियत यानी दोनों की तरफ़ से दी जाने वाली राहतों का लाभ उठा रहे हैं. इससे साफ तौर पर ज़ाहिर है कि आम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हालात ठंडे हो जाएं और दोनों ही पक्ष तटस्थ हो जाएं. वहीं सरकार ने कर्फ्यू तो जारी रखा है, लेकिन बड़ा नरम सा कर्फ्यू. कोई बयानबाज़ी नहीं कर रहा है, गिरफ़्तारियां नहीं हो रही हैं, पुलिस ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, तबादले रोक दिए गए हैं और किसी भी तरह लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है. सरकार के साथ साथ हुर्रियत भी वक़्त काटना चाहती है, क्योंकि जाड़े के मौसम में घाटी बाकी इलाक़ों से कट जाती है. हुर्रियत के लिए भी इस बार का मामला कुछ ज़्यादा ही खिंच गया है. उसके नेता बयानबाज़ी से बच रहे हैं, वे भी अब मामले को ठंडा करने में लगे हैं. हुर्रियत समझ गई है कि इस वक़्त समाज की मांग कुछ और है. लोगों का जो मूड है, उससे यही लगता है कि किसी भी एक हरकत से लोग नाराज़ हो सकते हैं.

कश्मीर में शांति बहाली के पीछे किसी सरकार, हुर्रियत या फिर दिल्ली से गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की कोई भूमिका नहीं है. यह स्थानीय लोगों का जज़्बा था, उनकी अमन पसंदगी थी. अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ता देख वे शांति बहाल करने सड़कों पर आ गए. पहले एक निकला, फिर दूसरा और फिर तो हुजूम निकल पड़ा. हर जुबान पर बस एक ही बात थी कि बस, अब बहुत हो गया. चार महीने से बंद, कर्फ्यू, हड़ताल और हिंसा झेल रही जनता इस बात से हलकान थी कि अगर यह सब चलता रहा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा. स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं होने का वक़्त आ गया, अभिभावकों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया और उसने कहा कि बच्चों के इम्तिहान होने दीजिए. कुछ भी हो जाए, आप अपनी लड़ाई अक्टूबर के बाद छेड़िए, लेकिन अभी बच्चों की परीक्षाएं होने दीजिए. परीक्षाएं वरदान साबित हो गईं. हुर्रियत ने स्कूल बहिष्कार किया था कि आप अपने बच्चों को अगर भेजेंगे तो अपने ज़ोखिम पर भेजेंगे. इससे अभिभावक डर गए कि अगर इस वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकीं तो बच्चों का काफी नुक़सान होगा. इसीलिए दिल्ली से जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया तो लोगों ने यही कहा कि आपको जो कुछ करना है कर लें, शांति के लिए जो भी प्रयास करने हैं कर लें, लेकिन कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था को इस हंगामे से दूर रखा जाए. इसके अलावा स्कूलों में ताले लगने के ख़िलाफ़

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुख्यमंत्री अब धरती पुत्रों को प्रोत्साहित करने की अपनी इस नीति का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की रणनीति बना रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

तबादला और इस्तीफ़ा

कैरियर के बीच में नौकरी छोड़ देना आईएएस अधिकारियों के लिए कोई नई बात नहीं है. हाल के सालों में कई अधिकारी निजी क्षेत्र के मोहपाश में बंधकर सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं. लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने बार–बार तबादलों से तंग आकर अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया. 1982 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के राजू शर्मा, जो फ़िलहाल राज्य राजस्व बोर्ड में हैं, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है. बताया जा रहा है कि पिछले दो महीनों के अंदर शर्मा का तीन बार तबादला किया गया और इसी से परेशान होकर उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया. सूत्र बताते हैं कि शर्मा के इन बार–बार के तबादलों के पीछे राजनीतिज्ञों का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. उच्च शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव रहते पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित एक बिल पर शर्मा अपने मंत्री राकेश धर त्रिपाठी से भिड़ गए थे. इसके ठीक बाद उन्हें राजस्व बोर्ड में भेज दिया गया. फिर, शर्मा नौकरशाहों के उस ग्रुप में भी शामिल थे, जिसने राज्य में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की पहचान करने का बहुप्रचारित अभियान चलाया था. फ़िलहाल शर्मा सरकार द्वारा अपना इस्तीफ़ा स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सेंट स्टीफेंस के उनके पुराने साथी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. इस कॉलेज के छात्र रहे कई मौजूदा और सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को पत्र लिखा है और उनके हस्तक्षेप की मांग की है. अब यह देखना बाक़ी है कि इसका कोई असर पड़ता है या नहीं.

नौकरशाही और राजनीति

राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपने राजनीतिक विरोधियों के मुक़ाबले बढ़त की हालत में ला दिया है. कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने अगले पांच सालों के लिए 15 आईएएस अधिकारियों की मांग की थी. लेकिन कैडर रिव्यू 2012 में होना है और ऐसा लगता है कि राज्य को अभी नौकरशाहों की कमी झेलनी ही पड़ेगी. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए राज्य कैडर के अधिकारियों को कलेक्टर के पदों पर प्रोन्नत करना शुरू कर दिया है, जो आम तौर पर आईएएस अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होती है. महाराष्ट्र में पहचान की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है और चव्हाण ने नौकरशाही में ताज़ा फेरबदल में इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि प्रोन्नति पाने वाले अधिकतर अधिकारी राज्य कैडर के ही हों. मुख्यमंत्री अब धरती पुत्रों को प्रोत्साहित करने की अपनी इस नीति का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की रणनीति बना रहे हैं. बहरहाल, चव्हाण के इस क़दम से राज्य कैडर के अधिकारियों और मराठी मानुस के बीच उनकी लोकप्रियता तो बढ़ सकती है, लेकिन राज्य में आईएएस अधिकारियों की लॉबी का समर्थन उन्हें खोना भी पड़ सकता है.

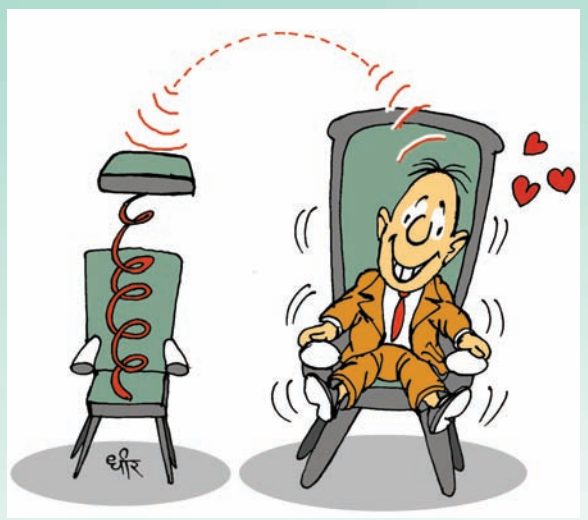

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

1989 बैच के आईएएस करें इंतज़ार

यह घाव पर नमक छिड़कने के जैसा ही है. 1989 बैच के आईएएस अधिकारियों की सूची में शामिल करने के मसले पर और देरी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई नामों पर अभी विचार चल ही रहा है. कम से कम इस बैच के 22 अधिकारियों को संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष स्तर के लिए चयनित किया गया है. स्पष्ट तौर पर, इस देरी से सब निराश हैं.

सुंदराजन संयुक्त सचिव बन सकती हैं

1982 बैच और केरल कैडर की आईएएस अधिकारी अरुणा सुंदराजन शीघ्र ही भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रुप में ज्वाइन कर सकती हैं. वह हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलीविएशन मंत्रालय में यह पदभार संभालेंगी. यह पद नवसृजित है.

विवेक, चंडीगढ़ (यूआईएआई) के नए एडीजी

1993 बैच के आईटीएस अधिकारी विवेक कुमार चंडीगढ़ (यूआईएआई) के नए एडीजी के तौर पर शीघ्र ही नियुक्त हो सकते है. वह 1988 बैच के आईडीएसई अधिकारी बृजमोहन मिट्टा की जगह लेंगे जो यूआईएआई में ज्वाइन न करने की वजह से हटा दिए गए हैं.

सूचना एवं प्रसारण में उदय की जगह राजीव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निफ्ट के महानिदेशक और 1979 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव टाकरू अतिरिक्त सचिव के रुप में ज्वाइन करेंगे. वे 1976 बैच और मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी उदय कुमार वर्मा की जगह लेंगे, जो हाल ही में एमएसएमई के सचिव नियुक्त किए गए थे.

उपाध्याय बीएसएनएल की अगले सीएमडी

बीएसएनएल का अगला सीएमडी कौन होगा, यह अब साफ हो गया है. 1975 बैच के आईटीएस अधिकारी आर के उपाध्याय, जो फ़िलहाल टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) में सीएमडी पद पर सेवारत हैं, बीएसएनएल के वर्तमान सीएमडी कुलदीप गोयल की जगह लेंगे. यह पद 31 जुलाई से ही रिक्त पड़ा था.

जनता जीती राजनीति हारी

पृष्ठ 1 का शेष

कई बच्चे सड़कों पर यह मांग लेकर उतरे कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाए. कश्मीर के लोगों की बस एक ही अपील थी कि उनके बच्चों का करियर बचाया जाए, राज्य सरकार उनकी इस मुहिम में पूरी तरह सहायता करे, स्कूल–कॉलेजों को सुरक्षा दी जाए, ताकि बच्चे वहां जा सकें. लोगों की मांग थी कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं हैं, वे सही वक़्त पर हो जाएं, ताकि विद्यार्थियों का साल बर्बाद न हो.

सरकार ने इस संदर्भ में सख्ती बरती कि बिना परीक्षा पास किए किसी को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. इसमें शिक्षा मंत्री की बहुत अहम भूमिका यह रही कि उन्होंने काफ़ी सख्ती के साथ अध्यापकों से कहा कि वे किसी भी हालत में स्कूल पहुंचें, चाहे उन्हें कार क्यों न हायर करनी पड़े या फिर पैदल जाना पड़े. इसी तरह निजी स्कूलों के प्रबंधतंत्र ने भी सख्ती दिखाई कि स्टाफ को हर हाल में स्कूल आना है. चाहे बच्चे स्कूल में हों या नहीं. इससे अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर एक तरह दबाव पड़ा, जिससे हल्की–फुल्की हरकत सड़कों पर शुरू हो गई. और एक बार जब सड़कों पर हरकत का माहौल शुरू हो गया तो फिर सख्ती का कोई माहौल देखने को नहीं मिलता है. फिर आपको हवाओं में नरमी का रुख़ नज़र आने लगता है. बच्चों का साल ख़राब होने के ख़तरे से अभिभावक परेशान हो

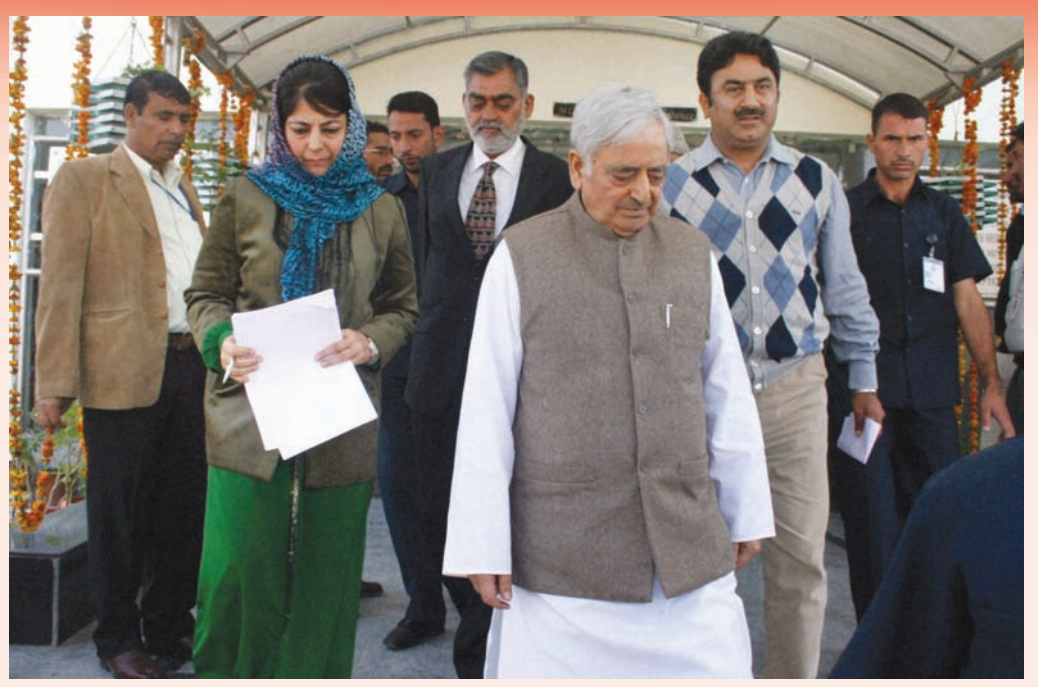

गए. सरकार ने भी लोगों के मूड को समझा और उसने ज़रूरी आदेश जारी किए. सरकार की तरफ़ से कहा गया कि परीक्षार्थियों के पास जो प्रवेशपत्र हैं, उन्हें कर्फ्यू पास मानकर वे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं. पुलिस से भी कह दिया गया कि इन विद्यार्थियों को रोका न जाए. इस तरह छात्र घरों से बाहर निकलने लगे और उन्होंने स्कूल–कॉलेज जाकर परीक्षाएं दीं. श्रीनगर के सभी बड़े स्कूल खोल दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी बस सेवाएं बंद कर दीं. कहा गया कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने और ले जाने की ज़िम्मेदारी अभिभावकों की होगी. अभिभावकों ने भी इस स्थिति से निपटने के लिए पूरा समर्थन दिया. लोगों ने कहा कि अगर बसें नहीं आती हैं और सुरक्षाबल स्कूल जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे तो वे बच्चों को ख़ुद स्कूल पहुंचाएंगे.

कश्मीर में यह बड़ी शांति से चल रहा है. यहां कर्फ्यू में भी स्कूल खुले हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं. अगर अभिभावक साथ हैं तो ठीक और अगर नहीं हैं, तब भी वे स्कूल जा रहे हैं. स्कूल बसें इसलिए बंद करा दी गईं, क्योंकि उन पर हमले होते थे. ख़बर बनती थी. लेकिन जबसे लोग अपने निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल पहुंचाने लगे हैं, तबसे पथराव की घटनाएं बंद हो गई हैं, क्योंकि किसी कार पर पथराव करने से ख़बर नहीं बनती और लोगों का समर्थन खोने का ख़तरा भी बढ़ जाता है. इसलिए बच्चों के स्कूल–कॉलेज जाने के बहाने ही सही, कश्मीर में जनजीवन सामान्य हो गया है. हालात को ठंडा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है. कोई भी परीक्षा स्थगित नहीं की गई. बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन एवं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ऐलान कर दिया कि हर बच्चा अपने प्रवेशपत्र को कर्फ्यू पास की तरह प्रयोग करके परीक्षा देने पहुंच जाएगा. उससे सारी सख्ती टूट गई. चाहे वह सरकार की रही हो या हुर्रियत की. एक आदमी निकला, दस निकले, कतारें निकलीं और फिर हुजूम...धीरे–धीरे सारा सन्नाटा ख़त्म हो गया. भारत सरकार ने स्कूलों के लिए 100 करोड़ का पैकेज दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए. यह आदेश दिया गया कि स्कूल खोले जाएं. भारत सरकार ने अभिभावकों की चिंता का फ़ायदा उठाया कि वे इस बात से तंग आ चुके हैं. सरकार ने अभिभावकों के इस संकेत को पहचाना और इसका इस्तेमाल डेडलॉक तोड़ने में किया. सुरक्षाकर्मियों से कहा गया कि अभिभावकों, बच्चों और उनके वाहनों को कोई नहीं छेड़ेगा. इससे स्वत: लोग निकले और उन्होंने हुर्रियत को न कर दी. एक निकले, फिर धीरे–धीरे सब निकले. और जो भी लोग चाहते थे कि हड़ताल रहे, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे थे, वे समझ गए कि अब उनकी नहीं चलेगी. सरकार ने बहुत अच्छी चीज पकड़ी थी और इसी को वह आगे भी बढ़ा सकती है. यहां जो लोग हैं, उनके बीच वर्ग बन गए हैं. इनमें एक बहुत बड़ा वर्ग वह है, जो चाहता है कि हालात नॉर्मल हो जाएं बच्चों की खातिर. भारत सरकार के लिए यह निश्चित ही बहुत अच्छा वक़्त है, जबकि वह शिक्षा व्यवस्था को ही आगे ले जाते हुए जोर डाले कि वह निर्बाध रूप से चलती रहे. स्कूल–कॉलेज चलते रहें, ताकि इसी बहाने यहां परिवहन और व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें.

यह एक ऐसा विषय था, जिससे कश्मीर का हर परिवार परेशान था. सबको अपने बच्चों की चिंता सता रही थी. बंद का समर्थन करने वाले संगठन और नेता सब चुप हो गए. उन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें. इससे कई फ़ायदे हुए. कश्मीर की जनता के साथ–साथ सरकार और हुर्रियत को भी राहत मिली. हुर्रियत को लगा कि यह एक ऐसा वक़्त है कि अगर अब कोई बयानबाज़ी हुई और स्कूल–कॉलेज बंद रहे तो जनता उसकी बातों को मानने से इंकार कर देगी. हुर्रियत ने स्थिति का जायज़ा लिया और इंतज़ार करने लगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, लोगों का क्या मूड है. वह अपनी साख बचाने के लिए लोगों पर कोई भी चीज थोपने से बचती रही. माहौल यह बन गया कि सब यही चाहने लगे कि बच्चे जल्द अपने डेली रूटीन में आ जाएं, नौकरी करने वाले लोग अपनी ड्यूटी पर जाने लगें. लोगों के इस मूड को देखते हुए हुर्रियत भी चुप है, वह किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाज़ी से बच रही है. वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है. बर्फ की वजह से श्रीनगर में काम ठप्प पड़ जाता है. मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अधिकारी सभी जम्मू चले जाते हैं. जब तक ये लोग यहां होते हैं, इनकी गाड़ियां दिखती हैं, कोठियों के आसपास लोग होते हैं, सड़कों पर इनका आना–जाना होता है. जैसे ही यह सरकारी मशीनरी जम्मू शिफ्ट हो जाएगी, यहां के लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 32
दिल्ली, 18 अक्टूबर–24 अक्टूबर 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सीमांचल
बाग़ी पलट सकते हैं बाज़ी

हाजी तौफ़ीक

शकील अख्तर

राज किशोर केसरी

वरुण सिंह

कलीमुद्दीन अंसारी

नवीन सिंह कुशवाहा

सादिक समदानी

संतोष कुशवाहा

कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है. कब कौन नेता पाला बदल ले या किसी से हाथ मिला ले, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता. कभी सीमांचल की राजनीति में राजद के अगुवा एवं लालू के प्रबल सहयोगी रहे तस्लीमुद्दीन आज नीतीश के साथ हैं और अपने प्रभाव से पुत्र समेत कई समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं. एक समय ऐसा भी था, जब वह नीतीश को सांप्रदायिक क़रार देते नहीं थकते थे. यही वजह है कि सीमांचल में उपजे नए समीकरणों ने यहां बाग़ियों की एक बड़ी फ़ौज खड़ी कर दी है, जो किसी की भी जीती हुई बाज़ी पलटने की हैसियत रखती है. अगर 2005 के विधानसभा चुनावों पर नज़र डालें तो जदयू की झोली में एकमात्र अररिया की जौकीहाट सीट आई थी, जिस पर मंजर आलम ने तस्लीमुद्दीन के पुत्र एवं राजद उम्मीदवार सरफ़राज को हराया था. सीमांचल की किशनगंज, धमदाहा एवं रुपौली यानी तीन सीटें राजद के खाते में गई थीं, वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते गोपाल अग्रवाल ने पाला बदल कर जदयू को गले लगा लिया था. बहादुरगंज, अमौर एवं कोढ़ा आदि सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं.

नीरज कुमार सिंह

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मिल रहे संकेतों के अनुसार, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रुपौली, कसबा एवं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में राजद–लोजपा गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस और जदयू के साथ त्रिकोणात्मक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बाग़ी उम्मीदवारों ने इस मुक़ाबले को रोचक बना दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सीमांचल में टिकट वितरण से लेकर भाजपा से सीटों के तालमेल तक जदयू की ओर से तस्लीमुद्दीन की जमकर चली. उन्होंने अपने जिन रिश्तेदारों–समर्थकों को चाहा, टिकट दिलाया. जिसे नहीं चाहा, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया. किशनगंज की चार विधानसभा सीटों में से तीन जदयू की झोली में गईं, जबकि किशनगंज सीट काफ़ी जद्दोजहद के बाद भाजपा के खाते में आई. यहां से युवा महिला प्रत्याशी के रूप में स्वीटी सिंह के नाम की घोषणा की गई. किशनगंज की अधिकतर सीटें जदयू के कोटे में जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में पार्टी नेतृत्व के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त आक्रोश है. वहीं जदयू के पुराने समर्पित कार्यकर्ता भी टिकट न मिलने से काफ़ी नाराज़ हैं. किशनगंज में प्राय: सभी दलों से बाग़ी उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां लड़ाई सुरजापुरी मुस्लिम बनाम अन्य मुस्लिम के बीच दिख रही है. इसी आधार पर कांग्रेस सांसद असरारुल हक़ की जीत हुई थी. नए परिसीमन में गठित बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज विधानसभा सीटों का भौगोलिक और जातिगत समीकरण बदल चुका है. स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों सीटें उनकी परंपरागत सीटें रही हैं. बहादुरगंज में पहली बार टेड़ागाछ प्रखंड को जोड़ा गया है, जहां अधिकतर मतदाता भाजपा समर्थक हैं. वरुण सिंह ने बहादुरगंज में भाजपा के लिए काफ़ी काम किया है. वह चुनाव मैदान में डट गए हैं. भाजपाइयों का कहना है कि ज़िला कमेटी राज्यस्तरीय समझौते को नहीं मानती. अत: सारे भाजपा कार्यकर्ता बहादुरगंज से वरुण सिंह, ठाकुरगंज से पूर्व विधायक अवध बिहारी सिंह एवं नवसृजित कोचाधामन से मुखिया मशकूर को प्रत्याशी बनाकर उनके लिए वोट मांगने में जुट गए हैं. ठाकुरगंज से वर्तमान विधायक गोपाल अग्रवाल को जदयू का टिकट मिल गया है, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है. भाजपा समर्थकों का कहना है कि गोपाल अग्रवाल को इस सीट से जदयू का टिकट मिलना आश्चर्य का विषय है. वह समाजवादी पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और दल बदल कर जदयू में शामिल हो गए. लोजपा प्रत्याशी नौशाद आलम की स्थिति ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में अच्छी दिख रही है.

नए परिसीमन में गठित बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज विधानसभा सीटों का भौगोलिक और जातिगत समीकरण बदल चुका है. स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों सीटें उनकी परंपरागत सीटें रही हैं.

कोचाधामन एवं किशनगंज में कांटे की टक्कर होने की संभावना है. किशनगंज से काफ़ी संघर्ष के बाद स्वीटी सिंह को भाजपा का टिकट मिला. टिकट न मिलने से क्षुब्ध लोजपा ज़िला अध्यक्ष कलीमुद्दीन अंसारी के एनसीपी से चुनाव मैदान में आ जाने से मुक़ाबला रोचक होने की उम्मीद है. नवसृजित कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सादिक समदानी, राजद के वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान और जदयू के मास्टर मुजाहिद के बीच मुख्य मुक़ाबला है. समदानी सांसद असरारुल हक के क़रीबी माने जाते हैं. अगर उन्हें सुरजापुरी मुस्लिमों का साथ मिलता है तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है. पूर्णिया के बायसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में हैं, उन्हें सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू का समर्थन प्राप्त है. उनके पक्ष में डगरुआ के पूर्व ज़िला पार्षद मोहम्मद शमीम, मुखिया नसीम एवं प्रमुख हाजी जफर मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं. इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है. उधर कांग्रेस से निसार अहमद चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस से टिकट न मिलने पर हाजी तौफीक उर्फ़ कुर्रश एनसीपी से चुनाव मैदान में आ गए हैं. उनकी पकड़ महानंदा से सटे गांवों में है.

पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय कॉमरेड अजित सरकार के पुत्र अमित सरकार के आ जाने से मुक़ाबला रोचक हो गया है. वर्तमान भाजपा विधायक राज किशोर केसरी हैट्रिक बना चुके हैं और चौथी बार विधायक बनने के लिए कसरत कर रहे हैं. कांग्रेस से राजचरित्र यादव का भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया. वह कई बार कुछ ही मतों से विधानसभा जाने से वंचित रह गए. धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नवीन सिंह कुशवाहा के आ जाने से मुक़ाबला रोचक हो गया है. नवीन के बारे में कहा जाता है कि लव–कुश समीकरण के अलावा अन्य जातियों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ है, जिससे राजद के दिलीप यादव एवं जदयू के लेसी सिंह के साथ उनका सीधा मुक़ाबला है. रुपौली विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक वीमा भारती ने पाला बदल लिया है. अब वह जदयू से उम्मीदवार हैं. लोजपा के शंकर सिंह भी यहां मैदान में हैं. उन्हें इस बार बड़हरा कोठी प्रखंड के रुपौली में जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भितरघात का ख़तरा सभी दलों को सता रहा है. इसलिए सीमांचल की सभी सीटों पर हार–जीत का अंतर काफ़ी कम होगा.

feedback@chauthiduniya.com

मगध
घात-प्रतिघात का दौर

सुनील सौरभ

महत्वाकांक्षी नेताओं की बढ़ती फ़ौज और कार्यकर्ताओं की घटती संख्या हर राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय बन गई है. चुनाव आते ही हर नेता की नज़र सिर्फ़ टिकट पर रहती है. अपने दल का टिकट न मिलने पर वे दल बदलने में पल भर की देर नहीं लगाते. जब उनसे उनके स्वार्थी होने की बात कही जाती है तो वे अपने बचाव में तरह–तरह के तर्क देते हैं. मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में सभी दलों के प्रत्याशियों की स्थिति देखने पर साफ़ पता चल जाता है कि जिस नेता को दलबदल करने के बाद किसी अन्य दल से टिकट मिला है तो पूर्व पार्टी के आलाकमान के प्रति उसके सुर बदल जाते हैं. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अभिराम शर्मा को जब जदयू से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला तो उनके भी सुर बदल गए. रात तक ग़लत नज़र आने वाले नीतीश सुबह होते ही भाग्यविधाता और विकास पुरुष नज़र आने लगे. जबकि वर्षों से जदयू का झंडा थामकर नीतीश का हाथ मज़बूत करने वाले स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता मुंह ताकते रह गए.

भितरघात से तो कमोबेश सभी दल त्रस्त हैं. गया शहर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा–राजद गठबंधन एवं कांग्रेस प्रत्याशी को भी भितरघात का सामना करना पड़ेगा. शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में राजद–लोजपा, भाजपा–जदयू और कांग्रेस यानी तीनों को भितरघात का ख़तरा है. बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतनराम मांझी के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र चले जाने के बाद उनकी समधिन ज्योति मांझी को यहां से जदयू का प्रत्याशी बना दिया गया, जिससे टिकट के लिए कतार में खड़े स्थानीय नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया और विरोध के स्वर तेज़ हो गए. गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह को टिकट मिलने के साथ ही विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है. उसका कहना है कि पूर्व के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वीरभद्र यशराज और अमरेंद्र सिंह डब्लू को हराने में सुरेंद्र सिंह की भी भूमिका थी. यही हालत वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने यह सीट भाजपा के कोटे में देकर छुटकारा पा लिया, क्योंकि यहां से क़रीब एक दर्जन मज़बूत जदयू नेता टिकट के दावेदार थे. इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए नीतीश कुमार ने वजीरगंज भाजपा को देकर अतरी सीट अपने खाते में ले ली, लेकिन इससे भी जदयू को राहत नहीं मिलने वाली. अतरी से कृष्णनंदन यादव को प्रत्याशी बनाने से जदयू के बड़े यादव नेता ख़फ़ा हैं और उनकी नाराज़गी भितरघात के रूप में सामने आ सकती है. हालांकि जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष देवनंदन प्रसाद सिंह के प्रयासों से ही कृष्णनंदन यादव को टिकट मिला है.

दल कोई भी हो, हर जगह असंतोष की लहर सहज ही दिख जाती है और लगभग हर दल में, हर सीट पर भितरघात की आशंका है. वजह साफ़ है कि सभी दल कार्यकर्ताओं के बजाय नेताओं को स्थापित करने में लगे हैं. कुर्था, अरवल, गोह, कुटुंबा, रफीगंज, औरंगाबाद, दाउदनगर, नवादा, गोविंदपुर, रजौली एवं हिसुआ के साथ–साथ गया ज़िले के टिकारी, इमामगंज एवं बेलागंज आदि विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी बदल कर टिकट पाने वाले प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अपने दल के ज़मीनी नेताओं–कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रत्याशियों को महंगा पड़ सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

धर्मनिरपेक्ष सरकार और तमाम संवैधानिक अधिकारों के होने के बावजूद मुसलमानों को समय-समय पर मुसलमान होने की क़ीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी तरफ़ शायद ही किसी का ध्यान जाता है.

मुख्यधारा में कैसे आएं मुसलमान

ज़ाहिद खान

हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही सुनियोजित तरीक़े से एक सामान्य बोध विकसित कर दिया गया है कि मुसलमान मुख्य धारा में नहीं आना चाहते और इसी वजह से वे पिछड़े हैं. कहने को मुस्लिम हर मामले में पिछड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं पर यह आरोप है कि बरसों से सियासी पार्टियां उनका तुष्टीकरण कर रही हैं. मानों मुसलमानों की शर्त पर ही पूरा देश पिछड़ा हो. ख़ैर, मान लिया जाए कि मुखतलिफ सरकारें और सियासी पार्टियां मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रहीं, लेकिन उसके फ़ायदे मुस्लिम समाज में कहीं दिखाई क्यों नहीं देते? इसका जवाब किसी के पास नहीं. उल्टे जब भी यह कथित तुष्टीकरण हुआ, मुस्लिम समाज तरक़्क़ी की दौड़ में और पीछे हो गया. बुज़ुर्ग शाहबानो का मामला एक छोटी सी मिसाल भर है. मुसलमान मुख्यधारा में क्यों नहीं आ पाए और इसकी क्या बड़ी वजहें हैं, आइए सिलसिलेवार पड़ताल करें.

आज अगर हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क की मुख्यधारा में कहीं नज़र नहीं आता, तो उसके पीछे बकायदा एक सोची-समझी साजिश रही है. सरकार के अंदर-बाहर बैठी दक्षिणपंथी ताक़तें बरसों से मुसलमानों के इर्द-गिर्द साजिशों के तार बुनती आई हैं, जिनकी गिरफ़्त से वे चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आज़ादी के बाद मुसलमानों पर सबसे बड़ी गाज इवाक्यूई प्रॉपर्टी लॉ (निष्क्रांत संपत्ति क़ानून) की शक्ल में गिरी. इस क़ानून के तहत मुसलमानों के उद्योग, व्यापार, दुकान, मकान, ज़मीन-जायदाद और संपदा का हरण इस आधार पर किया गया कि उनके परिवार के सदस्य बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे. ज़ाहिर है, इस मनमाने क़ानून ने उनकी आर्थिक-सामाजिक हालत ख़राब करके रख दी. वे रातोंरात अपने पुरखों की ज़मीन-जायदाद से बेदख़ल हो गए. अपनी जड़ों से कट चुके मुसलमान इतने पस्त हिम्मत हो चुके थे कि विरोध जताने या ख़ुद को संगठित कर पाने में अक्षम थे. लिहाज़ा हिंदुतान में उन्हें जो थोड़ा-बहुत मिला, उसे ही अपनी क़िस्मत समझ चुप बैठ गए. अपनी ज़मीन-जायदाद से तो वे बेदख़ल हुए ही, सरकारी नौकरियों में भी उन्हें लेने से रोका गया. पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने) ने अपने विभाग में बकायदा एक गोपनीय परिपत्र के ज़रिए मुसलमानों को नौकरियों में लेने से रोका. उस गोपनीय परिपत्र का मजमून कुछ इस तरह से था, पाकिस्तानियों या संभावित पाकिस्तानियों को. मुसलमानों के प्रति कमोबेश कुछ ऐसा ही रवैया तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का रहा. उन्होंने अपने एक शासनादेश में कहा था कि पुलिस और सेना में मुसलमानों की भर्ती न की जाए या कम से कम की जाए. पंत का यह शासनादेश जाने-अनजाने आज तक बरक़रार है. सेना की चयन प्रक्रिया में आज भी ऐसी मानसिकताएं काम कर रही हैं, जो सेना में मुसलमानों के चुने जाने के ख़िलाफ़ हैं. मौजूदा समय में 10 लाख भारतीय सैनिक हैं, जिनमें मुस्लिमों की संख्या महज़ 29 हज़ार होना सेना में भेदभाव की ओर ही इशारा करता है.

ज़ाहिर है, आज़ादी मिलने के शुरुआती 25-30 सालों में बमुश्किल उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह मिली. मुसलमानों पर अविश्वास और उन्हें शक की निगाह से देखा जाना एक बड़ी वजह रही, जिसके चलते वे शुरुआत से ही तरक़्क़ी की दौड़ में पिछड़ते चले गए. जैसे-तैसे यह यक़ीन बहाल हुआ. मुसलमानों ने मुख्यधारा में आने की कोशिश की, मगर देश में होने वाला हर सांप्रदायिक दंगा उन्हें पीछे की ओर धकेल देता. दंगों की आंच से मुसलमानों के रोज़गार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए. दंगों की ज़्यादातर वजह मजहबी बताई जाती है, जबकि उनके पीछे आर्थिक वजहें ज़्यादा काम करती हैं. मिसाल के तौर पर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मालेगांव, औरंगाबाद, मुरादाबाद, भिवंडी, भागलपुर एवं कानपुर आदि शहरों में जहां मुसलमान आर्थिक रूप से ज़्यादा मज़बूत थे, वहीं सबसे ज़्यादा दंगे हुए. इन दंगों ने मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ कर रख दी. आज से 60 साल पहले संविधान बनाते वक़्त हमारे देश के कर्णधारों ने भले ही किसी के साथ मजहब, जाति, संप्रदाय, नस्ल और लिंग के आधार पर कोई फ़र्क़ न करने का ऐलान किया हो, मगर आज हक़ीक़त इसके उलट है. ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ यह भेदभाव हर मामले में दिखाई देता है.

मुस्लिम समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र आदि में बहुसंख्यक समाज से काफी पीछे है. अलबत्ता, संविधान के तहत समानता का हक़ उसे भी हासिल है.

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट का अभी हाल में आया सर्वे देश में मुसलमानों के बदतरीन हालात को बयां करता है. सर्वे के मुताबिक़, देश में हर 10 में से 3 मुस्लिम ग़रीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजर-बसर कर रहे हैं. उनकी मासिक आय 550 रुपये से भी कम है. रिपोर्ट बताती है कि 31 फ़ीसदी मुस्लिम ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. बावजूद इसके मुल्क के हुक्मरानों को कहीं भी भेदभाव नज़र नहीं आता. 1980 में गोपाल सिंह कमेटी और बाद में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों में मुसलमानों की तस्वीर बहुत हद तक नज़र आई है. मुसलमानों के समग्र विकास के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कई सिफ़ारिशें की थीं. सबसे अहम सिफ़ारिश थी, सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के प्रति होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना, लेकिन रिपोर्ट को आए 4 साल हो गए, पर समान अवसर आयोग अभी तक हक़ीक़त नहीं बन पाया, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में समान अवसर आयोग गठित करने का वादा किया था. यही नहीं, यूपीए द्वारा दोबारा सत्ता संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने जून 2009 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए समान अवसर आयोग गठित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया था.

सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की दूसरी अहम सिफ़ारिश थी, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन इस पर भी सरकार कतई संजीदा नहीं दिखाई देती. जबकि संसद और बाहर दोनों जगह सरकार पर रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने का ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है. असल में देश में मुसलमानों का पिछड़ापन इतना है कि शहरी इलाक़ों में तक़रीबन 38 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाक़ों में 27 फ़ीसदी मुसलमान ग़रीबी रेखा के नीचे बदतरीन हालत में गुज़र-बसर कर रहे हैं. उनके पिछड़ेपन को देखते हुए मिश्र आयोग ने पिछड़े वर्ग के 27 फ़ीसदी कोटे में भी अल्पसंख्यकों का कोटा निर्धारित करने की वकालत की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ओर अभी तक कोई पहल नहीं की. लोकसभा और विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करने की सिफ़ारिश की थी. इस पर यूपीए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी कर दिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट का अभी भी इंतज़ार है. वक़्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन के लिए यूपीए सरकार ने संसद में बयान दिया था कि मौजूदा वक़्फ बोर्ड में त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए वक़्फ अधिनियम में शीघ्र ही व्यापक संशोधन किया जाएगा, जिससे करोड़ों-अरबों रुपये की वक़्फ संपत्तियों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सके, पर यह संशोधन भी संसद में पेश होने की बाट जोह रहा है.

मुस्लिमों की आय का मुख्य ज़रिया ख़ुद का रोज़गार है. सच्चर कमेटी का आकलन था कि मुसलमानों को वित्तीय संस्थाओं से दूसरों की अपेक्षा कम क़र्ज़ मिलता है. उन्हें क़र्ज़ देने में आनाकानी की जाती है. हर जगह यह हालत होने के बावजूद कहीं भी इसकी निगरानी नहीं होती. लिहाज़ा सरकार ने इस दिशा में सुधार करने के लिए मुस्लिम नौजवानों को स्वरोज़गार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क़र्ज़ की सहूलियत बढ़ाने, आगामी 3 साल में क़र्ज़ मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी तक ले जाने और इसकी निगरानी करने का वादा किया था, लेकिन हालात आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं. इस मामले में ख़ुद सरकारी आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, साल 2009-10 में गुजरात में सरकारी बैंकों ने अल्पसंख्यकों को जो कर्ज बांटा, वह उनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को बांटे गए क़र्ज़ का महज़ 4.45 फ़ीसदी है, जबकि यह 10 फ़ीसदी होना चाहिए था. बैंकों ने यहां अल्पसंख्यकों को 5,341 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा था, वहीं बांटा सिर्फ़ 1860.81 करोड़ रुपये यानी महज़ 34.84 फ़ीसदी. मुसलमानों को क़र्ज़ देने के मामले में सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार हो या फिर दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार, दोनों का मुसलमानों को क़र्ज़ देने के मामले में एक जैसा रवैया है. दिल्ली में यह लक्ष्य 5,982 करोड़ रुपये का था, लेकिन बांटे गए महज़ 3,165 करोड़ रुपये. यानी लक्ष्य का महज़ 52.97 फ़ीसदी. कमोबेश यही हाल कांग्रेस शासित अन्य राज्यों महाराष्ट्र एवं राजस्थान का रहा, जहां तय लक्ष्य का 50 एवं 58.51 फ़ीसदी ही क़र्ज़ बांटा गया.

इसके अलावा यूपीए सरकार ने ऐलान किया था कि चिन्हित किए गए 90 अल्पसंख्यक आबादी बाहुल्य ज़िलों, जो विकासात्मक मापदंडों पर पिछड़े हुए हैं, में बुनियादी और आर्थिक सुविधाओं में सुधार के लिए ख़ास प्रावधान किए जाएंगे. सरकार ने इस दिशा में कोशिश भी की. इन इलाक़ों के विकास के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना यानी एमएसडीपी शुरू की गई, जो 2,750 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना है. श्रीमती इंदिरा गांधी के 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के बाद मुसलमानों के समग्र विकास के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी पहल है, लेकिन यह बहुउद्देशीय योजना भी संकीर्ण राजनीति और उदासीन अफसरशाही का शिकार होकर रह गई है. राज्य सरकारों और नौकरशाहों का इस योजना के प्रति उपेक्षापूर्ण और उदासीन रवैया है. इसका उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां 2008-09 के दौरान इस मद में 169 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन सरकार ने इस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया. कमोबेश यही हाल अन्य राज्यों का है, जहां बमुश्किल इस रकम का 10 से 15 फीसदी ही ख़र्च किया जा सका है.

धर्मनिरपेक्ष सरकार और तमाम संवैधानिक अधिकारों के होने के बावजूद मुसलमानों को समय-समय पर मुसलमान होने की क़ीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी तरफ़ शायद ही किसी का ध्यान जाता है. ख़ास तौर पर वे नौकरशाही और सुरक्षा एजेंसियों की सांप्रदायिक सोच का सबसे बड़ा शिकार हैं. बिना अपराध के उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है. जब भी कहीं सांप्रदायिक दंगे या आतंकी घटना होती है, पूरे मुस्लिम समुदाय पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है. पुलिसिया धरपकड़ का पहला निशाना मुसलमान होते हैं और बिना समुचित जांच-पड़ताल के गिरफ़्तारियां होने लगती हैं. देश में हाल में हुए तमाम बम विस्फोटों में जांच एजेंसियों ने जो गिरफ़्तारियां कीं, यदि समीक्षा करें तो उनमें सबसे ज़्यादा गिरफ़्तारियां मुसलमानों की हैं. यह बात अलग है कि सबूत न मिल पाने के चलते बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा. मसलन जयपुर बम विस्फोट में डॉ. अबरार एवं अनवार और हैदराबाद में 22 मुस्लिम नौजवानों को मक्का बम विस्फोट का गुनहगार बताकर पहले तो 8-10 महीने जेल में रखा गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया. इन घटनाओं से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान किन हालात से गुज़र रहे हैं. उनके प्रति संदेह और अलगाव के माहौल ने उन्हें मुख्यधारा से काटकर रख दिया है.

यही वे वजहें हैं, जिनके चलते मुसलमान चाह कर भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं. मुसलमान मुख्यधारा में आएं, इसके लिए सरकार को अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी. सबसे पहले सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग के तमाम सुझावों और सिफ़ारिशों को ईमानदारी से अमल में लाना होगा. नौकरशाही में व्याप्त सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और उदासीनता दूर करने के विशेष प्रयास करने होंगे. मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान से न सिर्फ़ इस समुदाय की हालत सुधरेगी, बल्कि देश का भी समुचित विकास होगा. तमाम आयोगों-कमेटियों के गठन के पीछे सरकार की हमेशा यही मंशा रही है कि मुसलमानों का विकास किया जाए और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. दरअसल, सवाल हाशिए पर रहे समाज को आगे बढ़ाने का भी है. उपेक्षित तबकों की न्यायोचित आकांक्षाओं-मांगों की अनदेखी भला कब तक की जा सकती है. सामाजिक न्याय सभी जगह ज़रूरी है. न्याय होगा तो मुसलमानों के विकास में भी झलकेगा. ज़ाहिर है, मुस्लिम समुदाय का विकास देश के विकास से अलग नहीं है.

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

इस इलाक़े में जंगल, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाओं का अपार भंडार होना ही यहां के आदिवासी और अन्य वनाश्रितों की दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है.

आदिवासी आज भी ग़ुलाम हैं

रोमा

आज देश के अधिकांश जंगलक्षेत्र एक ऐसी हिंसा की आग से धधक रहे हैं, जिसकी आंच को कहीं न कहीं पूरा देश महसूस कर रहा है. इस आग का कारण इन क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों का तेज होना है. देश की आज़ादी के बाद से ही सुलग रही इस आग ने आज एक विकराल ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है. सरकारों द्वारा इस आग को लेकर ज़ाहिर की जा रही चिंताओं और मीडिया द्वारा किए जा रहे प्रचार के कारण आम समाज में भी यह धारणा मज़बूत हो रही है कि इस आग का सबसे बड़ा कारण नक्सलियों द्वारा हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जाना है.

यह धारणा एक हद तक सही है, लेकिन यह स्थिति का एकपक्षीय आकलन ही होगा. धरातल पर उतरकर अगर स्थिति का जायज़ा लिया जाए तो इसके पीछे सैकड़ों हज़ारो वर्षों से इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों व वनाश्रित समुदायों के साथ सरकारों के दमनात्मक रवैये और इन समुदायों के संघर्षों की एक लंबी दास्तान मिलेगी. विडंबना है कि आज़ादी के 63 वर्ष बीत जाने के बाद सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों की तरफ़ तब जा रहा है, जब वे ख़ुद इस आग में झुलसने लगी हैं. ऐतिहासिक रूप से वनों में आदिवासियों के संघर्षों का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है. वनों के अंदर ही स्वाधीनता पाने के लिए सबसे पहले संघर्ष का बिगुल बजाया गया था. हालांकि वनक्षेत्रों में यह संघर्ष देश आज़ाद हो जाने के बाद आज भी ज़ारी है, यानि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आदिवासी आज भी गुलाम हैं.

ग़ौरतलब है कि इन संघर्षों की तमाम गाथायें आदिवासियों के गौरवमयी इतिहास में दर्ज हैं, जिन्होंने लगातार जनवादी तरीके को क़ायम रखते हुए संघर्ष की राह को नहीं छोड़ा. लेकिन सत्ता की भेदभावपूर्ण नीतियों और वनाश्रित समुदायों के संघर्षों की अनदेखी के चलते नतीजा यह हुआ कि समुदायों द्वारा तैयार किए गए इस जनवादी परिसर पर हथियारबंद ताक़तों ने अपना क़ब्ज़ा जमा लिया. ऐसा नहीं है कि देश के सभी वन क्षेत्रों में हथियारबंद आंदोलन ही चल रहे हों. मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड का कैमूर क्षेत्र, मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से जुड़ा तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा, असम में काज़ीरंगा जैसे कई वनक्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर दमन व उत्पीड़न होने के बावजूद जनवादी आंदोलन मज़बूती के साथ चल रहे हैं, जो न केवल सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, बल्कि माओवादियों को भी पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं. लेकिन विडंबना यह है कि इन जनवादी आंदोलनों को भी नक्सली आंदोलन की संज्ञा दी जा रही है.

आज देश के वनों में सबसे बड़ा सवाल भूमि सुधार, वनों पर समुदायों के अधिकार व विकास का है, जिसे हल किए बग़ैर इन क्षेत्रों में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती. आज सरकार द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि माओवादियों को ख़त्म करने से समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन यह आम जनता के साथ किया जा रहा एक बहुत बड़ा धोख़ा है. दरअसल आज मामला माओवादियों से कहीं बहुत आगे जा चुका है, मामला अब जनता और सरकार के बीच सीधी टक्कर का है. यही वजह है कि सरकार को भी यह रास्ता आसान दिखाई पड़ता है कि माओवाद की आड़ लेकर जनवादी आंदोलनों को कुचल दिया जाए. इसकी वजह यह है कि सरकारों के लिए जनवादी आंदोलनों से जूझना, हथियार बंद आंदोलनों से जूझने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है. आज वनक्षेत्रों में लोग सन् 2006 में पास किए गए वनाधिकार क़ानून के तहत अपने अधिकारों को पाने के लिए जनवादी तौर-तरीक़ों से लामबंद हो रहे हैं. लेकिन इस क़ानून के लागू हो जाने के बाद भी सरकार की तरफ़ से वनसमुदायों को उनके अधिकार वास्तविक रूप में देने के लिए कोई राजनैतिक इच्छा नहीं दिखाई दे रही है. इस क़ानून को लेकर सरकार में एक असमंजस की स्थिति बराबर बनी हुई है.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री ने माओवादियों से लड़ने के लिए वन विभाग की मदद लेने की बात कही. हैरत की बात है कि देश की आज़ादी के 63 सालों में से क़रीब 40 वर्षों तक राज करने वाली पार्टी को शायद यह नहीं मालूम कि देश के जंगल क्षेत्रों में हथियार बंद आंदोलनों का सबसे बड़ा कारण वन विभाग द्वारा समुदायों के साथ किया गया अन्याय व उत्पीड़न ही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है व जिसका उल्लेख वनाधिकार क़ानून की भूमिका में भी है. ग़ौर किया जाए तो इस क़ानून में नक्सल समस्या को हल करने के सूत्र भी छुपे हैं. यह देखना ज़रूरी होगा कि जिन इलाक़ों में माओवादी गतिविधियां जोर पर हैं, वहां वन विभाग की स्थिति क्या है. अगर इन इलाक़ों में वन विभाग मज़बूत है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहां माओवाद नहीं है. अगर है भी तो वह माओवादियों के नाम पर राज्य को मदद करने वाला क्षेत्रीय सामंतों तथा पुलिस का पैदा किया कोई गुट हो सकता है. उदाहरण के तौर पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कैमूर क्षेत्र में आने वाले जनपद सोनभद्र का नाम लिया जा सकता है. इस जनपद में सामंती ताक़तों, बड़ी-बड़ी कंपनियों, वन विभाग व पुलिस द्वारा यहां के वनक्षेत्रों में रहने वाले दलित-आदिवासी समुदायों और अन्य ग़रीब वनाश्रितों का किया जाने वाला उत्पीड़न अपने चरम पर है. इस जनपद को राज्य पुलिस द्वारा माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. इस इलाक़े में जंगल, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाओं का अपार भंडार होना ही यहां के आदिवासी और अन्य वनाश्रितों की दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है. यहां आज़ादी के बाद राष्ट्र के विकास के नाम पर सरकार और बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा आदिवासियों की जंगल, ज़मीन और प्राकृतिक संपदाओं की बड़े पैमाने पर लूट की गई. एक तरफ़ अशिक्षित और विकास के रास्तों से पूरी तरह वंचित यहां के मूल निवासी आदिवासी व अन्य वनाश्रित समुदाय तो दूसरी तरफ़ यहां की ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर काबिज़ सभी तरह की सुविधाओं से लैस सामंती तबके व बाहर से आई पूंजीवादी ताक़तें. यानि एक ही ज़िले में एक-दूसरे से ठीक उलट दो तरह की दुनिया.

आज जबकि तमाम वनाश्रित तबकों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करते हुए बनाया गया वनाधिकार क़ानून देशभर में लागू हो चुका है, तब भी यहां के दलित आदिवासियों को उनके पुश्तैनी घर व ज़मीनों से लगातार बेदख़ल किया जा रहा है. इस इलाक़े में माओवादियों के होने की घोषणा किए जाने के पहले वन विभाग का जो अत्याचार था, वह इस घोषणा के बाद भी बरक़रार है. वन विभाग द्वारा आज़ादी के बाद से लगातार इस इलाक़े में क़ानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बग़ैर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारतीय वन अधिनियम, 1927 को इस्तेमाल करके स्थानीय लोगों की ज़मीनों को अपने नाम कराकर वनभूमि में बेशुमार इज़ाफ़ा किया गया. इसी काले क़ानून का इस्तेमाल करके यहां के आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करके झूठे मुक़दमे दायर करना व जेल भेजना आज भी बदस्तूर जारी है. अवैध तरीक़े से जंगलों की अंधाधुंध कटाई और खनिज व वन संपदाओं की लूट में शामिल जहां का वन विभाग इतना ताक़तवर हो चुका हो कि बेख़ौफ़ होकर इन सारी कारगुज़ारियों को अंजाम दे रहा हो और जिसका अत्याचार अपने चरम को छू रहा हो, वहां पर माओवाद भला कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस व प्रशासन की रिकॉर्ड में यहां माओवाद ज़िंदा है, जिसे ख़त्म करने के नाम पर करोड़ो रुपयों का बजट आता है, जिसकी बंदरबांट की जाती है. दूसरी तरफ़ कुछ दिन पहले यहां दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के एडीजी ने यह बयान दिया कि अब उत्तर प्रदेश में माओवाद नहीं के बराबर रह गया है. सवाल है कि फिर वह कौन सा माओवाद है, जिसका शोर यहां की स्थानीय पुलिस लगातार मचाती रहती है. दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले इस इलाक़े में यहां की पुलिस का काम है झारखंड पुलिस द्वारा सौंपे गए कथित नक्सलियों को माओवादी साबित करके उनका एनकाउंटर कर देना या फिर उन्हें यहां की जेलों में ठूंस देना. यह स्थिति तब है जब उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल दलित आदिवासी तबकों की हिमायती सरकार है, जिसके मूल एजेंडे में ज़मीन का सवाल प्रमुखता के साथ शामिल है. दूसरे यहां के लोग अपने जनवादी आंदोलनों की ताक़त से अपने छिने हुए हक़ कहीं-कहीं हासिल भी कर रहे हैं, जिसके कारण यहां वंचित समुदायों में एक उम्मीद सी बंधी रहती है और वे अति उग्रवाद के रास्ते को अख्तियार नहीं करते. लेकिन ज़मीन पर प्रशासनिक अमला सरकार की मंशा के ख़िलाफ़ ही तमाम कार्रवाईयां कर यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश में ही लगा रहता है.

दरअसल वनों पर समुदायों के अधिकार का मामला सीधे-सीधे वर्ग संघर्ष का मामला है. वनाधिकार क़ानून के रूप में वनाश्रित समुदायों को पहली बार एक राजनैतिक हथियार हासिल हुआ है. इस क़ानून में यह निश्चित किया गया है कि वनभूमि, जिस पर राज्य व अभिजात्य वर्गों का एकाधिकार रहा है, उसे वंचित वनाश्रितों को हस्तांतरित किया जाए. भूमि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में ही ख़ूनी संघर्ष की प्रबल संभावनाएं छुपी हैं, जिसे स्वयं राजसत्ता में यथास्थिति बनाए रखने वाली ताक़तें हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान अंजाम दे सकती हैं. एक तथ्य यह भी है कि जो हिंसात्मक गतिविधियां इन जंगलों में चल रही हैं, चाहे वह सरकार या माओवादी किसी तरफ़ से भी हों, उनके केंद्र में वनाधिकार या फिर भूमि सुधार का मुददा कहीं भी नहीं है. इस बात पर भी कोई ग़ौर नहीं किया जा रहा कि मौजूदा दौर में वंचित तबकों में जिस सामूहिक राजनैतिक चेतना का उभार आ रहा है, वह दोनों तरफ़ की दमनात्मक कार्यवाहियों पर सवाल उठा रहा है.

अगर आने वाले दिनों में कोई वर्ग संघर्ष होता भी है तो उसका नेतृत्व किसी माओवादी संगठन के हाथों में न होकर आम वनाश्रित, भूमिहीन, वंचित समुदायों के उसी तबके के हाथों में होगा, जो दोनों तरफ़ की हिंसा का लगातार शिकार होते-होते पूरी तरह नाउम्मीदी के दौर से गुज़र रहा है. अब तय सरकारों को ही करना है कि वे वंचित समुदायों के अधिकारों को छीनने की प्रक्रिया को और तेज़ करके इस वर्गसंघर्ष को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाने में मदद करना चाहती हैं या फिर पीढ़ियों से अपने बुनियादी हकों की बाट जोह रहे वंचितों के हकों की बहाली का रास्ता अख्तियार करके इस संभावित वर्ग संघर्ष का रुख़ अमन और शांति की दिशा की ओर मोड़ने में कामयाब साबित होती हैं.

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आज देश के वनों में सबसे बड़ा सवाल भूमि सुधार, वनों पर समुदायों के अधिकार व विकास का है, जिसे हल किए बग़ैर इन क्षेत्रों में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती. आज सरकार द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि माओवादियों को ख़त्म करने से समस्या का हल हो जाएगा लेकिन यह आम जनता के साथ किया जा रहा एक बहुत बड़ा धोखा है.

आज़ादी के बाद बंगाल की औद्योगिक सेहत में गिरावट आने लगी. केंद्र सरकार की नीतियों का बुरा असर दिखने लगा. ख़ासकर कोयले की फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति से बंगाल स्थानीय लाभ से वंचित हो गया.

पूरब न जइयो सइयां, चाकरी नहीं है

औद्योगिक बदहाली से प्रवासियों का बुरा हाल

सइयां मोरे गइले रामा पूरबी बनिजिया, कि दे के गइले ना,
एगो सुगना खेलनवा, कि दे के गइले ना.

बिमल राय

वह दौर था 30-40 साल पहले का, जब बिहार-उत्तर प्रदेश में महेंद्र मिश्र की यह पूरबी ख़ूब गाई जाती थी. नाच या नौटंकी में इस तरह के गाने चलते थे. उस जमाने में कमाई के लिए पूरब का क्रेज़ था और प्रवासी श्रमिक सतुआ-भूजा की गठरी लेकर निकल पड़ते थे श्रमसंधान के लिए. उनका रुख़ पूरब की ओर यानी असम व पश्चिम बंगाल की ओर होता था. असम के ईंट-भट्ठों व चाय बागानों में बिहारी मज़दूरों का ही बोलबाला होता था. भोजपुरी लोकगीतों का संकेत मानें तो मजदूर म्यामार के मोरंग तक पहुंच जाते थे. हालांकि ज़्यादातर मजदूरों की पसंद पश्चिम बंगाल ही रहा. उस जमाने में जब बंगाली भद्रजन जूट मिलों में तांत के रेशे से बचने के लिए इलाक़े से अलग रहना ही पसंद करते थे, इन मेहनती प्रवासी श्रमिकों को जूट मिलों के मालिकों ने हाथोंहाथ लिया. उत्तर बंगाल में तो चाय बागानों के लिए संथाल आदिवासियों को झारखंड के इलाक़े से ले जाने का सिलसिला अंग्रेजों ने ही शुरू कर दिया था. हालांकि तब बिहार और बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, पर इससे उद्यमियों के लिए अविभाजित बिहार की श्रम शक्ति के प्रति आकर्षण तो ज़ाहिर हो ही गया. अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के विकास समूह के मुखिया शंकर वेंकटेश्वरन के मुताबिक़ हर साल बिहार के क़रीब 2 लाख लोग दूसरे राज्यों में बेहतर रोज़गार की तलाश में निकलते हैं. 2001 की जनगणना के मुताबिक़ पिछले 10 सालों में 22 लाख बिहारवासियों ने दूसरे राज्यों का रुख़ किया. नीतीश कुमार के सुशासन के कारण इस दर में कमी का अनुमान किया जा सकता है, लेकिन यह तय है कि प्रवासियों का पलायन अभी भी जारी है. हां, अब यह पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर है.

तब से लेकर अब तक हालात काफी बदल गए हैं. उस जमाने में रजमतिया रो-रोकर पाती लिखवाती थी, डाक से या हथौती उन्हें भिजवाती थी और बेसब्री से जवाब का इंतज़ार करती थी. पर अब स्थितियां बदल गई हैं. अब अपने उनसे रजमतिया सीधे मोबाइल से बात करती है, एसएमएस भेजती है. यह सब प्रवासियों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में अर्जन करने की शक्ति का नतीजा है.

प्रवासियों का बंगाल के प्रति आकर्षण अकारण या पड़ोसी राज्य होने की वजह से ही नहीं था. भारत के आज़ाद होने के समय पश्चिम बंगाल देश के औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक था. प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बंगाल में कोयला, इंजीनियरिंग, जूट, चाय और कपड़ा जैसे पारंपरिक उद्योग ख़ूब फले फूले. ब्रिटिश भारत की राजधानी और बंदरगाह नगर होने के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी यह बड़ा केंद्र बना रहा.

आज़ादी के बाद बंगाल की औद्योगिक सेहत में गिरावट आने लगी. केंद्र सरकार की नीतियों का बुरा असर दिखने लगा. ख़ासकर कोयले की फ्रेट इक्वला-इजेशन नीति से बंगाल स्थानीय लाभ से वंचित हो गया. आज़ादी के बाद दुर्गापुर स्टील कंपनी को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई. इसके अलावा सिद्धार्थ शंकर राय के समय नक्सली हिंसा ने बंगाल को और तबाह कर दिया. आपातकाल की ज़्यादतियों के साथ इन स्थानीय कारणों ने राज्य में वामपंथियों के आगमन का रास्ता साफ किया. इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव के कारण उद्योगों के फलने-फूलने के रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई. केंद्र ने उद्योगों को लाइसेंस देने के अधिकार को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.

1991 में नरसिंहा राव सरकार में वित्तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण की प्रक्रिया के लगभग दो दशकों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों की वृद्धि दर कम हो गई.

पश्चिम बंगाल में भारत सरकार की सैकड़ों कंपनियां बंद पड़ी हैं, जिनमें नेशनल जूट मिल कॉरपोरेशन, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और कृष्णा सिलीकेट एंड ग्लास कंपनी शामिल हैं. पिछले साल एक समारोह में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि केंद्र अगर इनकी जमीन दे दे, तो उन पर नये उद्योग लगाए जा सकते हैं. ज़ाहिर है सिंगूर और नंदीग्राम के दूध से जली सरकार को बिना झंझट वाली ज़मीन चाहिए, ताकि वह अपनी औद्योगीकरण की गाड़ी दौड़ा सके. विपक्ष के और दूसरे लोग सुझाव देते हैं कि नए सिरे से ज़मीन अधिग्रहण करके उद्योग लगाने से आसान है बंद कारखानों का अधिग्रहण. पर हक़ीक़त यह है कि इन कारखानों का अधिग्रहण और भी मुश्किल है. ज़्यादातर कारखानों को लेकर कोर्ट केस चल रहे हैं. मालिकों ने पीएफ, ग्रेच्युटी व श्रमिकों के अन्य पावतियों का भुगतान नहीं किया है और फरार हैं. कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में 66 उद्योग बंद पड़े हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ पूरे बंगाल में क़रीब 500 बीमार या बंद उद्योग हैं, जिनमें से 334 मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में लंबित हैं. कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंटक के मुताबिक़ 2005 से 2007 तक राज्य में 14 हज़ार श्रमिकों का रोज़गार छिना. नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक़ 1993-94 से 1999-2000 के बीच बंगाल में रोज़गार वृद्धि की दर 0.76 प्रतिशत रही, जो पहले की अवधि की 2.44 प्रतिशत की दर से काफी कम थी. इसकी वजह रही उद्योगों का बंद होना और नए उद्योगों का नहीं खुलना. एनएसएस के मुताबिक़ 2006 में बंगाल में 77 लाख लोग रोज़गार कार्यालयों में बेरोज़गार के रूप में दर्ज थे, जिनमें से 4.1 लाख 14-24 साल की आयु वर्ग के थे. इनमें से 12 प्रतिशत बेरोज़गार ग्रेजुएट थे. एनएसएस के छठे चक्र के आंकड़ों के मुताबिक़ 2005-06 में पश्चिम बंगाल की 8 करोड़ 30 लाख की आबादी में बेरोज़गारों की वास्तविक संख्या 1,04,38000 से 3,21,7000 के बीच थी. इस तरह कुल आबादी का 3.8-11.2 प्रतिशत लोग बेरोज़गार हैं. इसके अलावा हर साल से 4 से 5 लाख नए ग्रेजुएट रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत हो रहे हैं, जबकि हर साल नौकरी पाने की दर 8 से 15 हज़ार के बीच है.

उद्योगपतियों के कथित शोषण के ख़िलाफ़ फैक्ट्रियों और मिलों में हड़तालें हुईं. श्रमिक अशांति और बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने से भारी संख्या में हिंदीभाषियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा. समय की ज़रूरत भांपकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने 1993 में राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की और इस प्रक्रिया में मार्क्सवादी सिद्धांतों से भी समझौता किया गया. बुद्धदेव के कुरसी संभालने तक औद्योगिकीकरण की गाड़ी तेज रफ़्तार से दौड़ती रही, पर कागज के नक्शे जब ज़मीन पर उतरने लगे तो ममता बनर्जी का नया अवतार दिखा, नैनो की विदाई हो गई और इस तरह सब गुड़गोबर हो गया. जाहिर है रोज़गार की कमी ने प्रवासियों को पूरब से मुंह मोड़ने पर मजबूर किया है. और यही वजह है कि रजमतिया अब गाती है, पूरब न जइयो सइयां, चाकरी नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वोत्तर की पीड़ा नहीं भुला पाएंगे प्रवासी

पूर्वोत्तर भारत के असम, नगालैंड और मणिपुर बहुत पहले से प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार मुहैया कराते थे. सबसे पहले असम में दूसरे राज्यों के लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा की शुरुआत 1987 में हुई. उस समय बिहारियों के साथ बंगालियों, बांग्लादेशियों और मारवाड़ियों को भी निशाना बनाना जारी रहा. गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ सन 2000 में उल्फा और बोडो उग्रवादियों के हमलों और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लगभग 1700 मौतें हुईं.

सिलसिला थमा नहीं. उल्फा की शह पर सन 2000 से 2003 के बीच हिंदीभाषियों के ख़िलाफ़ हमलों में 200 लोग मारे गए और अपने ही देश में क़रीब 10 हज़ार लोगों को विस्थापित होना पड़ा. 2007 में उल्फा ने हिंदीभाषियों के ख़िलाफ़ हमले और तेज कर दिए और 300 लोगों को अपना शिकार बनाया. नगालैंड और मणिपुर में हालांकि असम की तरह चुन-चुनकर हिंदीभाषियों की हत्याएं करने का लंबा सिलसिला नहीं दिखा और ख़ूनी संघर्ष नगा और कुकी विद्रोहियों के बीच देखने को मिला, जिससे माहौल अशांत रहा. 2007 में रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे बिहारी छात्रों पर उल्फा ने हमला किया. इस दौर में 60 लोगों की हत्याएं हुईं. मारवाड़ी समुदाय के लोग फिरौती के रूप में भारी आर्थिक शोषण का शिकार हुए तो सुदूर इलाक़ों में रह रहे बिहारियों को सबकुछ छोड़कर वापस बिहार लौटना पड़ा. 2008 में उल्फा ने जब युद्ध विराम का फ़ैसला किया और बातचीत का रास्ता अपनाने का रुख़ दिखाया तो हिंदीभाषियों का पलायन थोड़ा रुका. अब उल्फा की रीढ़ टूटने के कारण बहुत सारे वे प्रवासी असम लौट चुके हैं, जिनकी वहां अचल संपत्ति या जमा-जमाया कारोबार है.

बंगाल के विभिन्न कारखानों में श्रमिक हड़ताल के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1995 में 33 मामले, 1996 में 17 मामले, 1997 में 29 मामले, 1998 में 25 मामले, 1999 में 34 मामले, 2000 में 27 मामले, 2001 में 20 मामले, 2002 में 30 मामले, 2003 में 32 मामले, 2004 में 20 मामले, 2005 में 26 मामले और 2006 में 24 मामले दर्ज किये गये. इस तरह 1995 से 2006 तक पांच बड़े क्षेत्रों -चाय, जूट, बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयों, छोटी इंजीनियरिंग इकाइयों और कपड़ा - में हड़ताल के 135 मामले और तालाबंदी के 1700 मामले दर्ज किये गये. यह आंकड़ा सभी उद्योगों में इस प्रकार है: हड़ताल के 317 मामले और तालाबंदी के 3317 मामले. राज्य में 1984 में 510, 1988 में 559, 1994 में 275 और 2002 में 205 और 2006 तक 136 पंजीकृत ट्रेड यूनियन थे.

स्रोत : इवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन वेस्ट बंगाल, रत्ना सेन

बंगाल में लॉक आउट लाभार्थियों (हर माह 500 रुपये) की संख्या

वर्ष	तालाबंद औद्योगिक इकाइयां	श्रमिकों की संख्या
1998-99	190	27595
1999-20	219	32941
2000-01	256	39809
2001-02	249	33580
2002-03	250	33860
2003-04	263	42729
2004-05	276	41977
2005-06	266	35220
2006-07	249	36631

स्रोत : लेबर इन वेस्ट बंगाल

सभी फोटो- प्रभात पाण्डेय

मेरी दुनिया.... मुशर्रफ़ का धमाका! ...धीर

फाउंडेशन ने स्थानीय नगरपालिका की सहायता से इन अप्रशिक्षित गाइड्स को समुचित प्रशिक्षण देना शुरू किया.

नवलगढ़ के ये गाइड...

शशि शेखर

मोरारका हवेली में बबलू शर्मा फर्राटेदार फ्रेंच और अंग्रेजी में पर्यटकों को हवेली के इतिहास से रूबरू करा रहा है. लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बबलू पढ़ा–लिखा नहीं है. ग़रीबी की वजह से स्कूल नहीं जा सका था. शुरू से ही दोस्तों के साथ नवलगढ़ आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ घूमता रहता. उन्हीं से थोड़ा–थोड़ा फ्रेंच सीखने लगा. अपने दोस्त मोहम्मद युनूस से अंग्रेजी सीखी. सालों तक घूमते–सीखते आज बबलू नवलगढ़ का एक जाना–माना टूरिस्ट गाइड बन चुका है. फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा पर उसका एक समान अधिकार है. बबलू की ही तरह शेर मोहम्मद को भी देख कर यह यक़ीन करना मुश्किल होता है कि पांचवी कक्षा तक पढ़ा शेर मोहम्मद इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है. पांचवी तक ही पढ़ा जावेद भी फ्रेंच बोल लेता है.

दरअसल पर्यटन, खास कर अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध नवलगढ़ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है. यहां हरेक साल क़रीब तीस हज़ार देशी–विदेशी पर्यटक आते है. ज़ाहिर है, इतने पर्यटकों के लिए गाइड की भी ज़रूरत होती है. चूंकि गाइड ही इन देशी–विदेशी पर्यटकों के लिए आंख और कान का काम करते हैं. इनके द्वारा दी गई सूचना से ही पर्यटक नवलगढ़ की विरासत को जानते और समझते हैं. बबलू, जावेद, शेर मोहम्मद जैसे स्थानीय युवक गाइड के रूप में काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल गाइड के लिए जो ढेर सारी योग्यताएं चाहिए, इनके पास उसकी कमी थी. कम पढ़े–लिखे इन युवकों के लिए कोई सरकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं थी और न ही इनके पास अपने संसाधन थे जिसकी मदद से वे ख़ुद को और बेहतर गाइड के रूप में तैयार कर सकें. इस कमी को पूरा करने और प्रोफेश्नल गाइड तैयार करने के लिए मोरारका फाउंडेशन ने इन युवकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की.

फाउंडेशन ने स्थानीय नगरपालिका की सहायता से इन अप्रशिक्षित गाइड्स को समुचित प्रशिक्षण देना शुरू किया. प्रशिक्षण के दौरान इन युवकों को स्थानीय हेरिटेज, होटल्स, स्मारक, पर्यटन और ट्रैवल व्यापार से जुड़े विशेषज्ञों की मदद से प्रशिक्षित किया. इस प्रशिक्षण शिविर में नवलगढ़ के लगभग सभी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित गाइड शामिल हुए. इसका लाभ यह हुआ कि इन युवकों को नवलगढ़ की सही–सही जानकारी के साथ पर्यटन के अन्य पहलुओं के बारे में भी जानने का मौक़ा मिला. आबिद नाम का एक गाइड कहता है कि इस प्रशिक्षण से न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि अब वह अधिकारपूर्वक पर्यटन से जुड़े विषयों पर पर्यटक को जानकारी देने में ख़ुद को सक्षम महसूस करता है. एक और गाइड मनोज शर्मा बताता है कि हेरिटेज की जानकारी तो मोरारका फांउडेशन पहले भी हेरिटेज संरक्षण शिविर के माध्यम से देता रहा है, पर पर्यटकों को ये जानकारियां किस तरह पूरी तहजीब और संस्कृति के साथ दी जाए, इसका पता इस गाइड प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ही चला.

प्रशिक्षण के अंत में इन युवकों को फाउंडेशन और नगरपालिका की ओर से एक प्रमाणपत्र भी दिया गया. चौथी दुनिया से बात करते हुए ये युवक कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात से ख़ुशी है कि इस प्रशिक्षण के बाद उनके सिर से अप्रशिक्षित का लेबल हमेशा–हमेशा के लिए हट गया है और अब वे ज़्यादा गर्व और अधिकार के साथ पर्यटकों को नवलगढ़ की विरासत से रूबरू करा सकेंगे.

shashishekhar@chauthiduniya.com

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

जैविक खेती से देशी प्रजाति को बढ़ावा मिला : मुकेश गुप्ता

मुकेश गुप्ता मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक होने के साथ–साथ जैविक खेती के विशेषज्ञ भी है. चौथी दुनिया संवाददाता *शशि शेखर* ने नवलगढ़ यात्रा के दौरान मुकेश गुप्ता से जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की. मसलन, किसानों को अपनी जैविक उपज के लिए बाज़ार कैसे मिले? कृषि के लिए जैविक खेती कैसे वरदान साबित हो रहा है? पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

मुकेश जी, सबसे पहले तो आप जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताएं.

देखिए, जैविक खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ है कि देशी प्रजाति के अनाज की खेती को बढ़ावा मिला है. अब तक आम किसान संकर किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैविक खेती करने वाले किसानों ने बेहतर परिणाम के लिए फिर से देशी किस्म के अनाजों का उत्पादन करना शुरु कर दिया. इसके अलावा, जैविक अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फ़ायदेमंद होता है. अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अब लोग मोटे अनाज की ओर आकर्षित हुए हैं. जैविक अनाज की शुद्धता और स्वाद का कोई जोड़ नहीं है और यह अनाज पेट के रोगों के लिए खासा कारगर साबित हुआ है. वैसे ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी मोटा अनाज फ़ायदेमंद साबित हुआ है.

किसानों को अपनी उपज के लिए बाज़ार मिले, इसके लिए आप लोग क्या सहायता देते हैं?

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में हमारा फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है. जो भी किसान जैविक विधि से खेती करते हैं, पहले उनके उत्पादों का सर्टिफिकेशन किया जाता है. इसक अर्थ है कि यह उत्पाद जैविक हैं. यह काम कुछ मान्यता प्राप्त एजेंसियां करती हैं. हमारी फाउंडेशन के भी देश भर में कई जगह डाउन टू अर्थ नाम से रिटेल आउटलेट्स हैं, जहां जैविक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होता है. इन आउटलेट्स के ज़रिए भी हम किसानों को बाज़ार उपलब्ध करा देते हैं. इसके अलावा, किसान ख़ुद भी अपनी उपज मंडी में जा कर बेचता है. मैं आपको बता दूं कि जब किसान मंडी में जा कर यह बताता है कि उसका अनाज जैविक विधि से उगाया गया है, तो ख़रीददार उस अनाज को ज़्यादा दाम दे कर ख़रीदता है.

जैविक उत्पाद की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में बताएं.

देखिए, जैसा मैंने बताया कि देश के कई अलग–अलग जगहों पर हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, डाउन टू अर्थ नाम से. इसका पता हमारी वेबसाइट www.downtoearthorganic.com पर उपलब्ध है. इसके अलावा हम अपने आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी भी देते हैं. साथ ही, हमने नेचर्स बास्केट और फूड बाज़ार से भी समझौता किया हुआ है. इनके आउटलेटस पर भी हमारे किसानों द्वारा पैदा किए गए जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं.

आने वाले समय में जैविक खेती का आप क्या भविष्य देखते हैं और आगे की क्या योजना है?

देखिए, आने वाला वक़्त जैविक खेती का ही है. यह बात अब धीरे–धीरे किसानों को समझ में आ गई है. रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है, यह हमारे किसान भाई अच्छी तरह समझ चुके हैं. अब तक हमारे फाउंडेशन के साथ क़रीब 10 लाख किसान जुड़ चुके है. मतलब दस लाख किसान क़रीब 11 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर जैविक खेती कर रहे है. आने वाले कुछ सालों में हम इस संख्या को और बढ़ाएंगे. हमारी कोशिश होगी कि अगले कुछ सालों में हमारे साथ 20 से 30 लाख किसान और जुड़े.

इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करें

वी.बी. बापना
महा प्रबंधक

मोरारका फाउंडेशन, वाटिका रोड, जयपुर–302015
मोबाइल–09414063458
ईमेल–vbmorarka@yahoo.com.

तालिबान से सहयोग और चीन को खाड़ी तक पहुंचने में मदद करना, ये दो ऐसी बातें हैं जो साबित करती हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त नहीं है.

इंसाफ़ का मंदिर

मेघनाद देसाई

उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार शकील बदायूंनी का लिखा एक गीत है, इंसाफ़ का मंदिर है, ये भगवान का घर है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए मैं बदायूंनी के इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा. अयोध्या मामले में अदालत ने न्याय का बेहतरीन तरीक़ा निकाला, जिसके बारे में कम ही लोगों ने उम्मीद की होगी. यहां मुद्दा विवादित ज़मीन को तीन हिस्सों में बांटने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे अदालत ने जो तर्क दिए हैं, वह ज़्यादा अहम है. हाई कोर्ट के तीनों जजों सुधीर अग्रवाल, डी वी शर्मा और एस यू ख़ान ने यह माना कि 1857 से पहले तक इस ज़मीन का इस्तेमाल दोनों समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा किया जाता था. हालांकि, इस मुद्दे पर तीनों जजों में मतैक्य नहीं है, लेकिन फ़ैसले में उन्होंने माना कि मस्जिद बनने से पहले वहां किसी मंदिर का वजूद नहीं था, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों की परंपरागत आस्था को तवज्जो देते हुए उन्होंने यह भी माना कि भगवान राम का जन्म स्थान गुंबद के आसपास स्थित है. इस विश्वास का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि राम के जीवन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. इस मामले में राम और बुद्ध बिलकुल अलग हैं, क्योंकि बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई चीजें, जैसे कैंडी और हजरतबल में मिले उनके दांत, हमारे पास मौजूद हैं. इतिहास के नज़रिए से राम का चाहे जो भी अस्तित्व हो, लेकिन अयोध्या मामले में वह अपीलकर्ताओं में शामिल हैं और उनका क़ानूनी वजूद है. तीनों जजों का यह तर्क काफी अहम है कि न तो अखाड़ा और न ही वक़्फ़ बोर्ड एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए ज़रूरी कोई सबूत पेश कर सकते हैं. इसके साथ यदि हम इस बात को जोड़कर देखें कि 1857 से पहले दोनों समुदाय इस ज़मीन का मिलकर इस्तेमाल करते थे तो मुक़दमे के सार्वभौमिक फ़ैसले की ज़मीन तैयार हो जाती है और जजों ने ऐसा ही किया. सोलोमन के फ़ैसले के विपरीत जिसमें विवादित बच्चे को दोनों पक्षों के बीच काट कर बांटने की व्यवस्था दी गई थी, अयोध्या मामले में ज़मीन का बंटवारा किया जाना है और इससे किसी की शारीरिक हानि नहीं होती. मुझे क़ानून की उतनी ही समझ है जितना मैंने

अख़बारों में पढ़ा है, लेकिन मेरी सीमित समझ में यह बुद्धिमानी भरा फ़ैसला है. क़ानून के लिहाज़ से यह तर्कसंगत है या नहीं, यह मैं नहीं बता सकता.

राम के जन्म की वास्तविक तिथि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सत्य है कि उसके बाद और यहां तक कि 1528 के बाद से अब तक भारत में काफी कुछ बदल चुका है. अंग्रेज़ों की बनाई क़ानून व्यवस्था, जो क्रिकेट के अलावा उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपहार है, के प्रति हम कुछ ज़्यादा ही आसक्त हैं. इस विवादित मुद्दे की शुरुआत से लेकर आज तक किसी ने इस क़ानून की प्रासंगिकता पर कोई सवाल खड़े नहीं किए. हद तो यह है कि सभी संबद्ध पक्ष इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के पक्ष में हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी इससे अच्छा कोई समाधान हो सकता है. मुसलमानों को इस विवादित ज़मीन से बलपूर्वक और ज़बरदस्ती बेदख़ल किया गया था और उनके लिए ख़ुशी की बात यह है कि अब वहां एक नई मस्जिद बन सकती है. विवादित ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए हिंदुओं के दावे का कोई क़ानूनी सबूत नहीं है, यह उनकी आस्था से जुड़ा मुद्दा है. अदालत का यह फ़ैसला उनके लिए प्रसन्नता की बात है क्योंकि इसमें उनके पौराणिक विश्वास को तरजीह दी गई है. अखाड़ा के लिए भी यह फ़ैसला अच्छा है क्योंकि विवादित ज़मीन पर उसके दावे को वक़्फ़ बोर्ड के दावे के समान ही अहमियत दी गई. अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है. अब समय आ चुका है कि सरकार निष्पक्षता के अपने चोले को उतार फेंके और मामले को अपने हाथ में ले. सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील का चाहे जो भी फ़ैसला हो, लेकिन उसे तत्काल ज़मीन के बंटवारे के लिए सभी विकल्पों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए. 1970 के दशक के दिनों से ही मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि अयोध्या में विवादित ज़मीन पर सभी धर्मों के लिए सामूहिक धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाए. क़रीब-क़रीब यही बात अब अदालत ने भी कह दी है. सरकार को इसके डिज़ाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा करनी चाहिए. इस डिज़ाइन में एक-एक मंदिर और मस्जिद के अलावा निर्मोही अखाड़ा के इच्छानुरूप संरचना के लिए भी व्यवस्था हो. नए भारत के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है. सरकार को मंदिर और मस्जिद के लिए निजी आर्थिक सहयोग भी आमंत्रित करना चाहिए. यह डिज़ाइन ऐसा हो जिसमें भारत की सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्षता की झलक हो. यह एक अच्छा संयोग है कि देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष हिंदू या इस्लाम धर्म से जुड़े नहीं हैं. यह एक अच्छा मौक़ा है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. इज़रायल का जेरूसलम तीन धर्मों, यहूदी, इसाई और इस्लाम का केंद्र स्थल है. अयोध्या भी जेरूसलम की तरह हो सकता है और हम इसके ज़रिए भारत के लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष नज़रिए का उदाहरण पेश कर सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चीन पर चले चाबुक

वर्ष 1962 में दिए गए नारे हिंदी चीनी भाई-भाई के बाद भी चीन का भारत के प्रति धोखेबाज़ी का रवैया कायम है. कश्मीर, दलाई लामा और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर वह भारत को जब तब झटका देता रहता है, जबकि भारत ने हमेशा तिबब्त और ताइवान के मुद्दों पर चीन की नीतियों का समर्थन किया है. अब भारत को भी चाहिए कि कूटनीतिक चाबुक से चीन को यह एहसास करा दे कि हम किसी से कम नहीं हैं.

भारत द्वारा चीन के नहले पर दिया गया दहला सुकून भरा है. जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बी एस जसवाल को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार के बाद भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में चीन के साथ हर तरह का सहयोग स्थगित कर दिया है. इसी कड़ी में तीन चीनी सैन्य अधिकारियों को भारतीय वीजा देने से मना कर दिया गया है. ग़ौरतलब है कि जनरल बी.एस. जसवाल को एक उच्चस्तरीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत चीन दौरे पर जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात होने के कारण चीन ने उनको वीजा देने से इंकार कर दिया. तत्पश्चात विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत झांग येन को तलब कर कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 25 मिनट तक हुई बातचीत में येन से कहा गया कि जसवाल की यात्रा को लेकर बीजिंग का कड़ा रुख़ अनुचित है. दरअसल पिछले कुछ सप्ताहों से चीनी अधिकारियों से छोटे-मोटे मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था. नतीजा भारत ने फ़िलहाल रक्षा क्षेत्र में चीन के साथ हर तरह का आदान-प्रदान स्थगित करने का निर्णय लिया है. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व बहुमुखी रिश्ता है. रक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारा आपसी सहयोग बढ़ रहा है. फिर भी, समय समय पर रिश्ते की समीक्षा आवश्यक है. चीन के रवैये पर विपक्ष की टिप्पणी तो अपेक्षा के अनुरूप ही है, साथ ही सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी चीन के रुख़ की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि रिश्ते आपसी आत्मसम्मान की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं और एक-दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बीते जुलाई माह में भारत आए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा था कि चीन, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बैठक में चीन के दल ने कहा कि पड़ोसियों में भेदभाव करना हमारी विदेश नीति के ख़िलाफ़ है. पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के महानिदेशक और दल के नेता ल्यु मिंगपो ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मज़बूत करने की नीति पर चलेंगे. इसी बैठक में भारत के पूर्व विदेश सचिव एम के रसगोत्रा ने कहा कि भारत भी चीन के साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन यह भारत के हितों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थक नीति भारत के लिए भारी चिंता का विषय है. इसी दरम्यान चीनी दूतावास के काउंसलर ची फिंग ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों के महत्व को देखते हुए ही पार्टी का उच्च स्तरीय दल यहां आया है, ताकि भारतीयों के साथ विचारों का खुला आदान-प्रदान हो सके. यदि चीनी नेताओं के इन वक्तव्यों की समीक्षा यहां करें तो स्पष्ट हो जाएगा की भारत के प्रति उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है. ताज़ा उदाहरण के तौर पर जसवाल के वीजा प्रकरण तथा पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में लगभग 11 हज़ार चीनी सैनिक तैनात

हैं. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन को कश्मीर के इस इलाके का वास्तविक नियंत्रण सौंप रहा है. गिलगिट बल्टिस्तान का यह इलाक़ा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि यहां के लोग पाकिस्तानी क़ब्ज़े का विरोध कर रहे हैं. इन इलाकों में चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है. चीन यहां हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछा कर खाड़ी देशों तक पहुंचने की कोशिश में है.

तालिबान से सहयोग और चीन को खाड़ी तक पहुंचने में मदद करना, ये दो ऐसी बातें हैं जो साबित करती हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त नहीं है. गिलगिट बल्टिस्तान में दो महत्वपूर्ण नई बातें हुई हैं. पहली वहां पाकिस्तान शासन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त विद्रोह सुलग रहा है और दूसरी यह कि वहां चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सात हज़ार से ग्यारह हज़ार सैनिकों की घुसपैठ हो गई है. यह इलाक़ा दुनिया भर से कटा हुआ है. जानकार बताते हैं कि पेइचिंग इन रास्तों से पूर्वी चीन से बलूचिस्तान के गवादार, पासनी और ओरमरा में चीन द्वारा हाल ही में बनाए गए पाकिस्तानी नौसेना अड्डों पर ज़रूरी सामान और ऑयल टैंकर पहुंचाएगा. ये इलाक़े खाड़ी क्षेत्र से महज 84 घंटों की दूरी पर हैं. ड्रैगन ने भारत के साथ हमेशा ऐसे पड़ोसी की भूमिका निभाई है जो भारत का नुकसान ही करता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उसे झुकने में भी दिक्कत नहीं है. इसे भारत की दरियादिली ही कहेंगे कि तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद 2010 में चीन और भारत के बीच व्यापार क़रीब 331 करोड़ रुपये का हो गया है. चीन को अपने उत्पाद खपाने के लिए भारतीय बाज़ार की ज़रूरत है. चीन से आए मज़दूर भारत में कई परियोजनाओं में काम कर रहे हैं. चीन के कई बार कहने के बाद भारत ने जुलाई 2010 में बीजिंग दूतावास में आर्थिक शाखा का अलग से गठन किया. दोनों के बीच रोहतांग दर्रे से होकर भी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने का समझौता हो चुका है. हालांकि चीन, तिब्बत व ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वहां स्वतंत्रता को लेकर सालों से चीन विरोधी आंदोलन चल रहा है. इसके बावजूद भारत ने हमेशा तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना है, जबकि चीन को भारत में मेहमान के तौर पर रह रहे धार्मिक नेता दलाई लामा से भी दिक्कत है. चीन भारत के अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताता है. 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर रखा है. चीन के पास 5180 वर्ग किलोमीटर का कश्मीर का वह हिस्सा भी है, जो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दिया था. चीनी सेनाएं भारतीय सीमा में कई बार प्रवेश कर चुकी हैं. 16 जून 2008 को चीनी सेना के जवान सिक्किम सीमा से भारत में घुस आए थे. भारत और चीन के बीच 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा है. आश्चर्य इस बात का है कि चीन ने 2007 में अरुणाचल प्रदेश के आईएएस को चीन आने का वीजा नहीं दिया था. चीन का कहना था कि अपने ही देश में आने के लिए वीजा की क्या ज़रूरत है? चीन का कश्मीर के मामले में भी हमेशा भारत विरोधी रवैया रहा है और उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है. चीन ने पिछले साल मनमोहन सिंह के अरुणाचल प्रदेश जाने पर एतराज़ जताया था. उसका तर्क था कि यह विवादित क्षेत्र है और भारतीय प्रधानमंत्री को वहां जाकर दोनों देशों के बीच के सौहार्द्र को नहीं बिगाड़ना चाहिए. दलाई लामा के भी अरुणाचल जाने पर विरोध किया था. अपने देश के किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के जाने पर दूसरे देश की आपत्ति, चोरी और सीनाज़ोरी का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा. चीन का आरोप है कि भारत ने उसके क़रीब 90 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क़ब्ज़ा जमा रखा है, जिसका अधिकांश हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है. हक़ीक़त यह है कि ख़ुद चीन ने भारत के जम्मू कश्मीर सेक्टर में ही क़रीब 43 हज़ार वर्ग किलोमीटर भू भाग पर क़ब्ज़ा जमाया हुआ है.

यह हमारी पारंपरिक प्रेम सौहार्द्र वाली नीति ही है कि भारत को कभी भी राष्ट्रीय हितों को लेकर उग्र नीति अपनाने वाले देशों में नहीं गिना गया. इससे यह डर लगता है कि अन्य राष्ट्रों के बीच हमारी छवि कमज़ोर देश की न बन जाए, जो अपने हितों की रक्षा करने में भी ढुलमुल रवैया अपनाता है. आजतक हमें अपने हितों की पैरवी के लिए आक्रामक रुख़ अपनाते नहीं देखा गया, जबकि चीन को अपने हितों पर चोट पहुंचाने वाले किसी भी मामले पर उग्र रूप अपनाने वाले देशों में गिना जाता है. हम जब तक शक्तिशाली राष्ट्र की तरह से पेश आना नहीं सीखेंगे, ऐसे प्रश्नों से दो चार होना ही पड़ेगा. हमें न सिर्फ़ अपनी ताक़त पर भरोसा करना सीखना होगा, बल्कि इस सच्चाई को समझना होगा कि वर्तमान हालात में कोई भी राष्ट्र किसी ख़र्चीले युद्ध में नहीं फंसना चाहता है. चीन तो फिर भी आर्थिक महाशक्ति बनाने की कोशिश में लगा है. उस पर वह भारत के विशाल बाज़ार को छोड़ने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता है. ऐसे में हमें अपने हितों पर कठोर रुख़ अपनाने की ज़रुरत है.

राजीव रंजन तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

सरकार और जनता सबक ले

सद्भाव की मिसाल लालगोपालगंज आलेख पढ़कर खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ. जहां देश में अयोध्या विवाद की वजह से हिंदू-मुस्लिम के बीच तनाव की ख़बर फैल रही है, ऐसे में इस तरह का आलेख काफी संतोष पहुंचाता है. जिस तरह इस कस्बे में मुसलमान आपसी विवाद को भुलाकर सौहार्द्र की भावना से रहते हैं, देश की जनता और सरकार को इससे सबक लेना चाहिए.

–रवीश झा, *पटना*

उम्मीद की किरण

अपनी दुनिया में नवलगढ़ के आलेख का हर सप्ताह इंतज़ार रहता है. इनमें भारत के असल गांवों की तस्वीर झलकती है. दूरदराज के क्षेत्रों में लोग आत्मनिर्भरता की मिशाल पेश कर रहे हैं, वह हमें प्रोत्साहित करता है. हालांकि इस निर्भरता के प्रयास में मोरारका फाउंडेशन का सहयोग भी सराहनीय है. आशा है कि आगे भी इसी तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े लेख पढ़ने को मिलेंगे.

–एस बी यादव, *मौदहा, हमीरपुर*

ईमानदार प्रयास है

चौथी दुनिया की आवरण कथा कश्मीरियों के सर पर गोली मत मारो पढ़ा. लगा कि यह अख़बार सच्ची समाजसेवा की भावना और ईमानदारी से चल रहा है. वहीं दूसरे अख़बार इन विषयों पर राजनीतिक पक्षधरता के शिकार होकर रह जाते हैं. चौथी दुनिया की यह पहल सचमुच तारीफ़ करने लायक़ है.

–अरुण *(ईमेल से)*

सिर्फ महंगाई ही मुद्दा है?

पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत समेत रायपुर के नवनिर्मित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की. लगभग दो घंटों तक पत्रकारों से बातचीत में केवल उन्होंने मंहगाई को लेकर केंद्र सरकार को कोसा और एक दो रुपये में चावल देने के लिए अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के तारीफ़ों के पुल बांधे. मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यहां महंगाई के अलावा कोई और समस्या नहीं है?

–योगेश मिश्रा, *कटागी, रायपुर*

चौ. अजीत सिंह की राजनीति

अजीत सिंह का साक्षात्कार पढ़ा, ऐसा लगा कि वो सवालों का सीधा-सीधा जवाब नहीं देना चाहते. इनकी राजनीति का मूल आधार किसान ही हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी जमाखर्च के अलावा अजीत सिंह ने किसानों की भलाई के लिए कोई ठोस संघर्ष किया हो, ऐसा नहीं दिखता. जैसा कि उन्होंने इस साक्षात्कार में अपनी राजनीतिक लड़ाई के बारे में बताया है, अगर वो सचमुच ऐसा करते हैं तो यह बेहद खुशी की बात है.

–डॉ सुरेंद्र गुप्ता, *मुजफ्फरनगर*

बाघों की सुरक्षा पर गंभीर हो सरकार

उत्तराखंड में बाघों को बचाने के लिए कई बार मुहिम छेड़ी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. यहां बाघों का इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है. ऐसे में सरकार को सख्त होना पड़ेगा. लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सरकार के जागने तक बाघ पूरी तरह से खत्म हो जाएं.

–कमलेश पासवान, *नैनीताल (उत्तराखंड)*

राहुल गांधी की आंधी रंग लाएगी

बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों की जोड़तोड़ जारी है. यहां एक तरफ हवा नीतीश के पक्ष में है, वहीं सबकी नज़र राहुल गांधी की आंधी पर भी है. लेकिन जातिगत आधार पर रातोंरात हवा का रुख बदलते भी देखा गया है. क्या होगा, कहना मुश्किल है, मगर साफ है कि नीतीश ने अगर अपने वादे पूरे किए हैं, तो किसी भी दल की नहीं चलेगी.

–प्रवीण सिंह, *कहलगांव (बिहार)*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

सुदूर इलाक़ों से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपनी नाकामयाबी से सरकार अपने लोकतांत्रिक चरित्र पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार रही है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कश्मीरियों का दिल जीतने की ज़रूरत

इस बार की हिंसा इतने दिनों तक इसलिए चली, क्योंकि लगातार लोगों की मौत हो रही थी. मौत की वजह से लोग सड़क पर उतरते और सरकार कर्फ्यू लगा देती. विरोध उग्र प्रदर्शन में तब्दील होता रहा और सरकार उसे दबाने के लिए ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल करती रही. जनता और सरकार के बीच नफ़रत और अविश्वसनीयता की गहरी खाई पैदा हो गई. उमर अब्दुल्ला के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह विधानसभा में हंगामा किया, उससे तो यही लगता है कि वह कश्मीर में शांति बहाल होने के ख़िलाफ़ है. यह बात समझने की है कि कश्मीर के लोगों और अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा फ़र्क़ है. दूसरे राज्यों में रहने वालों के पास कोई पसंद नहीं थी. कश्मीर भारत में स्वेच्छा से शामिल हुआ. काफ़ी दिनों तक कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे. भारत में उसका विलय शर्तों के साथ हुआ था. आज कश्मीरियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ख़राब है तो उन्हें लगता है कि भारत से मिलकर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. यह फ़र्क़ हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए. उन्हें यह भी लगता है कि आख़िर क्या वजह है कि उनसे सटा हुआ पंजाब हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य है, लेकिन उसके बाहर आते ही जम्मू-कश्मीर में ग़रीबी नज़र आती है. कश्मीर के लोगों का दर्द क्या है, यह हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है.

कश्मीर आज भी भारत के दूसरे इलाक़ों से कटा हुआ है. आप किसी भी रेलवे स्टेशन जाएं, आपको हर प्रदेश का नागरिक मिल जाएगा. केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र यानी सब जगह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कश्मीरी नहीं मिलते. अब हमने इस पहेली को किसी तरह समझने की कोशिश की है. ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ग़रीबी नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि लोग रोज़ी-रोटी के लिए बाहर निकलना नहीं चाहते. दरअसल हम लोगों ने कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि वे अपनी रोज़ी-रोटी के लिए वहां से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते.

हम आपको 1991 में माले में हुए सार्क सम्मेलन की एक घटना बताते हैं. मंच पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ बैठे थे. भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें देखते ही कहा कि आजकल आप भारत के ख़िलाफ़ बहुत बयान दे रहे हैं, हर जगह कश्मीर मामले को उठा देते हैं. नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हमें कश्मीर दे दीजिए तो हम भारत के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर देंगे. चंद्रशेखर जी उन्हें अपने कमरे में लेकर आए और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि आपको फिर देश के सारे मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान जाना होगा. नवाज शरीफ भी दंग रह गए. चंद्रशेखर जी ने कहा कि जिस तर्क पर आप कश्मीर लेने की बात करते हैं, वही तर्क भारत के हर शहर और गांव में लगा दिया जाए तो हमारे देश में किसी भी जगह मुसलमान नहीं रह पाएंगे. उन्हें वहां से भगा दिया जाएगा. नवाज़ शरीफ़ चुप हो गए. इस घटना के बाद नवाज़ शरीफ़ कश्मीर के मामले में बयानबाजी से परहेज़ करने लगे.

कश्मीर हिंदुस्तान के लिए किसी ज़मीन का एक टुकड़ा भर नहीं है. यह भारत के संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय सहिष्णुता की परीक्षा ले रहा है. जहां तक हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की बात है, अगर हम कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकते तो बिहार के किसी शहर में धर्मनिरपेक्ष कैसे रह सकते हैं. कश्मीर का सवाल हिंदुस्तान के पंद्रह करोड़ मुसलमानों का सवाल है. कश्मीर का सवाल भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का सवाल है, सामाजिक संरचना की बुनियाद का सवाल है. ठीक उसी तरह, जैसे पंजाब और हरियाणा का विकास हो और बिहार एवं उड़ीसा का न हो. अगर ऐसा होगा तो नक्सलवाद जैसा आंदोलन होना तय है.

कश्मीर आज भी भारत के दूसरे इलाक़ों से कटा हुआ है. आप किसी भी रेलवे स्टेशन जाएं, आपको हर प्रदेश का नागरिक मिल जाएगा. केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र यानी सब जगह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कश्मीरी नहीं मिलते. अब हमने इस पहेली को किसी तरह समझने की कोशिश की है. ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ग़रीबी नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि लोग रोज़ी-रोटी के लिए बाहर निकलना नहीं चाहते.

कश्मीर की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि हिंसा, बंद और हड़ताल से लोग परेशान हैं और वे हुर्रियत की अपील को नज़रअंदाज़ करने लगे हैं. सब यही चाहते हैं कि जैसी स्थिति है, बस वही बनी रहे और हिंसा का दौर ख़त्म हो. हुर्रियत के तेवर भी अब नरम हो गए हैं, सड़कों पर वाहन आने-जाने लगे हैं, सख्ती का माहौल ख़त्म हो गया है और रिहायशी इलाक़ों से पुलिस चौकियां हटाई जा रही हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला के प्रति आम कश्मीरी का विश्वास बढ़ा है. ऐसे में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सामने एक सुनहरा मौक़ा है, जबकि कश्मीरी अवाम का दिल जीता जा सकता है. लोगों को तुरंत किसी समाधान की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन सब यही चाहते हैं कि सरकार समाधान निकालने के लिए कोई पहल ज़रूर करे. इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा यह कि सरकार को वक़्त भी मिल जाएगा. सरकार को कुछ बिंदुओं पर तुरंत अमल करना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसी भी क़ीमत पर हिंसा न हो. करीब साठ युवकों को पिछले दिनों पत्थर चलाने के जुर्म में जेल भेजा गया, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता का रोष ख़त्म हो. और जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारीजनों को घोषित किया गया पांच-पांच लाख रुपये का मुआवज़ा तुरंत देने की व्यवस्था हो. इसके अलावा सरकार ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बदलाव करने का वादा किया है, उस पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है. ये विषय ऐसे हैं, जिन पर कश्मीर के लोगों की निगाह टिकी है. इन सारी चीजों पर सरकार कब अमल करती है, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं. सरकार जितनी जल्दी इन मामलों को निपटाएगी, लोगों का गुस्सा उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सरकार की तरफ़ से अक्टूबर महीने में परीक्षाएं देने की छूट दी गई है. ऐसा ही कुछ नवंबर और दिसंबर में भी करना होगा, ताकि जनता को लगे कि सरकार ज़रूरी कामकाज के साथ-साथ समस्या का हल निकालने के प्रति भी सजग है. सरकार का यह पहला काम होना चाहिए कि वह अपने आचरण से कश्मीर की जनता में नेतृत्व और अपनी साख मज़बूत करे. इसके बाद हुर्रियत की मांगों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी. हुर्रियत ने अपना जो पांच सूत्रीय कार्यक्रम दिया था, उसमें आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, आटोनॉमी, मानवाधिकार, नौजवानों की रिहाई और सार्वजनिक सुरक्षा आदि शामिल हैं. सरकार अगर कश्मीर में अमन-चैन स्थापित करने की कोशिश करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह पहले कश्मीर के लोगों का दिल जीते.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मीडिया की भूमिका को समझे सरकार

सियालकोट में हुई नरसंहार की घटना अपने नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में पाकिस्तान सरकार की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डालने के वीभत्स दृश्य हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से भले दूर हो गए हैं, लेकिन दु:स्वप्न का सिलसिला अभी रुका नहीं है. मामले का मुख्य आरोपी और स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ का अभी तक कोई सुराग़ नहीं मिल पाया है. हैरत की बात तो यह है कि जिस मीडियाकर्मी ने इस घटना को दुनिया के सामने लाया, उसकी कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. भीड़ के इस दुष्कृत्य के बाद निजी टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर हाफिज़ इमरान पर हुआ यह हमला सरकार एवं क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के नकारा रवैये और उनकी अक्षमता के बारे में बताता है. इमरान के साथ जो कुछ भी हुआ, वह और भी शर्मनाक है क्योंकि उसने संबंधित अधिकारियों को पहले ही इस बाबत बता दिया था. ख़बर प्रसारित होने के बाद से उसे हत्या की धमकियां मिल रही थी और उसने गुजरावाला एवं सियालकोट के पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी. गृह मंत्री रहमान मलिक ने भी इमरान सहित सियालकोट के सभी पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर इमरान और उसके साथ गए कैमरामैन को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था. सरकार ने आश्वासन तो ख़ूब दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकारी तंत्र इमरान की सुरक्षा में नाकामयाब रहा. यह बहुत बड़ी विफलता है. सरकार के इस बयान में थोड़ी-बहुत सच्चाई ज़रूर है कि आत्मघाती हमलों का शिकार बन रहे हज़ारों की भीड़ वाले धार्मिक प्रदर्शनों को पूरी तरह चाक-चौबंद सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं है. पूरे देश में धार्मिक

मीडिया और सरकार के बीच के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि मीडिया का काम ही है सरकारी कामकाज पर नज़र रखना. लेकिन वह सरकार को लोगों की समस्याओं, उनकी भावनाओं और उनकी मांगों से भी अवगत कराने का काम करता है और यह मौक़ा उपलब्ध कराता है कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप काम करे.

अल्पसंख्यकों के पूजा स्थानों को सुरक्षित रखने में भी तमाम समस्याएं हैं. इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि निचले स्तर के पुलिस अधिकारी, जो प्रशिक्षित तक नहीं हैं, भ्रष्टाचार और हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देते हैं. लेकिन अन्याय को सतह पर लाने वाले एक अकेले नागरिक को सुरक्षित रखने में सरकार की नाकामयाबी समझ से परे और बेहद शर्मनाक है. इमरान का मीडिया से जुड़ा होना मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बनाता है, क्योंकि इससे ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे जो अन्याय और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं.

इमरान की सुरक्षा के प्रति अधिकारियों का रवैया यह दर्शाता है कि सरकार राज्य और मीडिया के बीच के रिश्ते को पूरी तरह नहीं समझती है. आतंकी हमलों और बाढ़ जैसी विभीषिकाओं के इस माहौल में जब सरकारी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है, मीडिया ज़मीनी स्तर पर सरकार के लिए आंख और कान के रूप में काम कर सकता है. भ्रष्ट अधिकारियों और अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे राजनीतिज्ञों की मौजूदगी के चलते ऐसा होना ज़रूरी भी है. हाल के दिनों में मीडिया ने जिस ख़ूबी से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, उसकी प्रशंसा किए बग़ैर नहीं रहा जा सकता. सियालकोट की इस वारदात को प्रकाश में लाकर इसने पाकिस्तान में भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर किया तो स्वात में लोगों की ख़राब हालत पर से भी पर्दा उठाया. स्वात से जुड़े वीडियो फुटेज ने तो आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के नज़रिए में बदलाव ला दिया. 2005 में आए भूकंप और इस साल बाढ़ के दौरान मीडिया ने प्रभावित इलाक़ों की पहचान में मदद की, राहतकर्मियों को पीड़ित लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ और राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के मामलों को भी प्रकाश में लाने का काम किया. फिर भी, सरकारी अधिकारी यह नहीं समझते कि मीडिया उनकी ज़िम्मेदारियों के समुचित निर्वहन में कितना कारगर हो सकता है. इमरान पर हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री फिरदौस आशिक अवां ने उसे सस्ती लोकप्रियता के पीछे भागने वाला घोषित कर दिया. पत्रकारों की आलोचना करने वाली वह अकेली नहीं हैं, सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदस्यों ने कई बार मीडियाकर्मियों को अपने निशाने पर लिया है. कभी उन्हें इजरायल का एजेंट बताया जाता है, कभी निजी टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी जाती है तो कभी सेंसरशिप को बढ़ावा देने वाले क़ानून बनाए जाते हैं.

मीडिया और सरकार के बीच के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि मीडिया का काम ही है सरकारी कामकाज पर नज़र रखना. लेकिन वह सरकार को लोगों की समस्याओं, उनकी भावनाओं और उनकी मांगों से भी अवगत कराने का काम करता है और यह मौक़ा उपलब्ध कराता है कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप काम करे. पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि सरकार मीडिया का एक पहलू ही देखती है, इस ओर ध्यान नहीं देती कि वह उसकी आंख और कान भी हो सकता है. बहरहाल, सुदूर इलाक़ों से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में अपनी नाकामयाबी से सरकार अपने लोकतांत्रिक चरित्र पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार रही है. आख़िर, स्वतंत्र मीडिया सच्चे लोकतंत्र का एक आवश्यक पहलू है, लेकिन जब मीडियाकर्मियों को डराया-धमकाया जाए, उन पर हमले किए जाएं तो यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है. यही वजह है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स, 2009 की रिपोर्ट में 175 देशों के बीच पाकिस्तान को 159वां स्थान मिला है. इमरान पर हमले की घटना के बाद पंजाब के क़ानून मंत्री राजा सनाउल्लाह ने जोर देकर कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए. लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं कि इसका मतलब मीडिया को अधिकारसंपन्न बनाने के साथ-साथ मीडियाकर्मियों सुरक्षा प्रदान करना भी है. अब वह समय आ चुका है कि सरकार पत्रकारों की अहमियत को समझे, उनके काम को तवज्जो दे. इसकी वजह केवल यही नहीं है कि मीडिया सरकार की आंख और कान हो सकता है, बल्कि आम नागरिक भी आज सिटीजन जर्नलिस्ट बनता जा रहा है. लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि पत्रकारिता के प्रति सम्मान की संस्कृति का विकास हो. सरकार यदि ऐसा नहीं करती तो देश की आवाज़ को दबाने का ख़तरा पैदा हो सकता है.

हुमा युसुफ
feedback@chauthiduniya.com
(लेखिका पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं)

हर भाषा को बोलने का अपना एक तरीका होता है. उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलते समय वाक्य के अंत में जोर दिया जाता है, लेकिन हिंदी में यह उल्टा होता है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

पाठकों के पत्र, समस्या और सुझाव

शहर हो या गांव, सड़क की खुदाई एक आम समस्या है. कभी बिजली वाले, कभी जल विभाग तो कभी टेलीफोन वाले आकर आपके मुहल्ले की सड़क या मुख्य मार्ग की खुदाई कर देते हैं. फिर महीनों, कभी-कभी तो सालों तक उस सड़क को यूं ही छोड़ दिया जाता है या थोड़ी-बहुत मिट्टी डालकर अपनी लापरवाही ढक दी जाती है और फिर एक लंबे समय तक उस सड़क की मरम्मत नहीं होती. ज़ाहिर है, एक ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप यह सब ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आख़िर बार-बार होने वाले इस मर्ज की दवा क्या है? इस अंक में हम एक ऐसे आरटीआई आवेदन का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने सवालों का जवाब पाने के लिए कर सकते हैं. इस आवेदन के इस्तेमाल से आप अपने क्षेत्र के सड़कों की खुदाई और उनकी मरम्मत के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं. मसलन, सड़क क्यों काटी गई? काटी गई सड़क की मरम्मत के लिए क्या संबंधित एजेंसी ने पैसा जमा कराया था या नहीं? अगर हां, तो अब तक मरम्मत क्यों नहीं हुई? इसके अलावा इस अंक में हम अपने पाठकों के कुछ पत्र भी शामिल कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पाठकों के पत्र से भी लाभांवित होंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों के पत्र

बैंक वाले परेशान कर रहे हैं

मुझे पीएनबी से एक लाख 20 हज़ार रुपये का लोन मिलना था, लेकिन 45 हज़ार रुपये देने के बाद बैंक वालों ने कहा कि आपको इतना ही लोन स्वीकृत हुआ था. मैंने हर जगह इसकी शिक़ायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने सूचना क़ानून के तहत अपना आवेदन पीएनबी मुख्यालय दिल्ली भेज दिया. प्रथम अपील कहां करूंगा?

-सलीमुद्दीन, *मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.*

आप अपना आवेदन स्थानीय शाखा के लोक सूचना अधिकारी के पास भी भेज सकते थे. आप पता करें कि जहां से आपको लोन मिला है, वहां का पीआईओ (लोक सूचना अधिकारी) कौन है. बहरहाल, आपने अपना आवेदन दिल्ली भेज दिया है तो जवाब मिलने का इंतज़ार करें. वैसे चाहें तो एक आवेदन स्थानीय शाखा में भी दे सकते हैं.

रास्ता ख़राब है

मेरे इलाक़े में एक रोड है, जो शकरी चीनी मिल से पठान कुबनी के बीच में है. वहां से एक रास्ता भालपट्टी पंचायत से जाकर मिलता है, जो 1983 में बना था. आज इस रास्ते की हालत बहुत ख़राब है. कोई भी जन प्रतिनिधि इस रास्ते की ओर ध्यान नहीं दे रहा है. अगर इस रास्ते से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी हैं तो कैसे करें?

-अफ़ज़ल हुसैन ख़ान, *नैनाघाट, दरभंगा, बिहार.*

ख़राब और टूटी सड़कों की समस्या आम है. यह अच्छी बात है कि आप इस संबंध में आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं. हम इस अंक में सड़क की खुदाई से संबंधित आवेदन का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं. आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सड़क की मरम्मत के बारे में सवाल पूछ सकते हैं. जैसे इसकी कब-कब मरम्मत हुई, कितना ख़र्च आया, किसने काम किया, जांच हुई या नहीं, जांच रिपोर्ट इत्यादि.

कहां से मिलेगी सूचना

सूचना अधिकार क़ानून का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पर है?

-जोयसम जार्ज, *गोपालपुरा, जयपुर.*

सूचना क़ानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में (केंद्र या राज्य सरकार दोनों) जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन उसके पास जमा करना पड़ता है. वहीं से आपको सूचना मिलती है. आपको जिस विभाग से संबंधित सूचना चाहिए, उस विभाग के पीआईओ के पास अपना आवेदन जमा कराएं. आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क देना पड़ता है. आवेदन पीआईओ के पास जमा कराने के बाद 30 दिनों के भीतर आपको सूचना मिल जानी चाहिए.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301

ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(सड़क खुदाई का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

.....क्षेत्र में दिनांक.....से दिनांक.....के दौरान सड़क काटने और उससे बने गड्ढों को पुन: भरने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उन एजेंसियों की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्होंने इस दौरान सड़कों में कटिंग या खुदाई का कार्य किया और सड़क काटने का उद्देश्य एवं समय भी बताएं.

2. इन एजेंसियों द्वारा सड़क काटने के लिए कितनी राशि जमा कराई गई? राशि जमा कराने की तिथि भी बताएं.

3. उन सभी स्कैचों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिनमें उन जगहों को दर्शाया गया हो, जहां एजेंसियों को सड़क काटने के लिए अनुमति दी गई.

4. क्या सभी एजेंसियों ने स्वीकृत स्थानों पर ही सड़क काटी या उसमें परिवर्तन भी हुआ?

5. आपके विभाग द्वारा उपरोक्त जमा की गई राशि का उपयोग कहां किया गया? उन सभी कार्यों की सूची दें, जिनमें इस राशि का उपयोग किया गया. इसमें सभी कार्यों के नाम, जगहों का नाम यानी जहां-जहां कार्य किया गया है और प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत राशि का पूरा विवरण हो.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में---रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम .....
पता .....

ज़रा हट के

अजब-ग़ज़ब गांव

यह दिलचस्प कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की है, जहां का मुंडेरा गांव अजीब प्रथा या अंधविश्वास के चलते एक दिन पूरी तरह खाली हो जाता है, दिन निकलने से पहले सारे लोग गांव की सीमा से बाहर चले जाते हैं और दिन ढलने के बाद वापस लौटते हैं. इस दौरान घरों में ताले भी नहीं लगाए जाते. हर तीसरे साल जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या सोमवार को इस अजीब परंपरा को निभाया जाता है. दिन निकलते ही गांव के बाहर ग्रामीणों का जमावड़ा लग जाता है और गांव में सन्नाटा छा जाता है. काली मंदिर में पूजा और सूर्यास्त के बाद गांव की परिक्रमा करके पताका फहराई जाती है और इसके बाद ही लोगों की गांव में वापसी होती है. इस पूरे प्रायोजन को पराह कहा जाता है. गांव के बुज़ुर्गों के मुताबिक़, सदियों से इस परंपरा को निभाने से पूरा गांव बीमारियों और दैवीय आपदाओं से बचा रहता है. दरअसल, कई सौ साल पहले इस गांव में थारू जनजाति की बस्ती थी, जिन्हें सपने में मां काली ने गांव के बाहर पराह करने का आदेश दिया और यह कहा था कि ऐसा करने से पूरा गांव बीमारियों और दैवीय आपदाओं से बचा रहेगा. थारू जनजाति की इस परंपरा का पालन मुंडेरा गांव के लोग आज भी करते हैं. यही नहीं, गांव में कोई नवविवाहिता हो या प्रसूता स्त्री, सभी को इस परंपरा का पालन करना पड़ता है. गांव के बाहर काम करने वाले लोग छुट्टी लेकर यह परंपरा निभाने आते हैं. गांव के लोगों की मान्यता है कि पराह के दिन यदि कोई गांव में रुका और उसने पानी पिया तो वह अंधा हो जाता है. इस डर से गांव में कोई नहीं रुकता. पराह के दिन घरों में ताले नहीं लगते और चोरी भी नहीं होती. इस मौक़े पर चंदे के पैसों से ख़रीदी गई एक भेड़ के गले में कुछ खाद्य सामग्री बांधकर उसे काली मंदिर ले जाया जाता है, जहां उसके गले से सामग्री खोलकर उसे प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है. इसके अलावा एक दर्जन ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है. इसीलिए कहते हैं कि भारत अजब-ग़ज़ब विविधताओं का देश है.

नवजात शिशुओं की भाषा

यूं तो शिशु जन्म से बहुत बाद में बोलना सीखता है, मगर उसके द्वारा भाषा को सीखने की प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है और जन्म के बाद उसके रोने की ध्वनि में उसके माता-पिता की मातृभाषा का असर देखा जा सकता है. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक नया शोध कहता है. वास्तव में बालक गर्भ में मां की आवाज़ के साथ-साथ आसपास हो रही बातचीत को भी सुनता है. भावनाओं को व्यक्त करते समय ध्वनियों में जो परिवर्तन वह सुनता है, उसे जन्म के बाद नकल करने की कोशिश करता है. शिशु मां के गर्भ में बाहरी आवाज़ों को सुनता है, यह एक स्थापित तथ्य है, लेकिन उन आवाज़ों की पहचान कर वह बोलने का अभ्यास भी कर लेता है, यह नई खोज है. इस खोज का श्रेय जाता है कैथेलीन वर्म्क को, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ज़बर्ग की एंथ्रोपोलोजिस्ट हैं. कैथेरीन और उनकी टीम ने अपने अभ्यास में पाया कि नवजात शिशुओं के रोने का पैटर्न अपने अभिभावकों द्वारा बोली जा रही भाषा के आधार पर तैयार होता है. आज तक वैज्ञानिक यही मानते आए थे कि बोलने की कला जन्म के तीन महीने बाद सीखी जानी शुरू होती है, लेकिन कैथेरीन और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि यह प्रक्रिया जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है. हर भाषा को बोलने का अपना एक तरीक़ा होता है. उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलते समय वाक्य के अंत में जोर दिया जाता है, लेकिन हिंदी में यह उल्टा होता है. यानी हिंदी में कोई वाक्य बोलते समय शुरू में जोर दिया जाता है और वाक्य का अंत थोड़ी धीमी आवाज़ में होता है. यही पैटर्न शिशु अपने रोने की आवाज़ में भी अपना लेता है. इस शोध के लिए उन्होंने 60 स्वस्थ नवजात शिशुओं का चयन किया. इनमें से 30 फ्रेंच थे और 30 जर्मन.

इनके रोने के अलग-अलग 500 पैटर्न रिकॉर्ड किए गए. जैसे डायपर बदलते समय रोना, खाने के समय रोना, बात करते समय रोना आदि. शोधकर्ताओं ने पाया कि जर्मन नवजात शिशु रोते समय शुरुआत तेज़ आवाज़ हाई पिच से करते हैं और फिर उसे धीमा करते हैं, जबकि फ्रेंच बच्चे धीमी आवाज़ लो पिच पर रोना शुरू कर तेज आवाज़ तक जाते हैं. जर्मन और फ्रेंच भाषा इसी पैटर्न के आधार पर बोली जाती है. शिशु मां द्वारा बोली जा रही भाषा में से ध्वनि संरचना की पहचान कर लेते हैं और अपने रोने में उसका इस्तेमाल करते हैं. अब ज़रा सोचिए कि आप किस भाषा में रोए थे!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 18 अक्टूबर–24 अक्टूबर 2010

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
प्रियजनों का सहज व्यवहार भी आपको दिखावा नज़र आएगा. विरोधी भी दोस्ती का प्रस्ताव देंगे. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपने सामान के प्रति सचेत रहें. वाणी में मधुरता बनाए रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
भाग्योदय के अवसर मिलेंगे. अपनी सोच में बदलाव लाएं, राह की मुश्किलें दूर होंगी. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है, स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें. परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

मिथुन 21 मई से 20 जून
आय के नए रास्ते खुलेंगे. अधिकारी आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे. साझीदारी में नए काम की शुरुआत होगी. वैभव का सामान जुटाने में ख़र्च संभव है. किसी दूसरे के विवाद में न उलझें, अन्यथा आप भी फंस सकते हैं.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को परेशानी हो सकती है. आपके अपने ही नुक़सान पहुंचाने का प्रयास करेंगे. लापरवाही के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कुछ नया काम करने से पहले घर मे बड़े-बुज़ुर्गों से विचार विमर्श अवश्य करें. आय में बढ़ोत्तरी के योग हैं.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी जेब का धन ख़र्च कर देंगे. आपके विरोधी राह में अड़चनें खड़ी कर सकते हैं. दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है. कष्ट के बावजूद यात्रा सुखद रहेगी. मित्रमंडली का सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. बदले की भावना से बचें. नए संपर्क बनेंगे.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. कोई लंबित कार्य पूरा होने का योग है. धन-धान्य की प्राप्ति हो सकती है. नए व्यापार से लाभ संभव है. व्यय पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्थायी संपत्ति के क्रय-विक्रय से लाभ होगा. विदेश यात्रा संभव है. विरोधी उलझाने का प्रयास करेंगे. नए मित्र बनेंगे. अचानक लाभ के अवसर उत्साहित रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. जीवनसाथी से किसी बात को लेकर तकरार की स्थिति बनेगी. भावावेश में कोई निर्णय न करें. कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
आप चतुराई से अपना काम निकालने में सफल होंगे. शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी. मांगलिक कार्य में ख़र्च की संभावना है. परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. नेत्र संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखें, कुछ लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. किसी भी कार्य में जल्दबाज़ी न करें. अच्छे समय का इंतज़ार करें. पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. वैवाहिक चर्चाओं में सफलता मिलेगी.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
साहसिक सेवा से जुड़े लोगों को खिन्नता का अनुभव होगा, धैर्य से काम लें. लेखाकार्य से जुड़े लोग परेशानी का अनुभव करेंगे. परिवारीजनों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. महंगाई आसमान से भी ऊपर जा रही है और बहुत सी जगहों पर रोटी और अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं.

पाकिस्तान

गहराता जा रहा है तख्तापलट का ख़तरा

आदित्य पूजन

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के एक बयान ने पिछले दिनों पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी. मुशर्रफ़ ने अपनी राजनीतिक पार्टी के लांच से तीन दिन पहले लंदन में कहा कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैनिक शासन का दौर शुरू होने वाला है. पूरी दुनिया के लिए यह बयान भले चौंकाने वाला हो, लेकिन चौथी दुनिया ने जुलाई महीने में ही यह बात कही थी. हमने उस समय कहा था कि सितंबर महीने तक पाकिस्तान सैनिक शासन की गिरफ़्त में आ सकता है. ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्तापलट हो सकता है और सैनिक तंत्र शासन पर अधिकार जमा सकता है.

परवेज़ मुशर्रफ़

यूसुफ़ रज़ा गिलानी

जनरल अशफ़ाक़ कयानी

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. महंगाई आसमान से भी ऊपर जा रही है और बहुत सी जगहों पर रोटी और अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं. आम आदमी परेशान है क्योंकि उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं. बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है. इसका सबसे बड़ा असर वहां की क़ानून व्यवस्था पर पड़ा है. छीनाझपटी बढ़ रही है और चोरी व डकैती की ख़बरें आम हो गई हैं. बेरोज़गार नौजवानों को लगता है कि नौकरी या काम न मिलने की हालत में चोरी डकैती रोज़ी-रोटी का आसान रास्ता है. पुलिस के पास समय नहीं है कि लोगों को पकड़े या फिर उसकी विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि कोई उसे तवज्जो ही नहीं दे रहा है. देश के अधिकांश हिस्सों में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहां कट्टरवादी और आतंकी संगठनों का राज चलता है. दहशतगर्दी अपने चरम पर है, प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. क़ानून-व्यवस्था का आलम यह है कि सरेआम क़त्ल और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाती. देश का पुलिस तंत्र सामंती ताक़तों का पिट्ठू बन कर रह गया है. आम लोग पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी शिक़ायत पर कार्रवाई तभी होगी जब किसी बड़ी शख्सियत का वरदहस्त उन्हें हासिल हो. हाल के दिनों में आई बाढ़ ने पहले से ही क़र्ज़ में डूबी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है. बाढ़ग्रस्त इलाक़ों में अभी भी लाखों लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हैं. देश का राजनीतिक तंत्र कितना ज़िम्मेदार है, इसका पता इस बात से लग जाता है कि जब लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे थे, तो राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी विदेश यात्रा पर थे. बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में भी घपले हुए. अल्पसंख्यकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया. नतीजा यह है कि केवल ज़रदारी ही नहीं, राजनीतिज्ञों की पूरी जमात ही जनता की नज़रों में पूरी तरह ख़ारिज हो चुकी है. राजनीतिक दलों और नेताओं को आम जनता की दुश्वारियों से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, उन्हें केवल अपने फ़ायदे की चिंता है. देश का न्यायिक तंत्र भी कमोबेश इसी हालत में है. वह हर क़ीमत पर अपने अधिकारों में इज़ाफ़े की कोशिश में है ताकि राजनीतिक तंत्र की उल-जुलूल हरकतों से बचा रह सके. देश में ग़रीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है. जनता निराश है क्योंकि उसकी समस्याओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है. ऐसे हालात हों तो तख्तापलट की संभावना से भला कैसे इंकार किया जा सकता है.

पाकिस्तान में सैनिक शासन

1958-71	-1958-69	अयूब ख़ान
	1969-71	याहया ख़ान
1977-88		जनरल जिया उल हक
1999-2008		परवेज़ मुशर्रफ़

वैसे भी, पाकिस्तान में तख्तापलट का पुराना इतिहास है. ख़ुद मुशर्रफ़ भी 1999 में नवाज़ शरीफ को सत्ता से बेदख़ल कर सैन्य शासन के मुखिया बने थे. मुशर्रफ़ ने यह मांग भी की है कि देश के संविधान में बदलाव कर शासन तंत्र में सेना की भूमिका तय की जाए. उनके इस बयान की चारों ओर आलोचना हो रही है और देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की मांग की जा रही है. लेकिन सच्चाई यही है कि सेना वैसे भी शासन में अपना दख़ल देती रही है. मौजूदा हालात में भी सभी फ़ैसले परदे के पीछे से सेना द्वारा ही लिए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले की बात है जब भारत और पाकिस्तान के विदेशमंत्रियों के बीच वार्ता हो रही थी. भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा का पाक प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साथ मिलने का कार्यक्रम तय था. इसी बीच सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी गिलानी से मिलने पहुंचे और कृष्णा के साथ उनकी मीटिंग को टाल दिया गया. यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र कहां स्थित है. सच्चाई तो यह है कि कयानी को सेवा विस्तार न मिलता तो पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट शायद पहले ही हो चुका होता. पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ, जब सेना प्रमुख को किसी चुनी हुई सरकार द्वारा सेवा विस्तार हासिल हुआ है. कयानी को सेवा विस्तार देने का फ़ैसला मजबूरी में लिया गया और इसमें अमेरिकी दबाव की भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन इससे ख़तरा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, बस कुछ समय के लिए टल गया. कयानी पाकिस्तानी सेना के उस धड़े से जुड़े हैं, जो आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है. इसमें कोई संदेह नहीं कि सैन्य तख्ता पलट की किसी भी योजना में कयानी को पाक सेना के साथ आतंकी संगठनों, कट्टरवादी राजनीतिक पार्टियों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल होगा. अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान-युद्ध में कामयाबी के लिए पाकिस्तान पर आश्रित है. उसकी एक ही इच्छा है कि पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सत्ता हो, वह उसके कहे मुताबिक़ काम करे और इस लिहाज़ से कयानी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

सरकार मजबूर है क्योंकि वह जनता का विश्वास खो चुकी है. लोग मांग करने लगे हैं कि इनसे अच्छी तो सेना थी. यह मांग वहां बढ़ रही है और लोकतंत्र के लिए ख़तरा पैदा कर रही है. लोकतंत्र के नाम पर शासन करने वाले लोग लूट तंत्र और दमन तंत्र की रक्षा करने वाले बन गए हैं. अपने 63 साल के अस्तित्व में आधे से ज़्यादा समय तक पाकिस्तान सैनिक शासन के अंतर्गत ही रहा है. 1958 में जब तत्कालीन सेनाध्यक्ष जेनरल अयूब ख़ान ने पहली बार तख्तापलट को अंजाम दिया था तो पाकिस्तान के नए संविधान को लागू हुए बमुश्किल दो साल ही हुए थे. 1971 में एक हिंसक संघर्ष के बाद देश का विभाजन हुआ और 1972 में ज़ुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी हुई, लेकिन केवल पांच साल बाद सेनाध्यक्ष जिया उल हक ने उन्हें सत्ता से बेदख़ल कर दिया. 1977 से लेकर 1988 तक देश में सैन्य शासन का दूसरा दौर चला. 1988 में जेनरल जिया की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो नई प्रधानमंत्री बनी. अगले एक दशक तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी तरह चलती रही. कभी भुट्टो तो कभी नवाज़ शरीफ देश के प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहीं. भारत के साथ कारगिल की लड़ाई में मिली पराजय से जनता में निराशा बढ़ी और 1999 में सेना ने मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर सत्ता अपने हाथों में ले ली. आज पाकिस्तान में एक बार फिर फौज़ के आने की आहट सुनाई देने लगी है. मुशर्रफ़ ने हो सकता है यह बयान अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए दिया हो, लेकिन इसे हलके में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आज शायद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है.

aditya@chauthiduniya.com

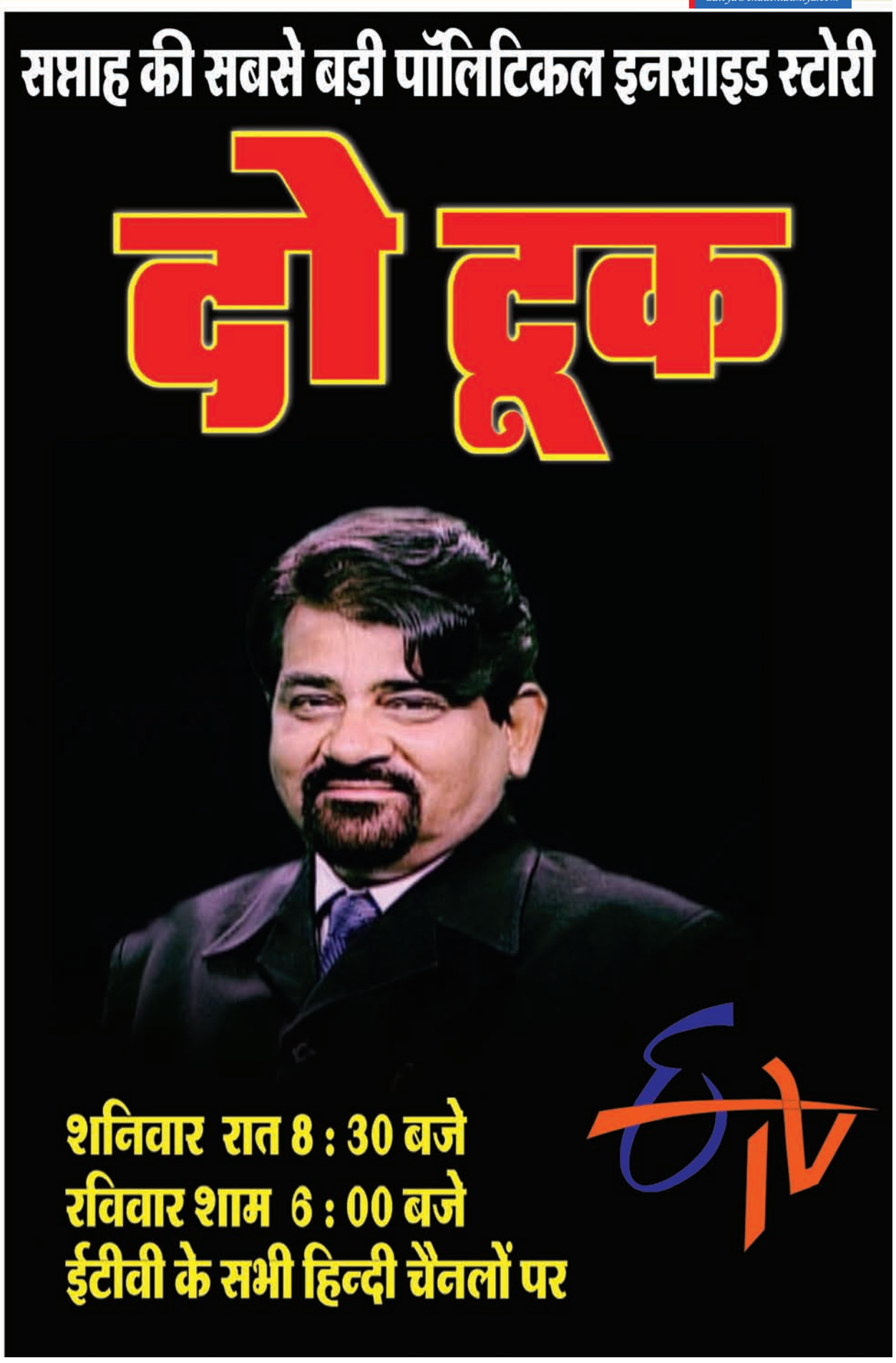

गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है. ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रयग्राह विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए.

जीवन मूल्य कितने ज़रूरी

आज अगर जीवन के मूल्यों के बारे में बात करें तो लगता है कि जैसे मज़ाक उड़ाया जा रहा है. आम धारणा है कि कलयुग में इन मूल्यों पर चल पाना संभव नहीं. अक्सर जब मूल्यों की बात आती है तो हम कहते हैं कि सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, माता-पिता का आदर आदि ही जीवन के मूल्य हैं. सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि मूल्य है क्या? जीवन मूल्यों पर चलकर ही किसी भी घर, कंपनी, समाज एवं देश के चरित्र का निर्माण होता है. मूल्य यानी जीवन के रास्ते को तय करने के लिए कुछ मूलभूत आधार. अगर देखें तो सच बोलने को मूल्य इसलिए कहा गया, क्योंकि सच बोलकर सदा अच्छा महसूस होता है, एक अंदरूनी ताक़त का एहसास होता है, पवित्रता का अनुभव होता है और सच बोलना सहज लगता है. पीछे मुड़कर अगर आप देखें तो जब पहली बार सच से परे हुए थे यानी झूठ बोला था, बहुत असहज होकर बोला था. मन ही नहीं, शरीर की भी प्रतिक्रिया अलग तरह की थी, क्योंकि आत्मा का मूलभूत मूल्य है सच. उसी तरह वफ़ादार और ईमानदार रहना भी हमें अच्छा लगता है. ग़ौर कीजिएगा, जब भी कोई धोखा या चोरी करता है तो मन कचोटता है, मुंह सूखता है, शरीर कांपता है, क्योंकि वह सच से परे जा रहा होता है.

कभी सोचा आपने कि इन सबको मूल्य क्यों कहा गया है? मूल्य यानी वह वस्तु, जिसकी कुछ क़ीमत हो. इन सभी व्यवहारों की क़ीमत है, हम जितना अधिक से अधिक इस व्यवहार को इस्तेमाल करते जाते हैं, हर बार का इस्तेमाल किया गया यह व्यवहार अपनी क़ीमत अदा करता और हमारे सत्कर्म के खाते में जमा हो जाता है. जैसे हम कहते हैं कि हर झूठ की, धोखे की, बेईमानी की क़ीमत अदा करनी पड़ती है. उसी तरह सच पर चले हर कर्म की, वफ़ादारी की, प्रेम की, सहयोग की यानी इन सारे व्यवहारों की क़ीमत जमा होती है. साथ ही साथ मन की मज़बूती और परमात्मा की कृपा सुनिश्चित हो जाती है.

कई बार सवाल उठता है कि आज के युग में जो सच के रास्ते पर चलता है, वह जल्दी सफल नहीं होता, लेकिन आप ध्यान से देखें, जो व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों पर अडिग रहकर चलता है, वह कभी भी भय में नहीं जीता. उसका चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से दमकता रहता है. वह निर्भय होकर अपनी बात कहता है और हर पल सुरक्षा का अनुभव करता है.

अगर आप समझें तो यही जीवन मूल्य हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं. इनसे हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है. हमें हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है. अगर जीवन मूल्यों पर चलकर इतना कुछ मिलता है तो हम सुख, शांति और प्रेम के लिए अन्यत्र कहीं क्यों भटकते हैं? इन पर चलना जब हमारे जीवन का स्वभाव है तो हम इन पर चल क्यों नहीं पाते? विषम परिस्थितियां आते ही डगमगा क्यों जाते हैं? क्यों आसान लगता है बेईमान होना, क्यों वफ़ादार रहना मुश्किल लगने लगता है? वजह, जब भी इन मूल्यों को हम अपनाते हैं, ज़िम्मेदारी का एहसास होता है. अगर हम आध्यात्मिक हो जाएं, ख़ुद को ईश्वर के साथ जोड़ लें और उसके दिखाए रास्ते पर चलते जाएं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा. सारा भय भी ख़त्म हो जाएगा. जिस चरित्रवान समाज-देश की कल्पना हम करते हैं, जिसकी इच्छा हमारे मन में है और जो हम कुछ हटकर अलग सा करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत स्वयं से ही होगी. स्व-परिवर्तन से ही जग परिवर्तन संभव है. आइए इन जीवन मूल्यों को समझें, इन पर चलकर एक सुदृढ़, सभ्य और स्वस्थ समाज की रचना का हिस्सा बनें.

ओम साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई बाबा की शिक्षा...

शिरडी में बाज़ार प्रति रविवार को लगता है. निकट के ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं. मध्यान्ह के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाती थी, परंतु रविवार के दिन लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्रायः दम ही घुटने लगता. ऐसे ही एक रविवार के दिन हेमाडपंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे. शामा बाबा के बाईं और वामनराव दाहिनी ओर थे. इस अवसर पर बूटी साहेब और काका साहेब भी वहां उपस्थित थे. तभी शामा ने हंस कर कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए प्रतीत होते हैं. ऐसा कहकर शामा ने उनकी बांह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले. जब हेमाडपंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीनकर उठाए.

भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति-भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह नहीं जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे रहे. इसका जवाब किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को सब उत्सुक थे. तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय को एकांत में खाने की बुरी आदत है. आज बाज़ार का दिन है और यह चने चबाते हुए ही यहां आए हैं. मैं तो इनकी आदतों से भलीभांति परिचित हूं और चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं. इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है. हेमाडपंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं. अभी तक मैंने शिरडी के बाज़ार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाज़ार नहीं गया. फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे ख़रीदता? और जब मैंने ख़रीदे ही नहीं, तब उनके खाने की बात तो दूर की है. भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं, उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता. बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं. अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है, क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन करते हो?

इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए. उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है. इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकतीं. इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वरार्पण कर देने से इनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है. इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए. यदि इसका नित्याभ्यास किया जाए तो परमेश्वर कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे. विषय के रसास्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए. तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा. इस प्रकार कुप्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी और आचरण में सुधार होगा. इसके फलस्वरूप गुरुप्रेम और ज्ञान में वृद्धि होगी. जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्यघन में लीन हो जाती है. वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो भिन्न समझता है, वह निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना दुर्लभ है. इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए. गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है. ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रयग्राह विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए. इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी. साई बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सामने रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी. ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी, सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट हो जाएगा तथा चित्त को सुख एवं शांति मिलेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोरो ने सोनिया की इस जीवनी में कल्पना के आधार पर कई प्रसंग जोड़े हैं. ख़ुद लेखक ने भी माना है कि यह सोनिया की फिक्सनलाइज़्ड बायोग्राफी है.

सवालों के घेरे में सोनिया की जीवनी

अनंत विजय

अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अच्छा–खासा बवाल मचाया था. दरअसल मोरो की यह किताब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है. मोरो का दावा है कि यह किताब सोनिया के बचपन, उनकी राजीव गांधी से मुलाक़ात और शादी, सास इंदिरा गांधी के साथ बिताए दिनों के अलावा राजीव की हत्या के बाद उनकी मनोस्थिति का चित्रण करती है. दरअसल मोरो की किताब से इस बात के संकेत मिलते हैं कि सोनिया गांधी पति की हत्या के बाद भारत छोड़ कर इटली जाना चाहती थीं. किताब में पृष्ठ संख्या सोलह पर इस बात का उल्लेख है कि सोनिया ने सोचा कि उस देश में क्यों रहना, जो अपने ही बच्चों को खा जाता है. पृष्ठ संख्या एक सौ छिहत्तर पर भी इस बात के संकेत हैं कि गांधी परिवार में राजीव की मौत के बाद इटली जाने पर चर्चा होती थी. किताब में कई ऐसे प्रसंग हैं, जहां लगता है कि लेखक ने सोनिया की ज़िंदगी के यथार्थवादी पहलुओं में अपनी कल्पना का तड़का लगाया है. जैसे पृष्ठ संख्या एक सौ तिरसठ पर कहा गया है कि रात के तीन बजे सोनिया ने राजीव से कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने के ड्राफ्ट में उन्होंने इंदिरा गांधी की मदद की थी.

ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे साबित होता है कि मोरो ने सोनिया की इस जीवनी में कल्पना के आधार पर कई प्रसंग जोड़े हैं. ख़ुद लेखक ने भी माना है कि यह सोनिया की फिक्सनलाइज़्ड बायोग्राफी है. लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि किसी जीवित व्यक्ति की काल्पनिक जीवनी लिखने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है. जब तक इस आत्मकथा पर विवाद नहीं खड़ा हुआ था, तब तक इसे सोनिया की जीवनी बताकर प्रचारित किया और बेचा जा रहा था. सबसे पहले यह जीवनी अक्टूबर दो हज़ार आठ में स्पेनिश में छपी और बाद में इसका अनुवाद इटैलियन, फ्रैंच और डच भाषा में हुआ. एक अनुमान के मुताबिक़, अब तक इस किताब की तीन लाख प्रतियां बिक चुकी हैं. ज़ाहिर है, लेखक ने तीन भाषाओं के बल पर एक बड़ा बाज़ार और पाठक वर्ग हासिल कर लिया है. अब मोरो इसे अंग्रेजी में प्रकाशित कर भारत के अलावा अन्य यूरोपीय देशों और अमेरिका के बाज़ार में सोनिया गांधी का नाम भुनाना चाहते हैं. जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि इसमें इटली में सोनिया के बचपन को प्रमुखता से छापा गया है. मोरो लिखते हैं, सोनिया के पैदा होने पर लुजियाना के घरों में परंपरा के अनुसार गुलाबी रिबन बांधे गए. चर्च ने सोनिया को नाम दिया एडविजे एनटोनियो अलबिना मैनो, लेकिन उनके पिता स्टीफैनो ने उन्हें सोनिया नाम दिया. रूसी नाम रखकर वह उन रूसी परिवारों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उनकी जान बचाई थी. सोनिया के पिता मुसोलिनी की सेना में थे, जो रूसी सेना से पराजित हो गई थी. सोनिया जियोवेनो के कॉन्वेंट स्कूल में गईं, लेकिन उन्होंने उतनी ही पढ़ाई की, जितनी ज़रूरत थी. यानी वह अच्छी विद्यार्थी नहीं थीं, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने के बावजूद वह हंसमुख और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थीं. कफ और अस्थमा की शिक़ायत की वजह से वह बोर्डिंग स्कूल में अकेले सोती थीं. आगे जाकर तूरीन में पढ़ाई के दौरान सोनिया के मन में एयर होस्टेस बनने का अरमान भी जागा था. उसके बाद सोनिया विदेशी भाषा की शिक्षक या फिर संयुक्त राष्ट्र में अनुवादक बनने की ख्वाहिश पालने लगीं. उपरोक्त प्रसंगों के सामने आते ही कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी. कांग्रेस का आरोप है कि मोरो ने वास्तविकता से छेड़छाड़ की है, लेकिन मोरो का दावा है कि उसकी किताब एक वृहद और लंबे शोध का नतीजा है. मोरो के मुताबिक़, तथ्यों और घटनाओं की सत्यता को जानने–परखने के लिए उन्होंने ख़ुद सोनिया के होम टाउन लुजियाना में काफी वक़्त बिताया. उसने किताब छपने के पहले उसकी पांडुलिपि सोनिया गांधी की बहन नाडिया को भी दिखाई थी. किताब छपने के बाद सोनिया को भी उसकी एक प्रति भेजी गई. नाडिया ने किताब पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि सोनिया की तरफ़ से कोई जवाब ही नहीं मिला.

कांग्रेस नेताओं की आपत्तियों और लेखक को क़ानूनी नोटिस के हो–हल्ले के बीच यह किताब सोनिया एवं उनके इर्द–गिर्द के विवादों और घटनाओं में सिमट कर रह गई. जबकि किताब में सांसद एवं सोनिया की देवरानी मेनका गांधी के बारे में ज़्यादा विस्फोटक प्रसंग छपे हैं, जो घटनाओं के चश्मदीदों के बयानों पर आधारित होने की वजह से ज़्यादा प्रमाणिक प्रतीत होते हैं. मोरो ने मेनका और इंदिरा गांधी की पहली मुलाक़ात का बड़ा दिलचस्प विवरण दिया है. जब मेनका इंदिरा गांधी से मिलने पहुंची तो बेहद डरी–सहमी हुई थीं. अपना परिचय देते समय मेनका यह बात छुपा गईं कि वह एक तौलिया कंपनी के विज्ञापन की मॉडल हैं. इंदिरा गांधी मेनका से पहली मुलाक़ात के बाद उनके एवं उनके परिवार के बारे में और ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा करना चाहती थीं, लेकिन संजय गांधी बेहद जल्दबाज़ी में थे और उन्होंने मंगनी कर ली. जब सगाई के बाद दोनों परिवार साथ खाने बैठे और बातचीत शुरू हुई तो इंदिरा गांधी को एहसास हुआ कि मेनका और उनके परिवार के लोग न तो उतने पढ़े–लिखे हैं और न ही विचारों में आधुनिक.

तेइस सितंबर उन्नीस सौ चौहत्तर को गांधी के पारिवारिक मित्र मोहम्मद यूनुस के घर पर संजय और मेनका परिणय सूत्र में बंध गए. यहां पर मोरो ने संकेत दिए हैं कि मेनका को गांधी परिवार में एडजस्ट करने में सोनिया से ज़्यादा दिक्कत हुई. मेनका को सिगरेट पीने की आदत थी, जबकि संजय धूमपान को सख्त नापसंद करते थे. इंदिरा गांधी अपनी बीमारी और सोनिया अस्थमा की वजह से धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं. एक बार तो मेनका के व्यवहार से राजीव गांधी काफी खिन्न हो गए थे. हुआ यह कि मेनका सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रही थीं और सोनिया घर के काम में हाथ बंटा रही थीं. यह देखकर राजीव को बेहद कोफ्त हुई, जिसे उन्होंने ज़ाहिर भी किया था. एक और बेहद दिलचस्प वाकया इस किताब में है. एक बार मशहूर लेखक खुशवंत सिंह गांधी परिवार से मिलने गए तो वहां कुत्तों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा था. मेनका के आइरिश वुल्फहाउंड और सोनिया के शांत से अफगानी कुत्ते के बीच लड़ाई चल रही थी. सोनिया दोनों को अलग करना चाह रही थीं, लेकिन मेनका इस झगड़े से मज़ा ले रही थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका कुत्ता सोनिया के कुत्ते से मज़बूत था. मेनका ने सोनिया पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए खुशवंत सिंह के साथ मिलकर सूर्या पत्रिका भी निकाली थी.

लेखक ने इंदिरा गांधी की सचिव ऊषा के हवाले से लिखा है कि मेनका बेहद बुद्धिमान थीं, लेकिन महत्वाकांक्षी थीं. उन्हें हर वक़्त लगता था कि संजय गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे. वह गाहे–बगाहे इस बात को सार्वजनिक रूप से कहती भी थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. सतहत्तर में कांग्रेस की करारी हार के बाद जब संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई तो इंदिरा गांधी मेनका को लेकर बेहद चिंतित रहने लगीं. उन्होंने अपनी दोस्त पुपुल जयकर से चिंता जताते हुए कहा भी था कि मेनका की मां की महत्वाकांक्षा उन्हें संजय की जगह लेने के लिए प्रेरित करेगी. इस सोच को बल मिला खुशवंत सिंह के एक लेख से, जिसमें उन्होंने खुलेआम वकालत की थी कि संजय की मौत के बाद उनकी राजनीतिक वारिस मेनका हैं. उन्होंने लिखा कि मेनका संजय गांधी की तरह बहादुर हैं और दुर्गा की अवतार हैं. ज़ाहिर है, ख़ुशवंत सिंह के लेख से इंदिरा गांधी आहत हुईं, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध में विजय के बाद उनकी तुलना दुर्गा से होने लगी थी. खुशवंत की इस तुलना से इंदिरा गांधी के मन में यह संदेह पैदा हो गया कि मेनका की रज़ामंदी के बाद ही खुशवंत ने वह लेख लिखा.

उसके बाद संजय पर लिखी किताब को लेकर विवाद और बढ़ा. राजीव गांधी के राजनीति में आने पर मेनका की आपत्तियों से इंदिरा गांधी बेहद ख़फ़ा रहने लगीं, लेकिन जब उन्नीस सौ बयासी में मेनका ने मना करने के बावजूद लखनऊ में लंबा–चौड़ा भाषण दे डाला तो इंदिरा गांधी ने मेनका के ख़िलाफ़ निर्णय लेने का मन बना लिया. मेनका के लखनऊ से वापस लौटते ही गुस्से से भरी इंदिरा गांधी ने उन्हें तत्काल घर से बाहर निकल जाने का हुक्म सुना दिया. घर से बाहर निकालने के वक़्त हुए हाई वोल्टेज ड्रामे पर भी मोरो ने विस्तार से लिखा है. मोरो ने किताब में एक डिस्क्लेमर भी लगाया है–बातचीत, संवाद और स्थितियां लेखक की व्याख्या पर आधारित हैं और ज़रूरी नहीं है कि वे प्रमाणिक भी हों. लेकिन यहां एक बार फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति की जीवनी को फिक्शनलाइज़ कैसे किया जा सकता है? क्या लेखकीय आज़ादी के नाम पर कुछ भी काल्पनिक लिखने की इजाज़त किसी लेखक को दी जा सकती है? इन्हीं सवालों और क़ानूनी पचड़ों के बीच भारतीय पाठकों को इस किताब का बेसब्री से इंतज़ार है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

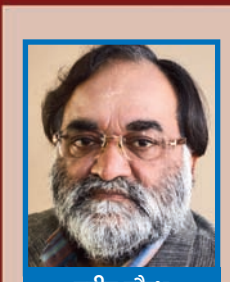

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहते थे. इसलिए वह सिर्फ़ इतना बोले कि कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम नहीं आईं.

साहब, काग़ज़ लिखाना ज़रूरी था. न लिखाते तो एडवांस डूब जाता. आनंद भारती ने मुन्नी को कपड़े वग़ैरह धोकर प्रेस कराने का निर्देश दिया. बोले, विदेश जा रहा हूं. इस काम में चूक नहीं होनी चाहिए. वैसे भी एक बार काम बता देने के बाद मुन्नी हर काम को टिच करके रखती थी. आनंद भारती ने नाश्ता किया और ब्रिटिश एंबेसी वीजा लेने चले गए. शाम को दफ्तर का काम निपटा कर वह जल्दी आ गए. अपना ब्रीफकेस तैयार किया. मुन्नी ने पूरी मदद की. सारी तैयारी हो चुकी थी. अगली सुबह चार बजे की फ्लाइट थी. एयरपोर्ट के लिए रात को बारह बजे निकलना था. मुन्नी जा चुकी थी. आनंद भारती टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे. कालबेल बजी. रात को इस समय टैक्सी वाले के अलावा और कौन हो सकता था. अनुमान सही था. आनंद भारती एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.

एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी थी. लंदन में बीते दिनों लिक्विड विस्फोटक के साथ आतंकी पकड़े गए थे. लंदन मेट्रो पर भी आतंकी हमला हो चुका था. इसलिए लंदन जाने वाली फ्लाइट में चेकिंग कुछ ज़्यादा हो रही थी. यात्रियों को तीन घंटे पहले से बोर्डिंग के निर्देश थे. आनंद भारती के साथ जाने वाले और भी चार पत्रकार थे. सभी एक–दूसरे से परिचित थे. दिल्ली से आनंद भारती के अलावा, सुविस मजूमदार और इंद्राणी नायर ही चढ़े. द हिंदू के पत्रकार अनंत कृष्णनन और टाइम्स की रेखा चिटणीस को दुबई में शामिल

होना था. लंदन की फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी. दुबई में तीन घंटे के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट थी. चेन्नई वालों के लिए दिल्ली से दुबई फ्लाइट पकड़ने का कोई मतलब नहीं था. इसलिए अनंत कृष्णनन ने चेन्नई से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट ली. रेखा अपनी बहनों के साथ छुट्टी मनाने के लिए दुबई में ही थीं, सो वह वहीं यात्रा में शामिल हुईं.

एमिरेट्स की फ्लाइट पर सभी लंदन के लिए सवार हुए. पांच के पूरे दल में दो को छोड़ कर सभी वेजिटेरियन थे. बुकिंग के समय ही तीनों ने वेजिटेरियन च्वायस लिखाई थी. डिनर के समय आनंद भारती, इंद्राणी मजूमदार और अनंत कृष्णनन को जो खाना मिला, वह नॉन वेजिटेरियन था. वह भी उन्हें वेजिटेरियन कह कर परोसा गया था. खाते समय सभी को लगा कि परोसे गए खाने में कुछ गड़बड़ है. सबने एक–दूसरे से पूछा. सभी को शंका हुई. एयर होस्टेस को बुलाया गया तो पहले तो उसने समझाया कि वेजिटेरियन खाने के नाम पर उसे यही मिला. वैसे भी एयर होस्टेस का रवैया भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं दिख रहा था. वे ब्रिटिश यात्रियों की सेवा में जी–जान से लगी हुई थीं. भारतीय यात्री द्वारा ड्रिंक मांगने पर वे नाक–भौं सिकोड़ती थीं. सर्विस में देरी शायद उनकी आदत का हिस्सा था. ब्रिटिश यात्री की कालबेल बजते ही एयर होस्टेस उनके सामने हाथ जोड़ खड़ी हो जाती थीं.

खाने के सवाल पर सब लोगों ने जमकर खिंचाई की. आनंद भारती ने जब कंप्लेंट बुक मांगी, तब जाकर फ्लाइट क्रू को लगा कि अब मामला गंभीर हो सकता है. इस बीच वह उनको यह भी बता चुके थे कि वे मीडिया के लोग हैं और ब्रिटिश सरकार के मेहमान हैं. क्रू में अफरातफरी मच गई. लेकिन आनंद भारती कंप्लेंट लिखने के लिए अड़े थे. इसी बीच क्रू की एक पाकिस्तानी सदस्य उनके पास आई. उसने अपने हिसाब से उर्दू और आनंद भारती के हिसाब से टूटी–फूटी हिंदी में अपना नाम बताया– जुबेदा. शर्मिंदगी के साथ बोली, सर, ग़लती मुझसे हुई है.

अगले अंक में जारी...

आदिशक्ति विंध्यवासिनी और विंध्य धाम

राजकुमार शर्मा

विंध्यवासिनी धाम प्रमुख शक्तिपीठों में एक है. मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म्य में कहा गया है कि जब देव–असुर संग्राम हुआ और देवता राक्षसों से पराजित होने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास शरणागत हुए. तब भगवान विष्णु सर्वप्रथम अपने तेज को स्वयं से अलग करते हैं, फिर सभी देवता अपना–अपना तेज भाग देते हैं और उसी से आद्यशक्ति मां प्रकट होती हैं. दार्शनिक रूप से इसे काल (समय) के अग्नि रूप में प्रदर्शित किया गया. उसका वर्ण काला, किंतु सिंदूर से आवेष्ठित है और उससे किरणें निकलती रहती हैं. वह सभी प्राणियों की स्वामिनी हैं. ब्रह्मा, विष्णु, देवतागण, दैत्य, पशु–पक्षी एवं संपूर्ण चर–अचर जगत उन्हीं के प्रभाव से संचालित होते हैं. मुख्य रूप से चामुंडा संहार और विनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं. आद्यशक्ति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. उन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में कार्य करने वाली महाशक्ति कहा गया है और त्रिदेवों की स्त्री शक्ति के रूप में भी स्मरण किया जाता है. देवी पुराण में यही शक्ति दुर्गा, उमा, शिवा देवी, ब्राह्मणी, विंध्यवासिनी, चामुंडा, शक्ति, पराशक्ति, गौरी, कात्यायनी, कौशिकी, पार्वती, नारायणी, मीना, धूमा, अंबिका, लक्ष्मी, चंडी, कपालिनी, काली, महिषासुर मर्दनी, नंदा, भवानी, तारा, वैष्णवी, महालक्ष्मी, श्वेता एवं योगेश्वरी आदि सैकड़ों नामों से जानी जाती है. सभी देवियों की मूल प्रकृति, कार्य एवं महत्व एक हैं. विंध्याचल पर्वत के मस्तक पर विराजमान होने के कारण यही आद्यशक्ति विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुईं. यह लोकहित के लिए विंध्य क्षेत्र में महासरस्वती, महाकाली एवं महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं. यद्यपि बाबा भोलेनाथ को काशी बहुत प्रिय है, परंतु शक्ति की उपस्थिति के कारण विंध्य क्षेत्र भी उन्हें उतना ही प्रिय है. इसी कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है.

शक्ति पूजा के विशद विवरण मध्यकाल के विविध ग्रंथों में मिलते हैं. पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा बहुतायत मिलती है. वेदों में भी शक्ति की अर्चना के अंश मौजूद हैं. भारत के बाहर भी अनेक प्राचीन देशों जैसे मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोनिया, अक्काद, यूनान, रोम एवं चीन आदि में शक्ति पूजा के व्याख्यानों एवं स्थलों की विशेष चर्चा है. मातृ देवी के रूप में सर्जक, पालक एवं संहारक भाव से ज्ञान, धन और रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती थी. सिन, शमस्, इस्तर, ईया, अस्सु, एन, बेले एवं थीटिस त्रिक की अर्चना प्रचलित थी. उक्त देवियां हंसवाहिनी, उलूकवाहिनी और पशुवाहिनी मानी जाती हैं. विंध्याचल माता की प्रसिद्धि उनके आदिशक्ति होने के कारण अधिक है. विंध्याचल के त्रिकोण पथ दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती के दया द्वार खोलते हैं, जिससे श्रद्धालुओं के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिटते हैं. सत, रज और तम संतुलित होकर जीव को मातृधाम की यात्रा करने के योग्य एवं पवित्र कर देते हैं. ऋग्वेद में स्वयं मां अपने स्वरूप के बारे में कहती हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हूं. धन, ज्ञान, योग्यता मैं ही देती हूं. शत्रुओं के नाश का कारण मैं ही हूं. मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती में माता के तीनों स्वरूपों की आराधना के निर्देश हैं. शाक्त मान्यता के लोग नवरात्र पूजन के प्रथम तीन दिन दुर्गा रूप, अगले तीन दिन लक्ष्मी रूप और अंतिम तीन दिन सरस्वती रूप की आराधना करते हैं.

विश्वास और तंत्र पथ के अनुसार, अलग–अलग देवी के तीन अलग–अलग रूपों की अलग–अलग विधि से उपासना की जाती है. जनसाधारण मां के सौम्य रूप की आराधना करते हैं. देवी के प्रचंड

रूप की पूजा कापालिक और कालमुख जैसे घोर पंथी करते हैं. इसमें पंचमकार तक का प्रयोग होता है. कामरूपिणी देवी की उपासना शाक्त लोग करते हैं. ये देवी को त्रिपुर सुंदरी, आनंद भैरवी और ललिता आदि नामों से पुकारते हैं. यहां भैरव को देवी की आत्मा माना गया है, जिनके नौ व्यूह हैं. काल व्यूह, कुल व्यूह, नाम व्यूह, ज्ञान व्यूह एवं अहंकार व्यूह आदि प्रमुख हैं. विंध्याचल में इन तीनों रूपों की स्थापना है. दार्शनिक सत्ता में शिव और शक्ति आदि तत्व हैं. शक्ति ही अंतर्मुखी होने पर शिव हैं और शिव ही बहिर्मुखी होने पर शक्ति हैं. विंध्यवासिनी देवी का उल्लेख महाभारत, वाल्मीकि रामायण, मार्कंडेय पुराण, कल्कि पुराण, देवी पुराण, देवी भागवत, श्रीमदभागवत, लक्ष्मी यंत्र, हरिवंश पुराण, वामन पुराण, दुर्गा सप्तशती, चंद्रकला नाटिका और कादंबरी जैसे महाकाव्यों, पुराणों और साहित्य में है. 12 महापीठों में भी इस धाम का पावन स्थान है. तारकेश्वर महादेव से लेकर विरोही तक विंध्य क्षेत्र में असंख्य मंदिर और कुंड हैं, जिनमें तारकेश्वर महादेव, पंचमुखी महादेव, लोंहदी महावीर, संकट मोचक महावीर, कृष्ण मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव, तारा देवी, रामेश्वर महादेव, दुग्धेश्वर महादेव, अक्रोधेश्वर लिंग, वीर भद्रेश्वर मंदिर, गोकणेश्वर महादेव, कामतेश्वर महादेव, कंकाल काली नंदजा, नारायण कुंड, लक्ष्मी कुंड, ब्रह्म कुंड, सप्तर्षि कुंड, नकादि कुंड, धर्मकुंड, गोकर्ण कुंड, सीता कुंड, रामकुंड, मुक्ति कुंड, भैरव कुंड श्मशान तारा एवं भैरव कुंड स्थित तारा शिवालय–श्रीयंत्र आदि विंध्यधाम के वैभव और प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं. भगवान राम ने त्रेता युग में विंध्याचल आकर शिवपुर के निकट रामगंगा घाट की प्रेतशिला पर अपने पूर्वजों का तर्पण किया. इतिहासकार मानते हैं कि माटी या पत्थर के जिस टुकड़े पर लाखों लोगों की श्रद्धा समर्पित होती है, वह माटी–पत्थर देवता और तीर्थ समान है. भारत को विंध्याचल की पावनता के कारण तीर्थों का देश कहा जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

ग्लोबल कंपनियों से साझा फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है. इससे कंपनी का तो फ़ायदा होता ही है, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवकों को भी कमाई का एक अच्छा जरिया मिल सकता है.

स्वरोज़गार के लिए बेहतरीन विकल्प है फ्रेंचाइजी

रीतिका सोनाली

एक वक्त था जब नौकरी के लिए पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत थी, पर मंदी के दौर ने ऐसा माहौल बना दिया है कि पढ़े-लिखे लोगों को भी नौकरी पाने के लिए ख़ाक छानना पड़ रहा है. हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि लोगों की हाथ आई नौकरियां भी छूट रही हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में हाथ आजमाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. भारत में फ्रेंचाइजी उद्योग चालीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकसित हो रहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा से लेकर हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर में 850 फ्रेंचाइजर और तक़रीबन 60,000 फ्रेंचाइजी हैं. क़ानूनी तौर पर हमारे देश में फ्रेंचाइजी-संबंधित करार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 और द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963 के अधीन आते हैं. कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोगों की नौकरियां बड़ी संख्या में जा रही हैं और हर कोई कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जिसमें निरंतरता हो, रोजी-रोटी का स्थाई और पुख्ता जुगाड़ हो. ऐसे में किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर शोहरत और पैसा कमाना एक बेहतरीन ऑप्शन है, जहां आप मालिक ख़ुद होते हैं और किसी बॉस या कुलीग की झिक-झिक भी नहीं सुननी पड़ती है. भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा देश काफ़ी समृद्ध है. इस लिहाज़ से यहां के शहरों में फ्रेंचाइजी के खुले अवसर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं. यह क्षेत्र कम निवेश और कम जोखिम के साथ बेहतर लाभ देने वाला है, इसलिए कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने आउटलेट खोलने की योजना बना रही हैं. ऐसे में ग्लोबल कंपनियों से साझा फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है. इससे कंपनी का तो फ़ायदा होता ही है, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवकों को भी कमाई का एक अच्छा जरिया मिल सकता है. फ्रेंचाइजी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए ऑटोमोटिव, आईटी, हेल्थ व ब्यूटी केयर, रिटेल, बिजनेस सर्विस, फूड एंड बिवरेज, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फाइनेंसियल सर्विस, रियल इस्टेट, ट्रैवल, होटल, मोटल आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें बेहतर संभानाएं हो सकती हैं. कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी कुछ शर्तों सहित मुफ्त देती हैं तो कई के लिए कंपनी को शुल्क अदा करना पड़ता है.

कैसे लें फ्रेंचाइजी

यदि आप अपना ख़ुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र यानी इंडस्ट्री तय कर लें. फिर संभावित व्यय और अपनी आर्थिक सक्षमता का आकलन कर लें. इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि किस इंडस्ट्री में किस कंपनी की फ्रेंचाइजी पर कितना पैसा लगेगा और आपकी उसका भार उठा सकते हैं या नहीं. इसके बाद कंपनी के फ्रेंचाइजर से मिलें. इंटरनेट पर सभी कंपनियों के संपर्क सूत्र दिए होते हैं, जिससे कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि का पता मिल जाता है. फ्रेंचाइजी फीस और अन्य शर्तों पर गौर करने के बाद जिस क्षेत्र के लिए आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसके कारोबार के तरीक़े को आंक लें. इसके बाद अंतिम फ़ैसला आपका ही होगा.

कंपनी का चुनाव कैसे करें

मंदी के दौर में शिक्षा का क्षेत्र ही पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है. हालांकि इसके लिए कोई लिखित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बाज़ार में गिरावट के बावजूद एजुकेशन फ्रेंचाइजर्स की गिनती जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखकर भी यही निष्कर्ष निकलता है. रिटेल क्षेत्र में भी बहार आई है. इसके अलावा फूड एंड बिवरेज के क्षेत्र में भी मंदी का असर नहीं दिखा है, बल्कि इसमें बढ़त ही देखी जा रही है. इसके अलावा वक्त के हिसाब से जैसे-जैसे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, वैसे ही रुचियां भी बदल रही हैं और इसी हिसाब से बदलता है मार्केट का स्वरूप. मार्केट के इसी हालात का जायजा लेकर कंपनी का चुनाव करना उपयुक्त है.

व्यय कैसे तय करें

फ्रेंचाइजी लेने का ख़र्च हज़ार से करोड़ों में आ सकता है और यह विविधता लगभग सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है. जैसे फूड एंड बिवरेज सेक्टर में एक कियॉस्क मॉडल जैसे स्टॉल की क़ीमत कुछ हज़ारों में होती है, जबकि बड़े ब्रांडेड फाइन डायनिंग रेस्त्रां के लिए करोड़ों रुपये लग सकते हैं. इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एबाकस एजुकेशन की फ्रेंचाइजी की क़ीमत एक लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, पर यदि किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ली जाए तो इसमें पचास लाख रुपये लग जाते हैं. ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें ख़ूब विस्तार हुआ है. मंदी के दौर में आम इंसान कम लागत में ज्यादा की उम्मीद रखता है, इस लिहाज़ से छोटे कियॉस्क का फ़ायदा कम नहीं है.

धोखे से बचें

भारत में फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री अभी नवोदित अवस्था में है और इससे संबंधित पूरी और सही जानकारी कुछ ही लोगों के पास है. कंपनियां इसी का फ़ायदा उठाकर अक्सर लोगों को ठगने में क़ामयाब होती हैं. मलेशिया में फ्रेंचाइजिंग के लिए अलग से क़ानून बनाए गए हैं, जबकि हमारे देश में इस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए अलग से कानून नहीं है. इसलिए धोखाधड़ी से बचने के लिए संबद्ध अधिकारी से पूरी बातचीत कर लें, हर प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर लें और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें. वैसे, हमारे देश में प्रतिवर्ष फ्रेंचाइजी प्लस एक्सपो लगता है, जहां से जानकारी लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त होकर इस काम की शुरुआत कर सकते हैं. एक्सपो में शामिल ना हो सकें, फिर भी इसकी बेवसाइट फ्रेंचाइजीप्लस डॉट कॉम से जानकारी लेकर या अधिकारियों के फोन नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं. इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.

संभावनाएं

एशियन फ्रेंचाइजी मार्केट से होने वाली आय प्रतिवर्ष 50 बिलियन अमरीकन डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ रही है और अनुमान के मुताबिक़ आनेवाले पांच सालों में यह बढ़कर 100 बिलियन अमरीकन डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगी. पिछले 4-5 सालों में भारत में फ्रेंचाइजी का ट्रेंड 30 से 35 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है और अब यह शीर्ष पर है. इस वक्त देश में तकरीबन 750 देसी-विदेशी कंपनियों की फ्रेंचाइजियां काम कर रही हैं. यह क्षेत्र अकेला लगभग 300,000 लोगों को सीधा रोजगार दिला रहा है. इसका कुल सालाना कारोबार 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है और लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. भारत की रिटेल इंडस्ट्री यानी ख़ुदरा उद्योग देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत है और कुल रोजगार में इसकी भागीदारी आठ प्रतिशत है. अनुमान है कि 2010 तक यह क्षेत्र 17 बिलियन अमरीकन डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा. पूरे देश में 500 से भी ज़्यादा नए बनते मॉल, 1500 से उपर बनते सुपरमार्केट और ना जाने कितने डिपार्टमेंटल स्टोर, इस क्षेत्र के सुनहरे भविष्य को पुख्ता करते हैं. विदेशी कंपनियां उद्यमी भारत के सभी राज्यों में फ्रेंचाइजी मार्केट को बढ़ावा देने में अग्रसर हैं.

ritika@chauthiduniya.com

शिक्षा के क्षेत्र में

- पिक्सलमेशन प्ले स्कूल- आजीवन फ्रेंचाइजी, जगह-1200 वर्गमीटर
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड- पत्राचार द्वारा विभिन्न विषयों में प्रबंधन कोर्सेस, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा- 3, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-1800 वर्गमीटर
- द ब्रेन वे- स्कूली बच्चों के लिए पूरक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेस
- एस टी सी टेक्नोलॉजी-सॉफ्टवेयर टेस्टींग इंडस्ट्री में अग्रसर, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-2, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-750 वर्गमीटर
- पिकासो डिजिटल मीडिया- एनिमेशन प्रशिक्षण संस्थान, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-4, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-3500 वर्गमीटर
- मदर्स प्राइड- प्ले स्कूल, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, जगह-3000 वर्गमीटर
- किड्स गुरुकुल- 2-10 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशनल खिलौने, गेम्स, किताबों और सीडी की लाइब्रेरी, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-3, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-150 वर्गमीटर
- पीटी एजुकेशन- अंग्रेजी विषय के प्रशिक्षण के अलावा सेकेंड्री, टर्शियरी पाठ्यक्रमों के परीक्षाओं की तैयारी कराने में अग्रसर
- शेमरॉक स्कूल- बच्चों का स्कूल, जगह-2000 वर्गमीटर
- बचपन- बच्चों का स्कूल, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-5, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-2000 वर्गमीटर

फूड व बिवरेज के क्षेत्र में

- फूड फैक्ट्री स्लाइस पिज्जा- इटालियन फूड कॉर्नर, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-5, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-150 वर्गमीटर
- एम/एस अंकल फूड प्रोडक्ट्स- स्नैक्स कॉर्नर, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-100 वर्गमीटर
- विजयनबिज- साइथ इंडियन फूड कॉर्नर, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-2000 वर्गमीटर
- जे कार्ट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्रा.लि.- होम डीलिवरी के साथ स्वास्थ्यवर्द्धक सलाद, स्मूथी, सूप, जूस बार, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-25 वर्गमीटर
- बेबे दा ढ़ाबा- भारतीय व्यंजन दरबार, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-20 वर्गमीटर
- कूल कुल्फी अशर्फी- मीठी व शुगर-फ्री मलाई, पिस्ता, बादाम इत्यादि कुल्फी ठेली, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-10 वर्गमीटर

रिटेल के क्षेत्र में

- एक्वेरियम वर्ल्ड- घरों, दफ्तरों व अन्य जगहों के लिए हर प्रकार का डिजाइनर ऐक्वेरियम, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-5, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-200-300 वर्गमीटर
- स्मार्ट शॉप 108 प्रा. लि.- वन स्टॉप शॉप, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-2, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-280वर्गमीटर
- डायागोल्ड- जीएम सोना, चांदी, अमरीकन डायमंड, जादू आर्ट ज्वेलरी की शोरूम, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-200 वर्गमीटर
- बुक कैफे- किताब की दुकान, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट
- किंडर स्पेस- बच्चों के फर्नीचर और फर्नीशिंग की सप्लाई व वन स्टॉप शॉप, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट,जगह-200 वर्गमीटर
- स्वास्तिक क्रिएशंस- महिलाओं के वेस्टर्न कपड़ों के थोक व ख़ुदरा जगह, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह-1500 वर्गमीटर
- क्रेजी प्राइसिंग- ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रेंचाइजी वर्ष सीमा-आजीवन, नवीकरणीय प्रोजेक्ट, जगह- 250 वर्गमीटर

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लक्ष्मण ने अपने करियर की कुछ सबसे बेहतरीन पारियां खेली हैं, लेकिन 35 साल की उम्र में उनकी परिपक्वता और कलात्मक बल्लेबाज़ी टीम के मध्य क्रम की सबसे मज़बूत कड़ी बन चुकी है.

टीम इंडिया की वेरी-वेरी स्पेशल जीत

पांच अक्टूबर का वह मंगलवार का भारतीय खेल जगत के लिए वैसे ही स्पेशल था जिसे लक्ष्मण की बल्लेबाज़ी ने वेरी–वेरी स्पेशल बना दिया. एक ओर राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट गोल्ड मेडल की बरसात कर रहे थे तो दिल्ली से थोड़ी दूर मोहाली के पीसीए स्टेडियम में वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की बादशाहत की एक नई कहानी लिख रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले मुक़ाबले में जीत के लिए 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करती भारतीय क्रिकेट टीम हार के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन लक्ष्मण ने ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर कंगारू टीम को निश्चित लगती जीत से दूर कर दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग की भारतीय सरजमीं पर टेस्ट मैचों में जीत के इंतज़ार को तो उन्होंने बढ़ा ही दिया, टीम इंडिया को 1–0 की अपराजेय बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे. टेस्ट मैचों में कलात्मक बल्लेबाज़ी का ऐसा नमूना शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो. मैच के पांचवें दिन लक्ष्मण जब मैदान पर बल्लेबाज़ी के लिए उतरे तो भारतीय टीम केवल 76 रनों पर पांच विकेट खो चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया को जीत का अंदेशा होने लगा था और उसके खिलाड़ी पूरे जोश में थे. लक्ष्मण ने तेंदुलकर के साथ मिलकर आक्रमण की नीति अपनाई. दोनों ने केवल 37 गेंदों में 43 रन ठोंक डाले और जीत का फासला सौ रन से कम हो गया. लेकिन 119 के स्कोर पर तेंदुलकर पेवेलियन लौट गए और उनके पीछे धोनी एवं हरभजन भी चलते बने. 8 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया से जीत अभी भी 92 रन दूर थी. लेकिन लक्ष्मण एक छोर पर डटे रहे और ईशांत शर्मा के रूप में उन्हें ऐसा जोड़ीदार मिल गया जो टिक कर खेलने को तैयार था. ईशांत ने एक–एक दो–दो रन लेकर लक्ष्मण का बख़ूबी साथ दिया. लंच के दोनों ओर यह साझेदारी 21.4 ओवर तक चलती रही और भारत का स्कोर दो सौ रन के पार पहुंच गया. अब जीत का फासला 11 रन दूर था और कंगारू टीम मैदान पर हताश दिखने लगी थी. उनकी इस हताशा को अंपायर बिली बॉडन के एक फ़ैसले ने नई उम्मीद दे दी जब उन्होंने ईशांत को एलबीडब्ल्यू क़रार दिया. लेकिन लक्ष्मण ने हिम्मत नहीं हारी और प्रज्ञान ओझा के साथ मिलकर कंगारुओं को जीत से मरहूम का दिया. टेस्ट मैचों में भारत की यह सबसे क़रीबी जीत थी. ईशांत शर्मा ने बल्लेबाज़ी में तो कमाल किया ही, गेंदबाज़ी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में लगातार तीन विकेट लेकर उन्हें 192 रनों के स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. ज़हीर ख़ान ने दोनों पारियों में कुल 8 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने. लेकिन असली हीरो तो लक्ष्मण ही रहे जिन्होंने 73 रनों की नाबाद पारी खेल टीम की नैया पार लगाई. ताज्जुब की बात तो यह है कि जीत के दोनों नायक, लक्ष्मण और ईशांत, चोटिल थे. लक्ष्मण पहली पारी में चोट से इतने परेशान थे कि दसवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने के लिए आए और केवल तीन गेंद खेलने के बाद आउट हो गए. दूसरी पारी में भी उनका खेलना तय नहीं था, लेकिन पांचवें दिन ज़हीर ख़ान के पेवेलियन लौटते ही वह बल्लेबाज़ी के लिए उतरे और मैच जिता कर ही दम लिया.

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लक्ष्मण ने अपने करियर की कुछ सबसे बेहतरीन पारियां खेली हैं, लेकिन 35 साल की उम्र में उनकी परिपक्वता और कलात्मक बल्लेबाज़ी टीम के मध्य क्रम की सबसे मज़बूत कड़ी बन चुकी है. पिछले कुछ महीनों में लक्ष्मण ने एक के बाद एक कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं. श्रीलंका के ख़िलाफ़ पिछली सीरीज़ में भी उन्होंने चौथी पारी में शतक लगा कर टीम को जीत दिलाई थी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही साल 2001 में 281 रनों की उनकी पारी को टेस्ट मैचों में सर्वकालीन महानतम पारियों में गिना जाता है. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुछल्ले बल्लेबाज़ों में भी टिके रहने का विश्वास जगाने में सफल होते हैं और टीम की जीत का रास्ता तैयार करते हैं. टीम इंडिया की यह जीत टेस्ट क्रिकेट में उसकी बादशाहत का और भी ज़्यादा पुख्ता करता है क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मज़बूत टीम को हराया जो हाल के दिनों तक दुनिया की नंबर वन टीम थी. फिर उसने मोहाली के मैदान पर अपने अपराजेय रिकॉर्ड को भी बरक़रार रखा. टीम की हालिया जीतों में एक नई बात यह देखने को मिली है कि इनमें हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाई है. मोहाली टेस्ट में ईशांत शर्मा ने तीन विकेट भले लिए, लेकिन पूरे मैच में अपनी फॉर्म के लिए भटकते रहे और लगातार नो–बॉल करते रहे. लेकिन उन्होंने इसकी भरपाई बल्लेबाज़ी में कर दी. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ प्रज्ञान ओझा को भी तीन विकेट ही मिले लेकिन उन्होंने एक छोर से रनों की गति पर लगातार अंकुश लगाए रखा. यह अच्छा संकेत है लेकिन खिलाड़ियों का बार–बार चोटिल होना टीम के लिए चिंता का विषय है. इससे न केवल टीम कॉम्बिनेशन पर बुरा असर पड़ता है बल्कि उसका मनोबल भी प्रभावित होता है.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 15,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 50,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

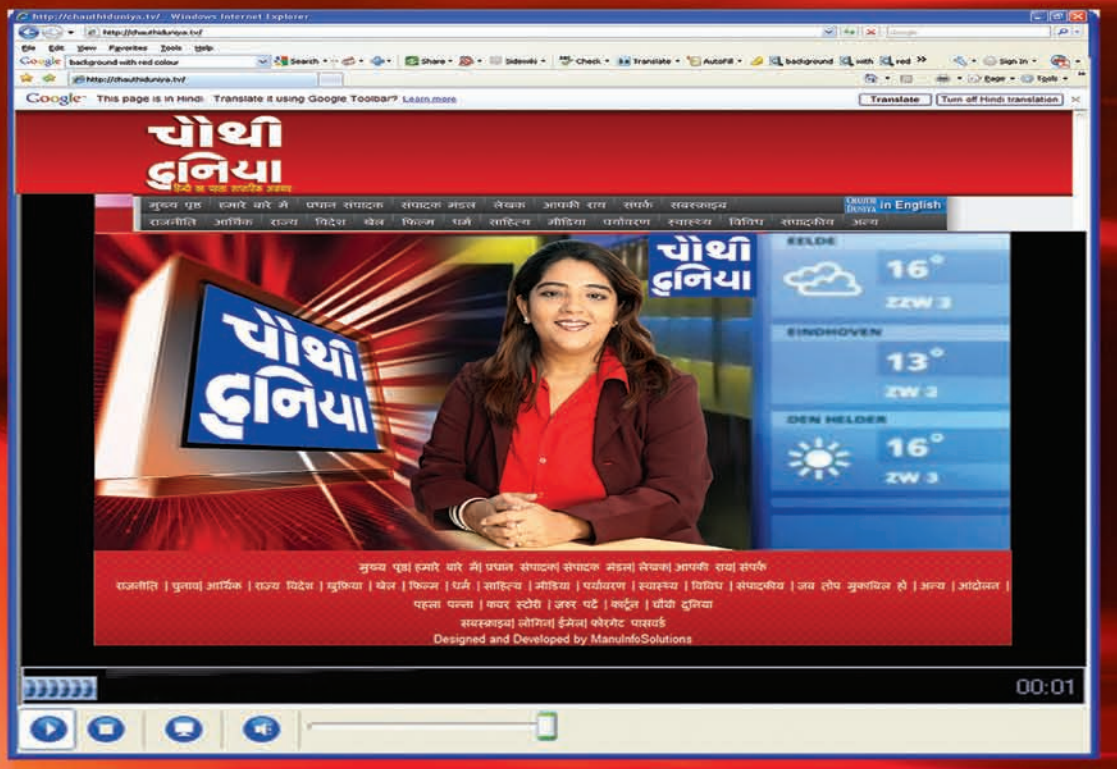

www.chauthiduniya.tv

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 अक्टूबर–24 अक्टूबर 2010

मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में कंगना ने मालफंक्शन सीन दिया था, जिसमें उनका टॉप हट जाता है.

हॉलीवुड में भारत का उड़ता मज़ाक़

प्रियंका प्रियम तिवारी

आज के दौर में जहां हमारे रहन-सहन और विचार पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से भी पश्चिम के लोग कम प्रभावित नहीं हैं. उनके जीवन में खान-पान, पहनावा और यहां तक कि फिल्मों में भी अब सहज ही हिंदू धर्म का प्रभाव और इसके प्रतीकों के व्यापक इस्तेमाल को देखा-समझा जा सकता है. अगर बात हॉलीवुड फिल्मों की हो तो यहां भी हिंदू धर्म और इसके प्रतीकों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि इसके पीछे मकसद विशुद्ध व्यापारिक ही होता है. और यही वजह है कि कई बार इन फिल्मों के माध्यम से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. इस चलन का हालांकि एक व्यावसायिक पक्ष भी है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है. और शायद यह भी एक बडी वजह है कि हॉलीवुड फिल्मों में हिंदू प्रतीकों का जम कर इस्तेमाल हो रहा है. शायद यह सोच कर भी कि विवाद से मुफ्त प्रचार और फिर उससे ढेर सारी कमाई हो जाएगी.

हॉलीवुड की सोनी पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स, डिजनी, पैरामाउंट और मोशन पिक्चर्स जैसी कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनिया भारत में सक्रिय रूप से काम कर रहीं हैं. विदेशी प्रोडक्शन कंपनियों में भारत और हिंदू धर्म को परदे पर दिखाने के प्रति रुचि बढ़ी है.

हिंदू धर्म को हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने के पीछे एक और दिलचस्प कारण है. विदेशियों के लिए आज भी भारत की बहुत से चीजें अपरिचित, आकर्षक, विचित्र और विविधता लिए हुए है. हिंदू धर्म काफी समृद्धशाली है, इसमें प्रयोग की अपार संभावनाएं है. हॉलीवुड में हो रहे प्रयोगों से इस धर्म का प्रभाव व्यापक तौर पर बढ़ा है. इससे सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना सत्य होती है, हमें एक-दूसरे के धर्म को जानने का मौका मिलता है, पर कई बार सृजनशीलता के चक्कर में ऐसी चीजें भी पेश कर दी जाती हैं, जो हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करती हैं. साथ ही अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच भी उस धर्म विशेष के प्रति तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं. इसके कई उदाहरण हॉलीवुड में देखे जा सकते हैं :

आइज वाइड शट : श्रीलंकाई तमिल कर्नाटक शैली के गायक मानिकराम योगेश्वरन से लंदन के एक स्टूडियो में जब गीता के श्लोक गाने के लिए कहा गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें विश्व स्तर पर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था. पर इसका इस्तेमाल स्टेनले क्यूब्रिक के निर्देशन में बनी विवादित फिल्म आइज वाइड में टॉम क्रूज और निकोल किडमैन के अंतरंग दृश्यों के फिल्मांकन में किया गया.

योगेश्वरन को पता भी नहीं था कि उनके द्वारा गाए श्लोक का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा. पूर्व और पश्चिम के बीच का यह मेल कई लिहाज से अच्छा है. इससे कला का एक नया और बेहतर स्वरूप सामने आ सकता है, लेकिन इस तरह के फ्यूजन हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं. गीता के श्लोकों का इस तरह के दृश्यों के साथ जोड़ा जाना किसी लिहाज से सही नहीं है. गीता के श्लोक, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च...युगे युगे को फिल्म से हटाने की मांग की गई. अमेरिका में दक्षिण एशियाई पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस संदर्भ में कहा कि हिंदू धर्म के प्रतीकों का रूपांकन हल्के अंदाज में किया जा रहा है, जबकि इस तरह का व्यवहार अन्य धर्मों से संबंधित विषयों-प्रतीकों के साथ नहीं किया जाता.

होली स्मोक : इसी कड़ी में केट विंसलेट और हार्वे केटल अभिनीत फिल्म होली स्मोक को भी कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. इसकी भारत में शूटिंग को लेकर कहा गया कि इसमें हिंदू धर्म को नास्तिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है.

नाइन लाइव्स : विश्व प्रसिद्ध सोनी म्यूजिक ने वर्ष 1997 में नाइन लाइव्स सीडी निकाली थी. इसमें भगवान कृष्ण को अपमानजनक मुद्रा में दिखाया गया था. भगवान कृष्ण के सीने से ऊपर का हिस्सा बिल्ली का था.

इंडियाना जोंस एंड टेंपल ऑफ डूम : स्पिलबर्ग ने इंडियाना जोंस और द टेंपल ऑफ डूम में दो औरतों के चित्र दिखाए, जिसमें एक को विदूषक और दूसरी को दुष्टात्मा के रूप में दिखाया गया. सर्वविदित है कि हिंदू धर्म में देवी काली को बुराइयों को खत्म करने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन स्पिलबर्ग ने उन्हें दानवी के रूप में दर्शाया.

मडोना : वर्ष 1998 में एमटीवी अवार्ड समारोह के दौरान मडोना ने खुद को भगवान शिव की वेशभूषा में प्रस्तुत करके अंतराष्ट्रीय फैशन जगत में हलचल मचा दी थी. मडोना ने इस बात को काफी भुनाया.

टूडी स्टेलर : हाल में लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस के तिब्बती पीस गार्डेन में पॉप स्टार स्टींग्स की पत्नी टूडी स्टेलर एक ऐसी स्कर्ट में दिखी, जो भगवान गणेश के परिधानों की डिजाइन पर आधारित थी. इस ड्रेस की तारीफ तो हुई, पर ऐसे वस्त्रों पर हिंदुओं के देवी-देवताओं के चिन्हों-प्रतीकों का इस्तेमाल धर्म विरुद्ध है.

जेना: वॉरियर प्रिंसेस : 1999 के फरवरी माह में दुनिया के सबसे मशहूर टीवी सीरियलों में से एक जेना: वॉरियर प्रिंसेस में कृष्ण, हनुमान, काली और इंद्रजीत जैसे हिंदू देवताओं को इस अंदाज में दिखाया गया, जिसकी चर्चा हमारे धर्मग्रंथों या किंवदंतियों में कहीं नहीं है.

माइक मायर : वर्ष 1999 के अप्रैल माह में वैनिटी फायर के लिए फोटोग्राफर डेविड ला चैपल माइक मायर के शॉट्स ले रहे थे. इन शॉट्स में माइक मायर ने हिंदू देवी-देवताओं की वेशभूषा में एक कार्टूनिस्ट की तरह पोज दिया था. दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ के सदस्यों ने इसकी निंदा की और कहा कि यह हिंदू देवी-देवताओं का घोर अपमान है, पर न्यूज वीक ने इस संदर्भ में सफाई दी कि हो सकता है, इस समय हॉलीवुड हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहा हो.

priyanka@chauthiduniya.com

कॉमेडियन कंगना

संजय दत्त और इरफान ख़ान स्टारर फिल्म नॉक आउट में कंगना राणावत एक टेलीविजन रिपोर्टर की भूमिका में हैं. फिल्म नॉक आउट के लिए उनके नाम की सिफ़ारिश ख़ुद संजय दत्त ने की थी. इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया है. आजकल संजय एंड फैमिली से कंगना की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई हैं. मान्यता की गोद भराई के मौक़े पर कंगना भी मौजूद थीं. इस मौक़े पर कंगना की ड्रेस चर्चा का विषय रही. हुआ यह कि उन्होंने ख़ूबसूरत सलवार-कमीज पहन रखा था, लेकिन पार्टी के दौरान उनकी ड्रेस बगल से खुल गई, जिससे उनके शरीर का काफ़ी हिस्सा दिखाई देने लगा. कंगना ने इसे छुपाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक फोटोग्राफर के कैमरे के फोकस में आने से बच नहीं पाईं और वह फोटो सार्वजनिक हो गया.

इसतरह का सीन रील लाइफ में कंगना ने फिल्म फैशन में दिया था, जिसमें उनका टॉप हट जाता है. उस दौरान फैशन जगत में शो की कामयाबी के लिए ऐसे सीन लगातार क्रिएट किए जा रहे थे. कंगना अपनी पहली ही फिल्म गैंगस्टर से दर्शकों की चहेती बन गई थीं. इसके बाद फिल्म वो लम्हे में पुन: उन्होंने दर्शकों का ख़ास अटेंशन बटोरा. इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने संजीदा अभिनय किया. कंगना ने अनुराग बसु की प्रस्तावित फिल्म साइलेंसर में काम करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि वह एक ही तरह के रोल में नहीं बंधना चाहती हैं. इंडस्ट्री में कॉमेडी फिल्मों की कामयाबी को देखते हुए अन्य कलाकारों की तरह कंगना भी कॉमेडी की डगर पर निकल पड़ी हैं. वह एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं. अपनी अगली फिल्म नो प्रॉब्लम में वह दर्शकों को हंसाती नज़र आएंगी. उनकी आने वाली प्रमुख फिल्में हैं नॉक आउट, नो प्रॉब्लम, तनु वेड्स मनु, रास्कल्स और वन एंड ओनली. इन फिल्मों से कंगना को काफ़ी उम्मीदें हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

रक्त चरित्र

राजनीति और हिंसा की पृष्ठभूमि पर सत्या, कंपनी और सरकार जैसी कई सफल फिल्में बना चुके रामगोपाल वर्मा अब अपनी अगली फिल्म रक्त चरित्र लेकर आ रहे हैं. उन्होंने इसे दो हिस्सों में फिल्माया है. इसका दूसरा पार्ट कुछ सप्ताह बाद रिलीज होगा. कहा जा रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. रक्त चरित्र साउथ के राजनेता परितला रवि की सच्ची कहानी है. रवि ने 1997 में हैदराबाद के रामा नायडू स्टूडियो के बाहर बम धमाकों के जरिए ख़ूनी खेल को अंजाम दिया था. इस हादसे में जान गवां चुके अपने पिता और भाई का बदला लेते हुए सूरी ने 2005 में रवि को मौत के घाट उतार दिया था. सूरी आज भी अनंतपुर जेल में सज़ा काट रहा है. फिल्म में रवि का किरदार विवेक ओबराय ने निभाया है और सूरी के रोल में साउथ के सुपर स्टार सूर्या हैं. सूर्या की यह पहली हिंदी फिल्म है, लेकिन वह बॉलीवुड के लिए अपरिचित नहीं हैं.

अपने शासनकाल में हुए इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन टी रामाराव ने ली थी. फिल्म में एन टी रामाराव के किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो उनके काफ़ी क़रीबी रहे थे. फिल्म में परितला रवि को एक तरफ जहां शांतिप्रिय, सदाचारी और दयावान दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ उनमें छुपे हैवान को दिखाया गया है, जो अपराध की दुनिया का बादशाह है और बेदर्दी से ख़ूनी खेल को अंजाम देता है. उसके लिए इंसान की ज़िंदगी की कोई क़ीमत नहीं है. पढ़ा-लिखा और शालीन परिवार का होने के बावजूद वह ऐसी हैवानियत भरी वारदातों को अंजाम देता है. दूसरी तरफ फिल्म का नायक सूर्या है, जो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है. वह अकेला लड़ता है और बुराई का अंत करके ख़ुद को क़ानून के हवाले भी कर देता है.

हिंदी में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा हैं. लेखक प्रशांत पांडेय हैं और सिनेमेटोग्राफर अमोल राठौर. मुख्य कलाकार हैं विवेक ओबराय और सूर्या. सहायक कलाकार हैं आशीष विद्यार्थी, अभिमन्यु शेखर सिंह, अनुपम श्याम, प्रियामणि, शत्रुघ्न सिन्हा, सुशांत सिंह एवं जरीना वहाब. यह फिल्म 22 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 18 अक्टूबर–24 अक्टूबर 2010

www.chauthiduniya.com

राजनैतिक दलों का संदेश

कार्यकर्ता बस झंडा ढोएंगे

बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, पर पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की जगह पुलिस तैनात है. ज़िंदाबाद के नारों की जगह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं. फूल की जगह पत्थर बरस रहे हैं. यह सब इसलिए कि बड़े नेताओं ने टिकट बंटवारे में ऐसी रिश्तेदारी निभाई कि आम कार्यकर्ता ठगा सा रह गया.

सरोज सिंह

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वामदलों को छोड़ दें तो कोई ऐसा दल नहीं बचा जहां टिकट बंटवारे के बाद बवाल न हुआ हो. स्थानीय नेता अपनी वफ़ादारी और जीतने की दुहाई देते देते थक गए पर टिकट नसीब न हुआ. उस पर पहला हक़ लोकतंत्र के नए राजाओं का ही माना गया. अपनी निष्ठा की मजदूरी का मेहनताना मांगने वाले कार्यकर्ता ख़ुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. इन अशांत लोगों में से कुछ शांत हो गए, कुछ भीतरघात में लगे हैं तो कुछ बाग़ी होकर चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं. अब धन, बल और राजनीतिक विरासत के राजाओं से उनका सामना है. जनता को तय करना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजा और प्रजा के बीच की दूरी ख़त्म होगी या फिर बढ़ेगी. इस चुनाव में टिकट बंटवारे से इतना तो साफ़ हो गया कि कम से कम बड़े नेता तो यह नहीं चाहते कि प्रजा विधानसभा जाने में राजा का रास्ता रोके. पहले राजा अपना सफ़र तय कर लें, प्रजा के बारे में बाद में सोचा जाएगा. दो टूक बात यह है टिकट बंटवारे से यह साफ़ हो गया कि बिहार की राजनीति पूरी तरह बड़े नेताओं की बपौती बनकर रह गई है. वे ख़ुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके रिश्तेदार. उसके बाद अगर जगह बची तो उनके आगे पीछे घूमने वालों को जगह मिलेगी. ज़मीन से जुड़े नेता व सालों तक पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका महज़ ज़िंदाबाद व मुर्दाबाद करने तक ही सीमित रहेगी.

टिकट बंटवारे की इस पूरी कवायद को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि जिस किसी बड़े नेता के पुत्रों या फिर अन्य रिश्तेदारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, उनमें ज़्यादातर किसी न किसी दल से इस समय चुनावी अखाड़े में हैं. पहली कोशिश अपने ही दल से टिकट दिलाने की रही, पर जब बाजी हाथ से निकलने लगी तो नैतिकता का नाटक और अंसतोष का दिखावा कर अपने संतानों व संबंधियों को दूसरे दलों से टिकट दिलवा दिया. दरअसल बिहार में इस बार कुछ नए राजनीतिक प्रयोगों को मान्यता मिली. आप सांसद किसी दल के हों, पर प्रचार दूसरे दल का कर सकते हैं. आप अगर अपनी पार्टी से अपने चहेतों को टिकट नहीं दिला सकते तो दूसरे दलों से दिला सकते हैं. मतलब राजा तो आगे जाएगा ही, भले ही उसे अपनों की छाती रौंद कर जाना पड़े. परिवारवाद का विरोध कर हीरो बनने वाले कई नेता भी इस बार अपने परिवार के लिए हर हद पार कर गए. कुछ ख़ास उदाहरणों से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं.

रामविलास पासवान पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, पर इस बार उनके मामा रामसेवकर हजारी ने उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ दिया है. इस काम में उनके सांसद पुत्र महेश्वर हजारी ने उनका पूरा साथ दिया. रामसेवक हजारी ख़ुद कल्याणपुर से जदयू के प्रत्याशी बने हैं जबकि महेश्वर हजारी की भाभी मंजू हजारी रोसड़ा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं हैं. उनके एक रिश्तेदार शशिभूषण हजारी को कुशेश्वरस्थान से भाजपा का टिकट मिला है. इनके अलावा भी बिहार की कुछ सीटों पर हजारी परिवार के शुभचिंतकों को टिकट से नवाजा गया. रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस पहले भी अलौली से चुनाव लड़ते रहे हैं पर इस बार उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी कुशेश्वरस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं. रामविलास पासवान के दामाद साधू जी मसौड़ी से तो इनके भांजे की पत्नी सरिता पासवान सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रही हैं. राजद सांसद जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को जब रामगढ़ से टिकट न मिला तो उन्होंने भाजपा का कमल अपना लिया और चुनावी अखाड़े में कूद पड़े. इसी तरह जदयू सांसद महाबली सिंह के पुत्र राजद के टिकट पर भाग्य आज़मा रहे हैं. मंत्री नरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र अजय प्रताप सिंह जमुई से जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं तो छोटे पुत्र सुमित कुमार सिंह झामुमो के टिकट पर चकाई से भाग्य आज़मा रहे हैं. बाहुबली नेताओं को जब कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उनकी पत्नियों ने मोर्चा संभाल लिया. आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आलमगर से, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला वैशाली से तो पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन बिहारीगंज से चुनाव लड़ रही हैं. सूरजभान सिंह के भाई ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मोकमा से तो उनके एक अन्य रिश्तेदार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. नागमणि ख़ुद मोरवा से चुनाव लड़ रहे तो उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर कुर्था से चुनाव मैदान में है. जहां तक टिकट वितरण की बात है तो इस बार प्रभुनाथ सिंह की भी चांदी रही. प्रभुनाथ सिंह के समधी विनय सिंह सोनपुर से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए. इसी तरह मांझी विधानसभा से प्रभुनाथ सिंह के चचेरे बहनोई मंत्री गौतम सिंह चुनावी मैदान में जदयू के टिकट पर किस्मत आज़मा रहे हैं. उनके एक और क़रीबी हेमनारायण सिंह राजद के टिकट पर खड़े हैं. प्रभुनाथ सिंह के ख़ास छोटेलाल राय जदयू से लड़ रहे हैं. प्रभुनाथ के छोटे भाई केदारनाथ सिंह भी चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं. तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज जदयू के टिकट पर जोकीहाट से लड़ रहे हैं. इनके अलावा पूर्व मंत्री व पिछले चुनाव तक विधान पार्षद रहे अजीमुद्दीन के पुत्र पूर्व ज़िला पार्षद अध्यक्ष पप्पू अजीम सिकटी से मैदान में हैं. पप्पू अजीम की पत्नी शगुफ़्ता अजीम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है. सांसदों व पूर्व सांसदों ने भी इस बार अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए कई बंधन तोड़ दिए. सुपौल से सांसद विश्वमोहन कुमार की पत्नी सुजाता देवी पिपरा से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं. इसके अलावा रामसुंदर दास, जगदीश शर्मा, हुकुमनारायण सिंह यादव, रघुनाथ झा, पूर्णमासी राम व अली अशरफ फातमी के बेटे भी इस चुनाव में भाग्य आज़मा रहे हैं. मोनाजिर हसन जदयू के सांसद हैं पर अपनी पत्नी को मुंगेर से राजद का टिकट दिलाने में सफल रहे. शकुनी चौधरी ख़ुद तारापुर से लड़ रहे हैं तो उनके बेटे सम्राट चौधरी परवत्ता से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. जयप्रकाश यादव बांका से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं तो उनके छोटे भाई विजय प्रकाश जमुई से विधानसभा के लिए किस्मत आज़मा रहे हैं.

दरअसल बिहार में इस बार कुछ नए राजनीतिक प्रयोगों को मान्यता मिली. आप सांसद किसी दल के हों , पर प्रचार दूसरे दल का कर सकते हैं. आप अगर अपनी पार्टी से अपने चहेतों को टिकट नहीं दिला सकते तो दूसरे दलों से दिला सकते हैं. मतलब राजा तो आगे जाएगा ही, भले ही उसे प्रजा की छाती रौंद कर जाना पड़े. परिवारवाद का विरोध कर हीरो बनने वाले कई नेता भी इस बार अपने परिवार के लिए हर हद पार कर गए.

ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि बिहार के बड़े नेताओं ने कैसे यहां की चुनावी राजनीति को हाईजैक कर लिया है. एक दूसरे के रिश्तेदारों को टिकट देने में सारे दलों के बड़े नेताओं ने दिल खोल दिया. ऐसे नेता जो दो दिन पहले पार्टी में आए और टिकट पा गए. कार्यकर्ता देखते रह गए. रोने के लिए जब कोई कंधा नहीं मिला तो पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाया और धरने पर बैठ गए. लेकिन लोकतंत्र पर रिश्तेदारों का बोझ देख उनकी आह कलेजा दहला दे रही है. भाजपा कार्यालय पर धरना दे रहे बछवाड़ा के एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि अपने ही लोग घर में डाका डालें तो शिकायत किससे करें. लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता. लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है तो अपनों की कुर्बानी देनी ही होगी. अपनों से उसका मतलब अपनी पार्टी के ही ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने से था. बात सही भी है, जिस तरह से टिकट पर बड़े नेताओं ने क़ब्ज़ा जमाया उससे तो यही लगता है कि राजनीति में आम लोगों की संभावना लगभग ख़त्म हो गई है. छोटे नेता व कार्यकर्ता केवल आगे–पीछे की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित रहेंगे. अगर यही चलता रहा तो आगे भी रानी के पेट से ही राजा पैदा होते रहेंगे और लबादा लोकतंत्र का होगा.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक दलों की चुनावी पैंतरेबाज़ी को राज्य का मुस्लिम मतदाता चुपचाप बड़ी बारीकी से देख रहा है. थोड़ा बहुत असमंजस भी है.

बसपा ने राज नारायण प्रसाद गुप्ता उर्फ़ मुन्ना जी को अपना उम्मीदवार बनाकर सिग्रीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

चुनावी तड़का

बैठे बैठाए मिलेंगे वोट

पुरानी कहावत है कि दो के झगड़े में तीसरे को फ़ायदा मिल जाता है. सुशीला देवी को लोजपा टिकट मिलने से उनसे ख़फ़ा कुछ नेताओं ने इ.धर्मेंद्र को मदद करने का ऐलान कर दिया है. राजद नेता प्रफुल्ल चंद्रघोष ने बग़ावती तेवर अपनाते हुए धर्मेंद्र के पक्ष में वोटरों की गोलबंदी शुरू कर दी है. नतीजा क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा लेकिन अंतिम समय तक अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर नहीं हुई तो धर्मेंद्र को बैठे बिठाए फ़ायदा मिल सकता है.

धोखा दिया, अब भुगतो

कहते हैं कि राजनीति में कब कौन किसका दामन छोड़कर किसके साथ रिश्ता जोड़ लेगा, यह कोई नहीं जानता है. अब लोजपा नेता और खगड़िया के वार्ड आयुक्त मो. शहाबुद्दीन को ही ले लीजिए, जनाब खगड़िया विधानसभा से लोजपा का टिकट चाहते थे. लोजपा ने पहले भरोसा भी दिलाया लेकिन अंतिम समय में पार्टी सुप्रीमो ने उन्हें बेटिकट कर दिया. गुस्से में तिलमिलाए और बग़ावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. शहाबुद्दीन अपने मंसूबों में कितने सफल हो सकेंगे, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी लेकिन इतना तय है कि मुस्लिम समाज के साथ–साथ अन्य बिरादरी में अच्छी पकड़ के चलते कई अन्य प्रत्याशियों का बेड़ा गर्क तो कर ही देंगे. शहाबुद्दीन कहते हैं कि पार्टी नहीं अपितु जनता मालिक होती है. हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, फ़ैसला जनता करेगी.

हम तो दूल्हा छोड़ के बैठे हैं

टिकट के इंतजार में एक पार्टी कार्यालय में बैठी कुछ महिला प्रत्याशियों का दर्द सुनिए. साहेबगंज की प्रत्याशी कह रही थी, लू में चेहरा जलाकर कांग्रेस का झंडा घर–घर ले गए. चूड़ा बांटे साड़ी बांटे. बाल बच्चा को छोड़ दिल्ली तक गए, लाखों ख़र्च हुआ पर जब टिकट देने की बारी आई तो एक नेता मैडम का पैर पकड़ कर टिकट ले उड़े. इतने पर लोजपा से ख़फ़ा एक महिला नेता ने कहा वैशाली से टिकट देने की बात थी पर उपर से नेता टपक गई. क्या नहीं किया, दूल्हे तक को छोड़कर पटना में बैठे पर सब चौपट हो गया. देखिएगा आह ज़रूर लगेगी.

एशिया की सबसे बड़ी बनमनखी चीनी मिल
नीतीश वादा करके भूल गए

चौथी दुनिया ने पूर्णियां ज़िले की बनमनखी चीनी मिल की बदहाली पर आलेख लिखा था. एक समय में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कही जाने वाली यह मिल बिहार सरकार की उदासीनता की वजह से खुल नहीं सकी थी. चौथी दुनिया ख़बर प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने इस मिल खुलवाने के लिए कोलकाता की कंपनी एलएम इंटरनेशनल से 90 सालों का समझौता किया है. यह मिल सरकार द्वारा 26.24 करोड़ की उच्चतर निविदा पर सौंपी गई है. अब 1997 से बंद पड़ी इस मिल के खुल जाने से चार हज़ार से ज़्यादा स्थानीय बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सकेगा. मिल के शुरू होने की घोषणा से बनमनखी के आसपास के इलाक़े में गन्ने की पैदावार में किसान फिर से एकजुट होते नज़र आने लगे हैं. इलाक़े के किसानों का कहना है कि मिल के बंद होने से सैंकड़ों किसानों की 132 लाख से अधिक की राशि बकाया रह गई थी. अब उनकी बकाया राशि मिलने की उम्मीद है.

ख़बर का असर

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नरेंद्र मोदी से दूर कहां हैं नीतीश : तारिक़ अनवर

देश में युवा राजनीति को पहचान देने वाले एनसीपी के वरिष्ठ नेता तारिक़ अनवर इन दिनों युवाओं के राजनीतिक भटकाव को लेकर काफ़ी चिंतित हैं. वह मानते हैं कि बड़े नेताओं ने युवा शक्ति को जातीय दायरे में बांट कर युवाओं को अपने हक़ से वंचित कर दिया है. टिकट को लेकर हुए हंगामे को तारिक़ साहब राजनीति में बढ़ रही धनशक्ति का दुष्परिणाम मानते हैं. बिहार की बदहाली के लिए लालू व नीतीश को वह बराबर का दोषी मानते हैं और यह राय रखते हैं कि बिहार का वास्तविक विकास तभी होगा जब यहां पूंजीनिवेश का रास्ता खुलेगा, बिजली होगी और कल कारखानों का जाल बिछेगा. प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ ख़ास अंश.

नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए.

नीतीश कुमार ने मुसलमानों को ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं दे पाए थे. वह पूरी कौम का भला क्या करेंगे. जो मंत्री थे, उन्हें भी निकाल दिया गया. अभी टिकट बंटा है, देख लीजिए क्या हाल है. आम मुसलमानों की दिक्कतों को समझने और सुलझाने का वक़्त उनके पास कहां है. उन्हें बस मुसलमानों का वोट चाहिए. लेकिन इस चुनाव में उनका भ्रम टूट जाएगा. मुसलमान सहित पूरे बिहार की जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है.

लेकिन मुसलमानों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी व वरुण गांधी को चुनाव प्रचार के लिए बिहार आने नहीं दिया.

नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार दूर कहां हैं. बिहार में दूरी बनाते हैं और दूसरे राज्य में साथ तस्वीर उतरवाते हैं. अगर मुसलमानों के ज़ख्मों का उन्हें इतना ही ख्याल है तो फिर भाजपा से नाता तोड़ क्यों नहीं लेते. क्या बिहार भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते. नरेंद्र मोदी के विचार व बिहार भाजपा के विचार अलग–अलग हैं. अगर दिल्ली में कभी एनडीए की सरकार बनेगी तो उसमें नरेंद्र मोदी के लोग या फिर वे ख़ुद नहीं होंगे. केवल चुनाव प्रचार में न बुलाने से मसला हल नहीं हो जाता. सरकार पांच साल चलती है, उसी दौरान नीतियां बनती है और काम होता है. भाजपा को साथ लेकर बनने वाली सरकार में मुसलमानों का भला होगा, यह सोचा भी नहीं जा सकता. धर्मनिरपेक्ष लोग भाजपा को बर्दाश्त नहीं कर सकते.

नीतीश कुमार के पांच साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं?

जनता को भारी निराशा हुई. बिहार की अवाम ने बिहार के विकास के जिस भरोसे से नीतीश कुमार को वोट दिया, उसे उन्होंने तोड़ दिया. पांच साल तक केवल बयानबाजी होती रही और जनता के बुनियादी मसले दरकिनार कर दिए गए. एक पैसे का पूंजीनिवेश नहीं हुआ, एक मेगावाट अतिरिक्त बिजली नहीं बनी और एक भी कल कारखाना नहीं खुला. कोई यह तो बताए कि इन चीजों को अलग कर विकास की कहानी लिखी जा सकती है? केंद्र सरकार से पैसा आया पर बिहार की सूरत नहीं बदल सकी. कुछ सड़कें बनीं, वह दो तीन सालों में टूट जाएंगी. फिर क्या कीजिएगा. जब तक अपना पैर मज़बूत नहीं किया जाएगा तब तक सही मायनों में विकास की बात सोचना बेमानी है. नीतीश कुमार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है. वह लालू का ही खेल खेल रहे हैं. जात पात में बिहार को बांटा गया और जनता की असली समस्या पीछे छूट गई. सूबे से आज भी बड़ी संख्या में पलायन जारी है. दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ जो सलूक होता है, सभी जानते हैं. हमारे बिहारी भाई अपमान का घूंट पीकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं. आज भी पढ़ाई के लिए हमारे बच्चों को दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ रहा है. बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है.

कल कारखाने व पूंजी निवेश न होने के लिए केंद्र सरकार पर ही दोष मढ़ा जा रहा है.

अपनी ग़लती व कमज़ोरियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं. केंद्र सरकार की नीतियां किसी एक राज्य के लिए नहीं बनाई जाती हैं. पूरे देश में एक ही नियम चलता है. इन्हीं नीतियों के अनुकूल प्रस्ताव बनाए जाते हैं. पर यहां तो नीयत ही साफ़ नहीं है तो नीतियां क्या करेंगी. केवल झूठे वादे कर जनता का वोट लेना है तो विकास कैसे ज़मीन पर उतरेगा.

बिहार में युवा राजनीति में भटकाव देखा जा रहा है. इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं?

दोनों की ग़लती है. युवा तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और लालू व नीतीश जैसे नेता इसी का फ़ायदा उठाते हैं. लालच देकर पहले उनकी सामूहिक ताक़त कमज़ोर करते हैं और उसके बाद उन्हें जातीय दायरे में लाकर बांध देते हैं. युवा शक्ति जातीय दायरे में जाकर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह चाहकर भी अपना हक़ नहीं ले पाती. मेरी राय है कि युवा ख़ुद को इस्तेमाल न होने दें और जातीय गोलबंदी की बजाए सामूहिक शक्ति बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.

आपकी पार्टी एनसीपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी?

विकास हमारा मुख्य मुद्दा होगा. नीतीश कुमार व लालू प्रसाद ने जात पात की राजनीति कर बिहार को विकास के पायदान पर काफ़ी पीछे खड़ा कर दिया है. हमारी पार्टी चाहती है कि बिहार में सही मायनों में विकास हो. पूंजीनिवेश हो, बिजली बने, कल कारखाने खुलें और पलायन रुके. पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो, ग़रीबों का अच्छा व सस्ता इलाज हो सके. इस पर हम ध्यान देंगे. घोषणा पत्र की जगह हम संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं. सरकार गठन में हम न लालू का साथ देंगे और न ही नीतीश का.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

अल्पसंख्यक मतदाता
वोट दे कर भी चोट खाते हैं हर बार

अशरफ अस्थानवी

बिहार विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. साथ ही सामान्य मतों की छीना–झपटी के लिए आम मतदाताओं को बहलाने, फुसलाने की होड़ भी मची हुई है. सभी दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए परेशान हैं. इन दलों के निशाने पर सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं. मुस्लिम मतदाताओं को पट्टी पढ़ाने में एक ऐसा राजनीतिक दल भी भिड़ा हुआ है जो मुसलमानों को अपने ही चश्मे से देखने और औकात में रखने के फॉर्मूले पर काम करता है. इसी कदमताल पर आगे बढ़ते हुए राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल ने अपने आप को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर खानकाहों के गद्दीनशीनों और मज़हबी रहनुमाओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं. दूसरी ओर ऐसे राजनीतिक दल भी ज़ोर आज़माइश में लगे हुए हैं, जो मुस्लिम मतदाताओं के बिना शर्त समर्थन वर्षों–वर्ष सत्तासीन रहे हैं. इनमें कांग्रेस बाबरी मस्जिद की शहादत से मर्माहत मुसलमानों के ग़म को हल्का करने के प्रयास में जुटी है तो राष्ट्रीय जनता दल एमवाई यानी मुस्लिम यादव के राजनीतिक समीकरण के बलबूते 15 वर्षों तक सत्ता का सुख भोगने तथा उसके एवज़ में मुसलमानों को विकास के मुख्य धारा से दूर रखने की मिली सजा को अब बहुत हो गया के रूप में देख रहा है. राज्य में तैयार चुनावी पृष्ठभूमि को पैनी नज़र से देखने वालों का मानना है कि राज्य का सत्ताधारी एनडीए तथा विरोधी दल मुस्लिम मतों को अपने अपने नज़रिए से अपने पक्ष में करने की जुगाड़ भिड़ाए हुए हैं. सत्ताधारी दल की कोशिश केवल इतनी है कि मुस्लिम मत वोट बैंक के रूप में न रह कर पूरी तरह बिखर जाए. मुस्लिम मतों के बिखराव में ही उसकी जीत का राज़ छिपा हुआ है. जबकि मुख्य विरोधी दल राजद–लोजपा गठबंधन इस कोशिश में है कि मुस्लिम मतों की बयार एक बार फिर इसके पक्ष में बह जाए. कांग्रेस यह मान बैठी है कि मुस्लिम मतदाता बड़ी तेज़ी के साथ उसकी ओर आ रहे हैं. अनुपातिक रूप से मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक संख्या में टिकट दिए जाने के निर्णय को मुसलमानों से कांग्रेस की बड़ी उम्मीद के नज़रिए से देखा जा रहा है. राजद–लोजपा एलायंस फूंक–फूंक कर क़दम बढ़ा रहा है. वह किसी भी क़ीमत पर मुस्लिम मतों की एकता में दरार के पक्ष में नहीं है. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन ठोक–बजाकर कर रहा है.

राजनीतिक दलों की चुनावी पैंतरेबाज़ी को राज्य का मुस्लिम मतदाता चुपचाप बड़ी बारीकी से देख रहा है. थोड़ा बहुत असमंजस भी है. निष्पक्ष मजहबी रहनुमाओं के बीच भी मतभेद की स्थिति है. लेकिन सभी इस पक्ष में हैं कि पक्ष–विपक्ष की राजनीतिक विचारधारा से उपर उठकर हर हाल में मुस्लिम मतों की एकता को मज़बूत करने का प्रयास होना चाहिए. यानी जो ग़लत है उसे पूरी तरह नकारा और जो अपेक्षाकृत सही हो उसे पूरी तरह स्वीकारा जाना चाहिए. दूसरी स्थिति में मुस्लिम मतों का कोई मोल नहीं रह जाएगा. लेकिन अल्पसंख्यकों के पक्ष में कौन सही है और कौन ग़लत, यह कोई तय नहीं कर पा रहा है.

इस सिलसिले में राज्य के कुछ उलेमा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धजीवियों से बातचीत की गई तो किसी हद तक मुस्लिम मतदाताओं का रुझान समक्ष में आया. इस क्रम में अपनी बातचीत के दौरान ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष तथा इमारत शरीया, बिहार के अमीर–ए–शरीअत हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन ने फरमाया कि कभी बिहार विधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 46 हुआ करती थी मगर आज यह संख्या घटकर 14 रह गई है. उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए राजनीतिक दल कम और स्वंय मुसलमान अधिक कसूरवार हैं. मुस्लिम मतदाता को अभी तक अपने मतों की क़ीमत मालूम नहीं हो सकी है. यदि ऐसा नहीं होता तो जात और पंथ से ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाते जो राष्ट्रहित, समाजहित को सर्वोपरि मानने के साथ–साथ अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो. अमीर–ए–शरीअत ने वर्तमान राज्य सरकार की ख़ामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पंचायत संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण ने सामाजिक समरसता को आघात पहुंचाया है. शराब की भट्ठियों और दुकानों की संख्या में बेतहाशा बृद्धि ने समाज में फैली बुराईयों में इज़ाफा किया है. इदारह–ए–शरिया, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के प्रमुख मौलाना गुलाम रसूल बलियावी नामी–गिरामी धर्मगुरू होने के साथ–साथ सत्तारूढ़ दल के पदधारक भी हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि मुसलमान अपने चुनावी मतों की ताक़त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. वह भी इस पक्ष में हैं कि राजनीतिक दलों को पुरस्कृत करने या दंडित करने के मामले में मुस्लिम मतदाताओं की एकता में दरार नहीं पड़नी चाहिए. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले खानकाह मुनअमिया, मीतन घाट, पटना सीटी के सज्जादानशीं सैयद शमीम अहमद मुनअमी का कहना है कि विधान मंडलों में मुसलमानों की लगातार घटती हुई तादाद अफ़सोसनाक है. जब तक मुस्लिम मतदाता बिखरे हुए रहेंगे तब तक संसद तथा विधान सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कमजोर रहेगा. फलस्वरूप उनके हितों की उपेक्षा होती रहेगी. ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डा. एजाज अली का मानना है कि मुसलमान किंग मेकर की स्थिति में रहते हुए इस देश में बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं. इस स्थिति का बुनियादी कारण स्वयं मुसलमान हैं और इसका निवारण भी इन्हीं के हाथों में है. उनका यह भी कहना है कि मुस्लिम हितों के प्रति कोई भी राजनीतिक दल ईमानदार नहीं है.

अबू कैशर

एजाज अली

मौलाना सैयद निजामुद्दीन

सैयद शमीम मुनअमी

राजनीतिक स्तर पर मुसलमानों को एकजुट करने के प्रयास में वर्षों से जुटे मुस्लिम यूनाईटेड फ्रंट के अध्यक्ष मो. अबु कैशर मुस्लिम मतों की छीना–झपटी करने की होड़ में संलिप्त राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के पक्ष में हैं. उनका भी यही कहना है कि ऐसा मुस्लिम मतों की एकजुटता से ही संभव है. अन्यथा मुस्लिम मतों की बदौलत सत्ता का सुख भोगने में महारत रखने वाले सियासी खिलाड़ी मुसलमानों को सब्ज़बाग़ दिखाते ही रहेंगे. कैसर साहब नें कहा कि राजनीतिक स्तर पर मुसलमानों की कमज़ोरी के कारण ही मुसलमान विकास के हाशिए पर मायूस खड़े हैं. समाजिक एवं राजनीतिक चेतना तथा नेतृत्व के अभाव के कारण ही मुसलमानों में बिखराव की स्थिति है. लेकिन यह संतोष की बात है कि इस स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है. असंगठित रूप से ही सही युवा वर्ग का रुझान राजनीतिक नेतृत्व की ओर हो रहा है. राष्ट्र सेवा तथा समाज सेवा की अपार संभावनाओं को क़रीब से देखने और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की समझ मुस्लिम युवा वर्ग में भी पैदा हो रही है और इसका स्पष्ट नतीजा भी हम देख रहे हैं. वो आने वाले दिनों से निराश नहीं हैं. प्रमुख चिंतक और समाजसेवी इंजीनियर हुसैन नें बिहार के मुसलमानों की दुर्दशा पर अफ़सोस जताते हुए कहा कि पौने दो करोड़ की मुस्लिम आबादी हर क्षेत्र में पिछड़ गई है. आज इस कौम का नेतृत्वकर्ता नहीं है. हम अलग–अलग ढफली बजा रहे हैं. हमारी भाषा हमारी संस्कृति पर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं. अब समय आ गया है कि मुसलमान अक्ल से काम लें और अपने मतों की क़ीमत समझें.

feedback@chauthiduniya.com

छपरा
दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

विजयेंद्र कुमार

संसदीय इतिहास में छपरा का काफ़ी महत्व रहा है. विगत लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुक़ाबले में रूढ़ी ने क़रीब 45 सौ वोटों से लालू प्रसाद से बढ़त बनाई थी. हालांकि वह इस चुनाव में लालू प्रसाद से हार गए थे. इस बार राजद ने यहां से स्थानीय जगदम कॉलेज के प्राचार्य प्रेमेंद्र रंजन सिंह को और राजग ने भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मैदान में उतारा है. यहां कांग्रेस की ओर से सारण ज़िला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह प्रत्याशी हैं. बसपा ने राज नारायण प्रसाद गुप्ता उर्फ़ मुन्ना जी को अपना उम्मीदवार बनाकर जनार्दन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. नए परिसीमन के तहत होने वाले प्रथम विधान सभा चुनाव में यादव वर्ग के किसी दलीय प्रत्याशी का न होना प्रेमेंद्र रंजन सिंह की स्थिति को मज़बूत कर रहा है.

अगर हाल के दिनों में इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करें तो यह क्षेत्र राजपूत बहुल माना जाता है. संख्या बल के हिसाब से दूसरे स्थान पर यादव व तीसरे स्थान पर अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों की बहुलता है. इस क्षेत्र में वैश्य समुदाय के वोटरों की संख्या क़रीब 20 हज़ार बताई जाती है. जो परंपरागत रूप से भाजपा के मतदाता के रूप में जाने जाते हैं. बसपा के उम्मीदवार के रूप में मुन्ना की दावेदारी से भाजपा प्रत्याशी के सामने मुश्किलें पैदा होने लगी हैं. लेकिन तय माना जा रहा है कि बड़ा मुक़ाबला राजद व राजग के बीच ही होने वाला है. जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मुक़ाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इस सीट पर लालू प्रसाद के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पैनी निग़ाह है. प्रभुनाथ सिंह के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी है, क्योंकि छपरा सीट पर उनके क़रीबी माने जाने वाले प्राचार्य प्रेमेंद्र रंजन चंदेल राजद प्रत्याशी हैं. इसके पूर्व यहां लालू प्रसाद के ख़ास रहे पूर्व मंत्री उदित राय का वर्षों तक क़ब्ज़ा रहा. राजग की ओर से भाजपा ने जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व खेलमंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चुनावी समर में उतारा है. कांग्रेस ने अनिल कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. बसपा ने वैश्य समुदाय से अपना प्रत्याशी खड़ाकर सिग्रीवाल के समक्ष मुश्किलें पैदा कर दी हैं. छपरा सीट पर यादव वर्ग से सामाजिक कार्यकर्ता झरीमन राय का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में कूदना तय है. 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 57 हज़ार 7 सौ 79 है. जिसमें पुरुष वर्ग के 1 लाख 19 हज़ार 4 सौ 82 एवं महिलाओं की संख्या 1 लाख 13 हज़ार 9 सौ 56 है. नए जातीय समीकरण के लिहाज़ से इस सीट पर राजपूत मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक हो गई है. इस विधान सभा क्षेत्र में राजपूत 60 हज़ार, यादव 40 हज़ार, मुस्लिम 28 हज़ार, वैश्य 26 हज़ार, भूमिहार 12 हज़ार, दलित 10 हज़ार के साथ शेष अन्य जाति के मतदाता हैं.

परिसीमन के बाद यहां सभी दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के चेहरे नए हैं. छपरा सदर प्रखण्ड की सात पंचायतों के साथ छपरा शहर के 44 वार्ड व रिविलगंज नगर पंचायत एवं प्रखण्ड को मिलाकर बनाए गए छपरा विधानसभा क्षेत्र में राजपूत वोटर निर्णायक स्थिति में हैं. वैसे यादव व मुस्लमान वोटर संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं. छपरा विधानसभा सीट पर किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा यादव वर्ग से कोई दलीय प्रत्याशी न बनाना एक ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा रहा है. इससे अलग सारण संसदीय क्षेत्र से विगत लोक सभा चुनाव में राजग प्रत्याशी के रूप में लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े भाजपा नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी की पैनी निग़ाहें भी इस सीट पर आ टिकी हैं. जदयू खेमे मे टिकट बंटवारे को लेकर आपसी गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है.

अनिल कुमार

प्रेमेंद्र राजन

जनार्दन सिंह

बताया जाता है कि तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के पूर्व जदयू के ज़िला स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका राजद में शामिल होने के लिए अपने हाथ–पैर मार रहा है. बहरहाल, यथास्थिति बरक़रार रही तो राजद के माय समीकरण के साथ राजपूत मतदाताओं का झुकाव भी राजद की स्थिति मज़बूत बनाने में कारगर साबित होगा. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह इस सीट को राजद के पाले में डालने के लिए राजपूत मतदाताओं को पटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. आसन्न चुनाव में विकास के मुद्दे गौण होने लगे हैं, जबकि जातीय समीकरण प्राय: सभी दलों में हावी हो रहे हैं. छपरा विधानसभा सीट पर राजग–राजद के साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान परवान चढ़ने लगा है. माना जाता है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुक़ाबले के आसार बन सकते हैं. अपने स्तर से मुक़ाबले में आने के लिए जी–जान लगाये मुख्य प्रत्याशियों को भीतरघात की स्थिति से जूझना पड़ सकता है, जो कि किसी की हार–जीत का कारण बनेगा.

feedback@chauthiduniya.com

प्यार प्रगति अनुशासन

प्रोग्रेसिव सेंट्रल हाई स्कूल

पटसा (हसनपुर), जिला–समस्तीपुर

फोन : 06275-282122, 282222

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त, कोड-330148

उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र गौरवपूर्ण शिक्षण संस्थान

नर्सरी से दशम वर्ग तक (अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम)

विशेषताएँ

- सह शिक्षा
- सुसज्जित–क्लास रूम
- आदर्श होस्टल
- समृद्ध पुस्तकालय
- वाहन सुविधा
- विज्ञान प्रयोगशाला
- अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा
- अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम
- प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्थायी शिक्षकों का समूह

चौथी दुनिया के स्थापना दिवस पर पाठकों को हार्दिक शुभकामनायें

निदेशक

राम किशोर राय

खगड़िया
जनता जवाब मांगने के लिए तैयार

राजेश सिन्हा

बाढ़, कटाव, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी समस्याओं से आजिज़ खगड़िया की जनता इस बार प्रत्याशियों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने से परहेज कर रही है. निवर्तमान विधायकों से पाई–पाई का हिसाब मांगने को जनता बेताब है. अन्य पार्टी प्रत्याशियों से उनकी बातों पर विश्वास करने का ठोस प्रमाण मांग रही है. किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ है कि जनता खुशी–खुशी निवर्तमान विधायकों के पक्ष में आंख मूंदकर मतदान करे. खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जदयू ने एक बार फिर निवर्तमान विधायक पूनम देवी यादव पर ही भरोसा जताया है, जबकि राजद–लोजपा गठबंधन के द्वारा भाजपा छोड़कर लोजपा में आई खगड़िया ज़िला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी को टिकट थमाया गया है. माकपा के डांगे सिंह चुनावी दंगल में हैं. निर्दलीय प्रत्याशियों की लंबी फौज़ देखने को मिल रही है. वर्षों से समाजसेवा करते आ रहे इ. धर्मेंद्र अन्य चुनाव की तरह इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आज़मा रहे हैं. लोजपा के बागी उम्मीदवार मो. शहाबुद्दीन, पूर्व विधायक रणवीर यादव के सगे भाई तथा खगड़िया की निवर्तमान विधायक पूनम के देवर संजय यादव भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग लड़ने को बेताब हैं. इस तरह की स्थिति के बीच अलग–अलग पार्टी के बागी फ़िज़ा बदलने में लगे हुए हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद दिनेश चंद्र यादव को उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने नीचा दिखाने का प्रयास किया था. खगड़िया की पूनम देवी यादव ने पिछले चुनाव में विकसित खगड़िया का भरोसा देकर मतदाताओं का विश्वास हासिल किया था. पूनम अपने वादे पर कितना खरा उतर पाईं, इसका जवाब मतदान के दिन जनता देगी. बेलदौर की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र से भी जदयू के द्वारा निवर्तमान विधायक पन्ना लाल पटेल को ही प्रत्याशी बनाया गया है. राजद–लोजपा गठबंधन के द्वारा पूर्व विधायक सुनीता शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि भाकपा से सत्यनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. दिवंगत सांसद रामशरण यादव के पुत्र पांडव यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार भाग्य आज़मा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित बेलदौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्ना लाल पटेल से जनता को कई आशाएं थी, लेकिन विकास के मामले में यह क्षेत्र भी फिसड्डी रहा. परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर तत्कालीन परिवहन मंत्री रामानंद सिंह तथा लोजपा–राजद गठबंधन से पूर्व कबीना मंत्री सम्राट चौधरी उर्फ़ राकेश कुमार चुनावी अखाड़े में कूदेंगे. परबत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले रामानंद सिंह भी जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके, ऐसा वहां की जनता का कहना है. मनोज कुमार सहित दर्जनों मतदाताओं का कहना है कि विधायक बनने के बाद रामानंद सिंह काले शीशे वाली गाड़ी में अपने गांव तक आते थे.

पांडव यादव, पन्ना लाल सिंह, पशुपति पारस, पूनम देवी, रामचंद्र सदा, सुशीला देवी

अलौली विधानसभा से लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के अनुज पशुपति कुमार पारस एक बार फिर भाग्य आज़मा रहे हैं. अलौली का प्रतिनिधित्व करने वाले पशुपति कुमार पारस ने विकास के मामले में अलौली को मॉडल बनाने का वादा तो किया ही था, बाढ़ और कटाव से निजात दिलाने का भी वादा किया था. लेकिन रामवृक्ष सदा का कहना है कि विकास की बात तो दूर पारस जी जीतने के बाद इलाक़े का भ्रमण तक करने नहीं आए. महज एक पुल के कारण कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग है. बहरहाल, जनता जवाब मांगने और हिसाब करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

feedback@chauthiduniya.com

बायसी क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए क्षेत्र की जनता जाति, धर्म–मजहब से उठकर भाजपा प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनायें

संतोष कुशवाहा

निवेदक

हाजी जफर, प्रमुख डगरूआ

मो. शमीम, समाजसेवी

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 18 अक्टूबर–24 अक्टूबर 2010

इस फ़ेहरिस्त में कई नेता तो दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय. कुछ ऐसे हैं जो नई पार्टियों से टिकट लेकर अपना भाग्य आज़माएंगे.

सांसद पुत्र

बाप बड़ा न पार्टी, टिकट दे वही साथी

बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही कैमूर की राजनीतिक धरती पर बग़ावत की जो पौध अचानक पनप गई, उससे राज्य के सत्ताधारी गठबंधन राजग एवं विरोध की राजनीत कर रहे विपक्षी दल राजद के राजनीतिक समीकरण तार तार होते दिखाई दे रहे हैं. भला ऐसा हो भी क्यों नहीं. एक तरफ़ ज़िले के प्रभावशाली पूर्व मंत्री एवं वर्तमान राजद सांसद जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा के टिकट पर रामगढ़ से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी तो दूसरी तरफ़ राजद छोड़कर जदयू के टिकट पर काराकाट लोकसभा से चुनाव जीते राज्य सरकार के पूर्व मंत्री महाबली सिंह के बेटे धर्मेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है. इन दोनों सांसद पुत्रों की बग़ावत ने कैमूर के राजनीतिक विश्लेषकों की सारी समीक्षा ध्वस्त कर डाली है. इन दोनों सांसद पुत्रों की बग़ावत ने कैमूर की राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नए समीकरण की तैयारी करना राजनीतिज्ञों की विवशता हो गई है. बग़ावत कैमूर की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है. समय समय पर यहां राजनीतिक परिवारों में विरोध के बिगुल बजते रहे हैं. पूर्व में समाजवादी धारा की राजनीति करने वाले राज्य सरकार के मंत्री स्व. सचितानंद सिंह के क्षेत्र रामगढ़ में जब राजनीतिक विरासत

सांसद पुत्रों की बग़ावत ने कैमूर के राजनीतिक विश्लेषकों की सारी समीक्षा ध्वस्त कर डाली है. इन दोनों सांसद पुत्रों की बग़ावत ने कैमूर की राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से हर सीट पर चुनाव लिए नए समीकरणों की तैयारी करना राजनीतिज्ञों की विवशता हो गई है.

जगदानंद सिंह ने संभाली थी तो बीच बीच में सचितानंद सिंह के पुत्र और रिश्ते में जगदानंद सिंह के भतीजे बिलू सिंह ने भी बग़ावत का बिगुल बजाया थी. अचानक सुधाकर सिंह का राजद छोड़ भाजपा में जाना एवं धर्मेंद्र कुशवाहा का जदयू छोड़ राजद में आना यहां आम मतदाताओं के लिए आश्चर्यजनक रहा है. जगदानंद सिंह रामगढ़ की नुक्कड़ सभाओं में पुत्र मोह की तिलांजली देते हुए अपने समर्थकों से जहां राजद की जीत के लिए एक बार फिर दुहाई दी है, पर महाबली सिंह की रहस्यमय ख़ामोशी चैनपुर में राजग गठबंधन के नेताओं के लिए परेशानी का कारण बना है. बताते चलें कि महाबली सिंह के सांसद चुने जाने के चैनपुर विधानसभा से भाजपा ने बृज किशोर बिन्द को मैदान में उतारा, इन्होंने राजद के बीरेंद्र सिंह को लगभग 2 हज़ार मतों से पराजित किया था. यह सीट राजद की झोली से भाजपा की झोली में चली गई थी, अब महाबली सिंह के पुत्र धर्मेंद्र की दावेदारी राजग में रहते मज़बूत नहीं दिखी तो राजद का दामन थाम अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने का प्रयास किया है. यह अलग बात है कि इस पहल में सांसद पिता महाबली सिह की सहमति थी या नहीं. इस पर दोनों पक्ष से कोई बयान नहीं आया है. रामगढ़ में कहानी थोड़ी अलग है. यहां राजद के विधायक रहते हुए जगदानंद सिंह बक्सर लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गए और उन्होंने रामगढ़ की विधायकी अपने बेटे को सौंपने के बजाए अंबिका यादव को आज़माने का प्रयास किया. शायद यही कारण है कि रामगढ़ की विरासत हाथ से निकलते देख सुधाकर सिंह को लगा कि परिवारिक विद्रोह भले ही सामने आए, लेकिन क्यों न भाजपा का दामन थाम विरासत पर क़ब्ज़ा जमाया जाए. उनकी मंशा पर फ़िलहाल तुषारपात होता दिख रहा है. राजद ने अभी यहां उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन पार्टी के लिए चौक–चौराहों एवं नुक्कड़ो पर जगदानंद सिंह राजद के पक्ष में अक्रामक तेवर के साथ प्रचार करने में जुटे हुए हैं. देखना यह है कि कैमूर के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर स्थित इन दोनों विधानसभा के चुनावी रणनीति का असर मध्य में स्थित सुरक्षित क्षेत्र मोहनिया एवं सामान्य क्षेत्र भभुआ पर कितना पड़ता है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

जमुई

करीना समेत कई नए चेहरे दौड़ में

इमरान खान

वैसे तो जमुई दिग्गजों की पृष्ठभूमि रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में नए चेहरे भी मैदान में उतरेंगे. यह वे लोग हैं जिन्हें अपनी विरासत में भी राजनीति मिली है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चुनावी महासमर में पहली बार दो–दो हाथ करेंगे. इस फ़ेहरिस्त में कई नेता तो दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय. कुछ ऐसे भी हैं जो नई पार्टियों से टिकट लेकर अपना भाग्य आज़माएंगे. बड़े–बड़े दिग्गज एवं उनके सगे–संबंधी अपनी–अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नज़र आ रहे हैं. नए लड़ाके भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं हैं. जमुई विधानसभा की बात करें तो जदयू के टिकट पर चुनाव अजय प्रताप लड़ रहे हैं. अजय पूर्व विधायक स्व. अभय सिंह के भाई एवं मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं. पहली बार चुनाव मैदान में उतरे अजय पूरे दमखम के साथ लोगों से समर्थन मांग रहे हैं. अजय का मानना है कि जमुई की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हर किसी के दिल में विकास का सपना है. प्रकाश भगत भी पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आज़माने जा रहे हैं. प्रकाश को लगता है कि सभी जाति व वर्ग के लोग दलगत भावना से परे सुंदर व विकसित जमुई के लिए उन्हें वोट देंगे. इसी तरह युवा नेता अनिल सिंह भी ख़ुद को कम नहीं आंक रहे हैं. उनका कहना है कि मैं भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं पर जमुई की चिंता मुझे हमेशा रही है. यहां के युवकों के लिए जो बन पड़ा मैंने किया. अनिल सिंह को उम्मीद हैं कि जमुई की जनता इस बार सही फ़ैसला करेगी. सागर साव भी जमुई विधानसभा में दो–दो हाथ करने को तैयार हैं. उनका दल छोटा भले है, लेकिन वह अन्य जातियों के वोट के भरोसे बाजी अपनी तरफ़ करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. चकाई विधानसभा क्षेत्र

सुमित सिंह

करीना पासवान

नेपाली सिंह

अनिल सिंह

अजय प्रताप सिंह

सागर साह

से मंत्री नरेंद्र सिंह के दूसरे पुत्र सुमित कुमार सिंह पहली बार जनता के सामने हैं. सुमित का दावा है कि विधायक बना तो चकाई का कायाकल्प कर दूंगा. उन्हें हर जाति व वर्ग का समर्थन मिल रहा है. चकाई से नेपाली सिंह भी पहली बार चुनावी अखाड़े में कूदे हैं. उनका कहना है कि जनता ही मालिक है और उसने मुझे चुन लिया है. वह कहते हैं कि मैं घर का बेटा हूं और घरवाले ही अपनों का दर्द समझते हैं. सिकंदरा विधानसभा से सुभाष पासवान पहली बार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. सुभाष का कहना है कि इस बार जनता ने तय कर लिया है कि नए चेहरे को विधानसभा भेंजेगे.

समस्त भारतीय पार्टी की करीना को दलित–महादलित व मुस्लिम वोट पर पूरा भरोसा है. उनका कहना है कि ग़रीबों की सेवा उनके लिए सर्वोपरि है. कहा जाए तो जमुई ज़िले में इस बार कई नए चेहरे अपनी किस्मत आज़माएंगे. इन्हें पूरा भरोसा है कि बाजी इनके ही हाथ लगेगी. इसलिए जनता का दिल जीतने के लिए वे अपनी पूरी ताक़त लगा रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कृपया ध्यान दें !

सभी एसबीआई ए.टी.एम. कार्ड धारक

एसबीआई एटीएम डेबिट कार्ड अपनायें!
नगद साथ रखने से मुक्ति पायें!!

भारतीय स्टेट बैंक
हर मोड़ पर आपके साथ

सिर्फ़ बैंकिंग. और कुछ नहीं.

क्या करें–क्या न करें–12 संदेश

क्या करें :

1. ए.टी.एम. कार्ड को निजी सुरक्षा में रखें। कार्ड प्राप्त होने पर उसके पीछे अपना हस्ताक्षर करें।
2. ए.टी.एम. पिन (गोपनीय संख्या) को याद रखें।
3. ए.टी.एम. से लेन–देन करते समय ए.टी.एम. कक्ष में अकेले रहें।
4. ए.टी.एम. कार्ड सही एवं सुरक्षित ढंग से प्रविष्ट करें।
5. ए.टी.एम. पिन मांगे जाने पर सही पिन डालें।
6. निकासी सीमा के अन्तर्गत ही रकम निकालने का अनुरोध करें।
7. ए.टी.एम. मशीन से रकम निकलने पर तुरन्त प्राप्त करें।
8. ए.टी.एम. कक्ष छोड़ने से पहले लेन–देन अवश्य पूर्ण कर लें।
9. ए.टी.एम. कार्ड के पिछली भाग पर की काली पट्टी को बचावें।
10. लेन–देन के पश्चात निकलने वाली पर्ची को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। पर्ची नहीं निकलने पर शाखा से तुरंत सम्पर्क करें।
11. ए.टी.एम. कार्ड खोने पर उसे शीघ्रता से HOT करायें। तुरंत टॉल फ्री नं. पर अथवा ATM कार्ड निर्गत शाखा को सूचना दें। विशेष जानकारी हेतु कार्ड के साथ भेजी गयी उपभोक्ता मैनुअल का उपयोग करें।
12. किसी भी परेशानी में टॉल फ्री नं. 1800112211 या 9955952211 पर सम्पर्क करें।

क्या न करें :

1. ए.टी.एम. कार्ड को मोड़े नहीं।
2. ए.टी.एम. कार्ड के पीछे की काली पट्टी को नुकसान न होने दें।
3. अपना ए.टी.एम. कार्ड किसी को न दें।
4. ए.टी.एम. कार्ड की गोपनीय संख्या (PIN) को लिख कर न रखें।
5. ए.टी.एम. कार्ड की गोपनीय संख्या (PIN) किसी को न बताएं।
6. ए.टी.एम. परिचालन के समय किसी अन्य व्यक्ति की सहायता न लें।
7. ए.टी.एम. कक्ष में किसी व्यक्ति के होने पर प्रवेश न करें।
8. ए.टी.एम. कार्ड प्रयोग करते समय गलत PIN का प्रयोग न करें।
9. निकासी सीमा से ज्यादा रकम निकासी हेतु अनुरोध न करें।
10. ए.टी.एम. द्वारा रकम निर्गत करने पर उसे लेने में थोड़ी भी देर न करें।
11. लेन–देन पश्चात् निकलने वाली पर्ची को लेना न भूलें।
12. ए.टी.एम. में नीचे दिखाए स्वागत संदेश आने के पहले ए.टी.एम. न छोड़ें।

* शर्तें लागू

अधिक से अधिक एटीएम का प्रयोग करें

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, गया

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा में पधारें या 1800112211 टॉल फ्री नम्बर या 9955952211 पर कॉल करें।
वेबसाईट : www.sbi.co.in ई–मेल : contactcentre@sbi.co.in

हर भारतीय का बैंक

Rajbari
Tea Lounge
THE TEA SUPERSTORE

India's leading chain of Tea Super Stores

Anything n Everything about TEA
All under one Super Store
◆ Tea Store ◆ Tea Accessories ◆ Tea Bar

Franchisee requirements
Space : 250-300 sq. ft. Investment : 4-5 Lacs
For information : www.rajbaritealounge.com
Call : 09430504070, 06456-225102 or
Email : rajbaritealounge@gmail.com

BHAGAT TOLI ROAD, KISHANGANJ (BIHAR)